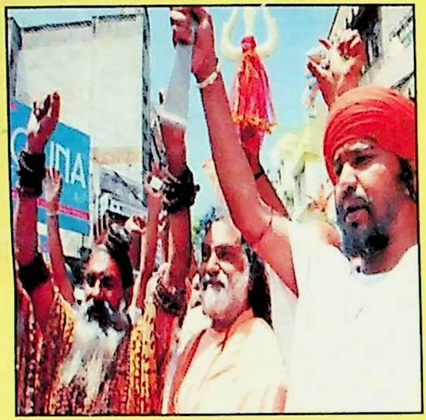
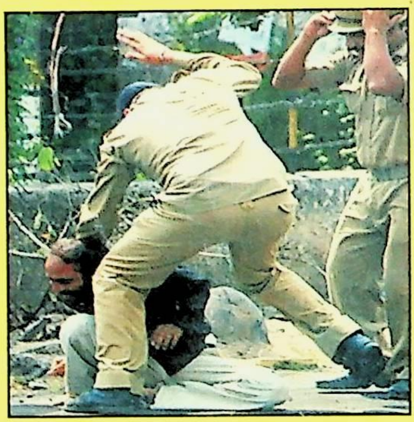
आस्था की विजय

धर्मसत्ता के आगे झुकी राजसत्ता









लेखक : नरेन्द्र सहगल

श्री अमरनाथ यात्रा संघर्ष समिति के
ऐतिहासिक आंदोलन की अमर गाथा

सुरुचि प्रकाशन, झण्डेवाला, नयी दिल्ली – 110055



रक्षाबंधन पर धर्मरक्षा प्रतिज्ञा

लाखों लोगों ने एक दूसरे की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध कर अंतिम श्वास तक इस धर्मयुद्ध में लड़ते रहने की प्रतिज्ञा की।

"मैं पाक परस्त अलगावादियों को पराजित कर श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड को जमीन वापस मिलने तक तन-मन-धन पूर्वक संघर्ष करने का संकल्प लेता/लेती हूं।"

संगठित हिन्दू – शक्तिशाली भारत

आस्था की विजय

लेखक

नरेन्द्र सहगल

सुरुचि प्रकाशन
केशवकुंज, झन्डेवाला, नयी दिल्ली–110055

आस्था की विजय

लेखक : नरेन्द्र सहगल

जारीकर्त्ता : श्री अमरनाथ यात्रा संघर्ष समिति, जम्मू

प्रकाशक
सुरुचि प्रकाशन
केशव कुंज, झण्डेवाला,
नयी दिल्ली – 110055
website : www.suruchiprakashan.com
e-mail : suruchiprakashan@vsnl.net

विक्रम संवत् 2065 (सन् 2008)

अक्षर संवर्धन : धर्मेन्द्र कौशल

मुद्रक : निशा एन्टरप्राइजेज, दिल्ली

ISBN : 81-89622-55-2

समर्पण

आस्था की विजय यह पुस्तक समर्पित है उन देशभक्त युवकों को, जिन्होंने अपने बलिदान देकर भारत विरोधी अलगाववादियों पर राष्ट्रीय शक्तियों की विजय का इतिहास रचते हुये, राजसत्ता को झुकाया

अभिनंदन

हिन्दू स्वाभिमान की रक्षार्थ इस
जनांदोलन में शामिल सभी राष्ट्रवादी
संगठनों और राष्ट्रभक्तों का
हार्दिक अभिनंदन

आस्था की विजय

पुस्तक : अनुक्रमणिका

जारीकर्त्ता : श्री अमरनाथ यात्रा संघर्ष समिति, जम्मू

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक

श्री कु. सी. सुदर्शन का वक्तव्य

श्री लीलाकरण जी शर्मा के संयोजकत्व में बनी श्री अमरनाथ यात्रा संघर्ष समिति ने पिछले दो महीनों से बालटाल और दोमेल में ज़मीन के लिए जो संघर्ष चलाया उसकी सफल परिणति के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उन्हें भूरि-भूरि बधाई देता है।

जम्मू-कश्मीर की सरकार ने विधानसभा में इस सम्बन्ध में जो कानून बनाया था, किन्तु अलगाववादी ताकतों के तुष्टिकरण के फेर में पड़कर उसे निरस्त करने की जो कार्यवाही माननीय राज्यपाल के द्वारा की गई थी, उसे वापस लेकर उपर्युक्त कानून के अन्तर्गत पुनः सारे अधिकार बहाल किये जाना समिति द्वारा दिखाए गए दृढ़ निश्चय, सातत्य, अडिगता और विवेकशीलता का ही सुपरिणाम है। यदि सरकार ने प्रारम्भ में ही अपने ही द्वारा पारित कानून पर दृढ़ रहने की हिम्मत दिखाई होती तो जम्मू-कश्मीर की जनता को इस दौरान जो कष्ट, आर्थिक हानि और दमन का सामना करना पड़ा, वह न करना पड़ता। कहावत है " देर आयद, दुरुस्त आयद " – देरी से ही क्यों न हो, सरकार ने जनभावनाओं की तीव्रता का अनुभव कर अपने कदम वापस लिये इसके लिए वह भी धन्यवाद के पात्र हैं।

आबाल-वृद्ध, स्त्री-पुरुषों के द्वारा पोषित इस जन आन्दोलन को साम्प्रदायिक कहकर बदनाम करने का प्रयत्न किया गया। किन्तु जम्मू सम्भाग ही नहीं, सारे भारत की जनता ने जाति-पांति-पंथ-भाषा तथा दलगत भेदों से ऊपर उठकर जिस एकता व आत्मीयता का प्रदर्शन किया, वह अभिनंदनीय ही नहीं अपितु अनुकरणीय भी है। जम्मू-सम्भाग सहित समूचे देश के इस्लाम परस्त एवं अन्य सब पंथावलम्बियों ने इस आन्दोलन का तहेदिल से समर्थन किया और यही इस आन्दोलन की सफलता का आधार भी बना। देश में सभी पूज्य आचार्यों, सन्तों, महर्षियों, एवं मुनियों के आशीर्वाद ने इस आन्दोलन के लिए ठोस सम्बल का काम किया। इस आन्दोलन में बलिदान हुए समस्त हुतात्माओं के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अप्रित करते हुए एक बार पुनः जम्मू-कश्मीर की जनता सहित समस्त देशप्रेमी जनता का अभिनंदन करता हूँ।

भारत माता की जय ।

विश्व हिन्दू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय प्रधान श्री अशोक सिंहल एवं महासचिव डा. प्रवीण तोगड़िया का बधाई संदेश

पूरे देश की हिन्दू जनता एवं विश्व हिन्दू परिषद के लाखों कार्यकर्त्ता, जम्मू की वीर भोग्या धरती पर पुनः एक बार जनरल जोरावर सिंह का शौर्य दिखाने के लिए जम्मू की जनता को इस ऐतिहासिक विजय के लिए बधाई देती है और हृदयपूर्वक अभिनंदन भी करती है।

गत 60 वर्षो से कश्मीर के अलगाववादी और देश विरोधी ताकतें नंगा नाच करके देश की जनता को ब्लैकमेल कर रही थी। जम्मू की जनता पर अन्याय कर रही थी और देश के स्वाभिमान पर भी आधात कर रही थी, उनको सबक नहीं सिखाने का दर्द दिल में बना रहता था। पैसे के लिए लड़ने वाले लोग बहुत होते हैं, सत्ता के लिए संघर्ष करने वाले लोग बहुत होते हैं परन्तु कश्मीर की प्रत्येक इंच जमीन यह देश की है इसलिए बाबा अमरनाथ यात्रा के लिए जमीन लेकर रहेंगे, यह ध ार्म की रक्षा का संघर्ष और संकल्प एक बार जनरल जोरावर सिंह, हरिसिंह नलवा, श्री गुरु गोविंद सिंह और महाराणा प्रताप और महाराणा गुलाब सिंह के संकल्प को जम्मू की जनता ने पुनः स्मरण करा दिया।

35 दिन तक व्यापारियों ने व्यापार बंद रखा, छात्रों ने शिक्षा बंद रखी, मजदूरों ने मजदूरी नहीं की, कर्मचारी काम पर नहीं गये। मानों जम्मू का छात्र, व्यापारी, मजदूर, महिला और बच्चा बाबा अमरनाथ के अपमान का बदला लेने के लिए धर्मयुद्ध कर रहा था। अनेक बंधुओं ने इस धर्मयुद्ध में अपना बलिदान भी दिया। उन सब की आत्मा एवं उनके परिवार के चरणों में पूरे देश का हिन्दू साष्टांग दण्डवत प्रणाम करता है।

आप सब बंधुओं ने श्रीअमरनाथ यात्रा संघर्ष समिति का नेतृत्व करके, किसी भी लालच व दबाव में न आकर दो महीने से ज्यादा समय तक जनता का अपार विश्वास संपादन किया, यह आपकी निष्ठा और ध ार्म के प्रति श्रद्धा का स्वयं प्रमाणपत्र है।

हिन्दुओं के स्वाभिमान के इस धर्मयुद्ध में लगे एवं कश्मीर भारत का हिस्सा है, यह सिद्ध करके इस राष्ट्रीय यज्ञ में संघर्ष करने वाले, बलिदान देने वाले, आर्थिक अभाव के बीच भी लड़ने वाले और सेनापति की भांति नेतृत्व करने वाले आप सभी बंधु, भगिनि एवं अमरनाथ संघर्ष समिति के पदाधिकारियों और जम्मू की जनता को बहुत–बहुत बधाई।

हस्ताक्षर

(अशोक सिंहल)
अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष

(डा. प्रवीण तोगड़िया)
अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री

अपनी बात

राष्ट्रवादी शक्तियों की विजय

हिन्दू अस्मिता और राष्ट्रीय स्वाभिमान की रक्षा के लिए श्री अमरनाथ यात्रा संघर्ष समिति द्वारा चलाये गये आंदोलन को मिली विजय हिन्दुत्व और राष्ट्रवादी शक्तियों की पाकिस्तान समर्थक देशद्रोही अलगाववादियों पर ऐतिहासिक विजय है। जम्मू के देशभक्त लोगों ने दो महीने तक निरंतर कष्ट सहकर जिस संगठित शक्ति का परिचय दिया है, इससे समस्त देश की राष्ट्रवादी शक्तियों को दिशा मिली है।

जम्मू के हिन्दुओं की संगठित शक्ति ने यह संदेश दिया है कि हिन्दुत्व ही एक ऐसा धरातल है जिस पर पूरा देश स्वाभिमान से खड़ा होकर भारत की अखण्डता, राष्ट्रीय संस्कृति, गौरवशाली इतिहास, धार्मिक स्थलों, मान बिन्दुओं और सामाजिक एकता के प्रतीकों की रक्षा कर सकता है। श्री अमरनाथ धाम पर आये संकट ने पूरे भारत विशेषतः हिन्दू समाज के स्वाभिमान को ललकारा था। श्री अमरनाथ यात्रा संघर्ष समिति की विजय केवल मात्र जम्मू क्षेत्र की विजय न होकर उन सभी राष्ट्रीय शक्तियों की विजय है जो पिछले 61 वर्षों से देशघातक, विदेश प्रेरित और आतंक आधारित संगठनों से लोहा ले रहीं हैं।

सर्वविदित है कि जम्मू–कश्मीर की कांग्रेस गठबंधन वाली सरकार ने मंत्रीमंडल के एक सर्वसम्मत निर्णय के आधार पर श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड को बालटाल कश्मीर में 100 एकड़ जमीन अस्थाई रूप से किराये पर मात्र दो महीने के लिए दी थी। प्रदेश सरकार ने यह जमीन प्रदेश की विधानसभा द्वारा बनाये गये श्राइन बोर्ड एक्ट के तहत गठित श्रीअमरनाथ श्राइन बोर्ड को जब दी थी तो उस समय कश्मीर केन्द्रित सभी राजनीतिक दल खामोश रहे। परन्तु हिन्दुत्व और भारत राष्ट्र के साथ जुड़ा हुआ यह सरकारी फैसला अराष्ट्रीय तत्वों को बर्दाश्त नहीं हुआ। पाकिस्तान समर्थक हुर्रियत कांफ्रेंस, सभी अलगाववादी और आतंकवादी संगठन, पीडीपी और नेशनल कांफ्रेंस ने हिन्दुओं से जमीन वापस लेने का शोर मचा दिया। कश्मीर में अलगाववादी तूफान आया। आजादी के नारे बुलंद हुये, पाकिस्तान के झण्डे फहराये गये और हिन्दुस्थान के झण्डे जलाये गये। भारतीय सेना, भारतीय सेवा अधिकारी तथा बाहर से मजदूरी करने आये गरीब लोग निशाना बनने लगे। इस अलगाववादी तूफान के आगे प्रदेश और केन्द्र सरकार ने घुटने टेके और

नवनियुक्त राज्यपाल एन.एन. वोहरा ने किसी कायदे–कानून का ध्यान न रखते हुये जमीन प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग को वापस कर दी। कश्मीर में जश्न मनाये गये।

इधर जम्मू के हिन्दू समाज समेत सभी देशभक्तों ने कश्मीर में उभरे देशद्रोह के खिलाफ आवाज उठाई। एक प्रबल जनांदोलन शुरू हुआ। केन्द्र सरकार के इशारे पर राज्यपाल महोदय ने संघर्ष को विफल करने के लिए अत्याचारों के सभी रिकार्ड तोड़ दिये। जम्मू के लोगों के उत्साह और संगठित शक्ति के आगे सरकार झुकी और श्रीअमरनाथ श्राइन बोर्ड को भूमि व सभी अधिकार वापस दिये गये। हिन्दु समाज का स्वाभिमान वापस लौटा। जम्मू के देशभक्त लोग शांत हुये। तो भी अत्यंत चिंताजनक और घटिया तरीके से सरकार ने कश्मीरी अलगाववादी संगठनों को खुश करने का एक प्रयास किया। जम्मू के लोगों को अपनी विजय के उपलक्ष्य में 31 अगस्त को रैली नहीं करने दी गई। पूरे जम्मू संभाग में फिर से कर्फ्यू लगाकर लोगों को घरों में कैद कर दिया गया। जबकि कश्मीर के लोगों को "नमाजे–शुकराना" अदा करने की न केवल अनुमति ही दी गई थी बल्कि सरकारी कर्मचारियों और सादे वेषधारी पुलिस कर्मियों ने इसकी व्यवस्था भी की थी। यह सरकार भले ही हिन्दू शक्ति के आगे झुकी है परन्तु इसके मानस में मुस्लिम तुष्टिकरण की भावना और वोट बैंक के लिए किसी भी हद तक गिर जाने की वृत्ति समाप्त नहीं हुई।

जम्मूवासियों ने अपनी संगठित शक्ति से समस्त देशवासियों को संदेश दिया है कि देशद्रोहियों, अलगाववादियों और आतंकियों को पराजित करने के लिए राजनीति से पूर्णतः अलिप्त जनशक्ति की अवश्यकता है। पिछले 61 वर्षों में यह पहला अवसर है जब कोई सरकार हिन्दुओं के किसी सवाल पर झुकी है। गौ रक्षा अभियान, हिन्दू कोड बिल, हिन्दू धर्म स्थल बचाओ आंदोलन, शाहबानो केस, श्री रामजन्मभूमि मुक्ति संघर्ष, तथा इसी प्रकार के हिन्दू अस्मिता की रक्षा के आंदोलन के आगे सरकार कभी नहीं झुकी। इतना जरूर है कि श्रीराम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के समय केन्द्र की सरकार ने मंदिर के शिलान्यास की अनुमति दे दी थी और श्रीराम सेतु रक्षा अभियान के संदर्भ में श्रीराम के अस्तित्व को नकारने वाली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपने ही हलफनामे को बदल लिया था। परन्तु हिन्दुओं के किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन को

सफल नहीं होने दिया गया। कांग्रेस सरकारों ने सदैव ही मुस्लिम तुष्टिकरण पर आधारित वोट बैंक की घटिया राजनीति को ही अपनाया। राष्ट्रहित को दरकिनार करते हुये कांग्रेस ने पिछले 61 वर्षों में राष्ट्रवादी शक्तियों को दबाने की कोशिश की। जम्मू के देशभक्त लोगों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करके मुस्लिम बहुल कश्मीर को ज्यादा अधिकार देना, कांग्रेसी सरकारों की मुस्लिम चाटुकारिता की परिचायक है। जम्मू के लोगों ने पहली बार कांग्रेस सरकार को न केवल झुकाया है बल्कि उसे हिन्दू स्वाभिमान और राष्ट्रीय संस्कृति का सम्मान करना भी सिखाया है।

यह ठीक है कि जम्मू के लोगों ने अपने बलिदान देकर देशद्रोहियों के इरादों को एक बार विफल कर दिया है, परन्तु कश्मीर के अलगाववादी तत्वों ने भारत की संप्रभुता, अखण्डता और एकता को जो चुनौती दी है, उसकी ओर से आंखे मूंद लेना भी ठीक नहीं। विजय के उल्लास में यह न भूल जायें कि अब समस्त देश के सामने आई इस चुनौती को भी इसी प्रकार से संगठित होकर स्वीकार करने की आवश्यकता है। हिन्दुओं के पक्ष में सरकारी फैसला होने के बाद कश्मीर में अलगाववादी तत्व हालात को और भी ज्यादा बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हुर्रियत कांफ्रेंस और पीडीपी के नेताओं ने तो जमीन के मामले को दरकिनार करके अब सीधे तौर पर आजादी की जंग का ऐलान कर दिया है। अब यह मसला पूरे देश का बन चुका है। भारत की सरकार को अब वोट बैंक की चुनावी राजनीति से उपर उठकर देश की अखण्डता को बचाने के लिए कठोर कदम उठाने चाहिए। जम्मू और समस्त भारत की देशभक्त जनता सरकार का साथ देगी।

हिन्दुत्व की रक्षा के लिए दो महीने तक निरंतर चले इस आंदोलन का वैचारिक आधार और संक्षिप्त इतिहास इस पुस्तक में दिया गया है। अनेक मित्रों ने पुस्तक को तैयार करने में निस्वार्थ भाव से सहायता की। मैं ऐसे निष्ठावान एवं स्नेहिल साथियों का धन्यवाद करता हूं। प्रस्तुत पुस्तक के संबंध में रचनात्मक आलोचना, सुझाव और आशीर्वाद आमंत्रित हैं। श्रद्धेय पाठकों के लिए अनेक शुभ कामनाएं

नरेन्द्र सहगल

श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड

हिमालय पर्वत की ऊंची सुरम्य पर्वत श्रृंखलाओं में एक 13500 फुट उंची बर्फानी चोटी पर स्थित श्रीअमरनाथ धाम की पवित्र गुफा में स्वयंनिर्मित बर्फानी शिवलिंग के दर्शनार्थ प्राचीन काल से ही हजारों की संख्या में हिन्दू यात्री जा रहे हैं। पहाड़ी रास्तों, दुर्गम नदी नालों और घने जंगलों को पार करते हुये श्रद्धालु यात्रियों को अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। परन्तु यह कठिनाईयां कभी भी हिन्दू समाज को अपनी श्रद्धा और आस्था से डिगा नहीं पाईं। अनेक प्रकार के प्राकृतिक प्रकोपों के बावजूद भी राष्ट्र की भावनात्मक एकता की प्रतीक श्रीअमरनाथ यात्रा निरंतर चलती रही।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् श्रीअमरनाथ यात्रा के प्रबंध की जिम्मेवारी जम्मू–कश्मीर की सरकार के पास आ गई। यात्रियों की निरंतर बढ़ती संख्या के कारण सरकारी पर्यटन विभाग सारी व्यवस्थाएं संभालने में अक्षम साबित होने लगा। 1996 में यात्रा के समय आये भयंकर बर्फानी तूफान ने प्रदेश सरकार और उसके पर्यटन विभाग की पोलपट्टी खोल दी। 300 से ज्यादा यात्री मारे गये और हजारों जख्मी हुये। सारे सरकारी बंदोबस्त विफल हो गये। देश भर में प्रदेश सरकार के खिलाफ आवाज उठी। विश्व हिन्दू परिषद समेत कई हिन्दू संगठनों ने यात्रा से संबंधित एक श्राइन बोर्ड बनाने की मांग उठाई। इससे पहले राज्यपाल जगमोहन ने माता वैष्णों देवी श्राइन बोर्ड का गठन करके भक्तों के लिए एक सुचारू व्यवस्था की स्थापना की थी। इसी तरह से श्री अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड की जरूरत देश भर में महसूस की गई। सरकार ने नितीश सेन कमेटी का गठन करके सुझाव मांगे। इस कमेटी के सुझावों को स्वीकार करते हुये जम्मू–कश्मीर की सरकार ने सन् 2000 में प्रदेश की विधानसभा में एक सर्वसम्मत प्रस्ताव द्वारा एक श्राइन बोर्ड एक्ट बनाया। इस एक्ट के तहत श्रीअमरनाथ श्राइन बोर्ड का गठन हुआ। प्रदेश के राज्यपाल की अध्यक्षता में काम करने वाले इस बोर्ड के 10 सदस्य निश्चित किये गये। यात्रा की सारी व्यवस्था तथा पवित्र गुफा में पूजा अर्चना के काम की जिम्मेदारी इस श्राइन बोर्ड के हाथ में सौंप दी गई। बोर्ड के सक्रिय होने से यात्रियों को ढेरों सुविधाएं मिलीं और श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ने लगी। पूरे भारत में जेके बैंक के माध्यम से यात्रियों का पंजीकरण, सार्वजनिक लंगर व्यवस्था, हैलीकाप्टर सेवा, प्रदूषण मुक्त शौचालय, वातावरण को शुद्ध रखने वाले अस्थाई

वैज्ञानिक उपकरण, चलते फिरते चिकित्सालय और विश्रामस्थल इत्यादि प्रबंधों के कारण सन् 2007 में यात्रियों की संख्या 5 लाख का आंकड़ा पार कर गई। राज्यपाल सेवानिवृत्त ले. जनरल एस.के. सिन्हा की अध्यक्षता वाले श्रीअमरनाथ श्राइन बोर्ड की यह ऐतिहासिक सफलता अमरनाथ धाम के इतिहास का एक स्वर्णिय अध्याय बन गया।

सन् 2002 में श्रीअमरनाथ श्राइन बोर्ड ने बालटाल (कश्मीर) में यात्रियों की सुविधा के लिए 800 कनाल जमीन सरकार से मांगी। तत्कालीन मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद और उनकी बेटी पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने तभी से ही न केवल इसका विरोध शुरू कर दिया बल्कि प्रदूषण, वन विभाग की मजबूरी, और जनसंख्या असंतुलन जैसी तरह–तरह की बेबुनियाद आशंकाएं उत्पन्न करके यात्रा का विरोध शुरू कर दिया। दरअसल पीडीपी नेताओं को हिन्दू यात्रियों की बढ़ती संख्या और हिन्दुओं के इस आस्था स्थल से ही नफरत है। जब राज्यपाल महोदय ने यात्रा की अवधि एक मास से दो मास तक की उस समय भी मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने इसका विरोध किया। वह कोर्ट में गये और पराजित हुए। सन् 2007 में बोर्ड ने फिर एक प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से बालटाल में अस्थाई रूप से जमीन मांगी ताकि यात्रियों के ठहरने और विश्राम करने के लिए अस्थाई ढांचों का निर्माण किया जा सके। मई 2008 में राज्य सरकार ने मंत्रीमण्डल में यह प्रस्ताव रखा जिसमें कांग्रेस, पीडीपी और पीपल्स डैमोक्रेटिक फ्रंट के मंत्री शामिल थे। पीडीपी के मंत्रियों ने ही यह जमीन श्राइन बोर्ड को देने का प्रस्ताव रखा। मंत्रीमण्डल ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और श्राइन बोर्ड को 800 कनाल जमीन बालटाल में दे दी गई। कुछ शर्ते इसके साथ जोड़ी गई।

1. श्राइन बोर्ड इस जमीन का इस्तेमाल अस्थाई रूप से केवल दो महीने के लिए ही करेगा। इन दो महीनों का किराया 2 करोड़ 31 लाख 30 हजार 400 रूपये निश्चित किया गया।
2. श्राइन बोर्ड को यात्रा समाप्ति के बाद यह जमीन वन विभाग को वापस सौंपनी होगी।
3. श्राइन बोर्ड इस भूमि पर किसी भी स्थाई ढांचे का निर्माण नहीं कर सकता।
4. श्राइन बोर्ड इस जमीन का इस्तेमाल यात्रियों की सुविधाओं के अतिरिक्त किसी और काम के लिए नहीं करेगा और न ही इस जमीन को किसी दूसरी संस्था को हस्तांतरित करेगा।

5. श्राइन बोर्ड इस जमीन पर से पेड़ों को काटने का मुआवजा भी 19 लाख 94 हजार प्रतिवर्ष वन विभाग को देगा।

श्राइन बोर्ड ने उपरोक्त सब शर्तों को स्वीकार कर लिया तथा सभी विभागों ने जिनमें पर्यावरण और वन विभाग भी शामिल हैं, No Objection Certificate जारी कर दिये। सरकार ने गर्वनमेंट Order No. 184 दिनांक 26–5–2008 को एक आदेश जारी किया जिसमें मंत्रीमंडल निर्णय 947 दिनांक 20–5–08 का उल्लेख करते हुये लिखा कि "सिंध फारेस्ट डिवीजन" की 39.88 हैक्टेयर जमीन श्रीअमरनाथ श्राइन बोर्ड को बालटाल और दोमेल में अस्थाई भवन और ढांचा बनाने के लिए दी जाती है। रांगा से बालटाल के लिए 9 हैक्टेयर तथा बालटाल में शिविर बनाने के लिए 30.88 हैक्टेयर जमीन दी गई। इसमें एक शब्द diversion का प्रयोग किया गया। कहीं भी सेल अथवा ट्रांसफर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया।

राष्ट्रीय एकता की प्रतीक अमरनाथ यात्रा

भारत के प्राचीन ग्रंथों और आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार श्री अमरनाथ धाम की यह पवित्र गुफा सम्पूर्ण सृष्टि के आद्य और आराध्य देव भगवान शिवशंकर का निवास है। इस पवित्र गुफा में प्राकृतिक रूप से बनने वाले बर्फ के शिवलिंग के रूप में स्वयं भगवान शंकर विराजमान होते हैं। अतः यह अमरनाथ धाम सृष्टि के आदिकाल से ही सम्पूर्ण मानव समाज का आस्थास्थल रहा है। जब मानव का अस्तित्व हिन्दू मुसलमान और ईसाई इत्यादि वर्गों में विभाजित नहीं था तभी से इस धाम का आध्यात्मिक महत्व चला आ रहा है। इसलिए यह अमरनाथ धाम भी जाति, पंथ और क्षेत्र की संकीर्ण दीवारों से दूर सम्पूर्ण जगत् से संबंधित है।

कश्मीर में अलगाववादी बवाल

इस तरह सरकार द्वारा श्राइन बोर्ड को जमीन सौंप दी गई। जमीन पर अस्थाई ढांचों का निर्माण भी शुरू हो गया। पूरे देश में इस नई व्यवस्था का स्वागत हुआ। हिन्दुओं के इस उत्साह और उन्हें कश्मीर में मिली धार्मिक सुविधाओं को हुर्रियत कांफ्रेंस जैसे अलगाववादी संगठन बर्दाश्त नहीं कर सके। हुर्रियत कांफ्रेंस के चेयरमैन मीरवायज उमर फारूख, तहरीके हुर्रियत के अध्यक्ष सईद अलीशाह गिलानी, डैमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी के शबीर शाह और जम्मू–कश्मीर लिबरेशन फंट के यासीन मलिक इत्यादि पाकिस्तान समर्थक नेताओं ने अमरनाथ यात्रियों की सुविधा के लिए दी जाने वाली जमीन का पुरजोर विरोध शुरू कर दिया। भारत तथा हिन्दू विरोधी नेताओं ने कश्मीर की जनता को भड़का कर सड़कों पर उतार दिया। भारत की सरकार और हिन्दू संगठनों के विरुद्ध अलगाववादी जहर उगला जाने लगा। कश्मीरियों के दिमाग में भरा जाने लगा कि अमरनाथ यात्रियों को जमीन देने के बहाने कश्मीर में हिन्दू कालोनी बनाई जा रही है। कश्मीर का जनसंख्या संतुलन बिगाड़ा जा रहा है। कश्मीरियों पर हिन्दू तहजीब थोपी जा रही है। भारतीय सरकार कश्मीरियों की संस्कृति को नष्ट कर रही है। इसके साथ ही पूरे कश्मीर में पाकिस्तान के झण्डे फहराने शुरू कर दिये गये।

भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे जलाये गये। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद हुये। "हम क्या चाहते हैं–आजादी", "यहां क्या चलेगा–निजामे मुस्तफा" (इस्लामिक राज), भारतीय कुत्तों वापस जाओ" इत्यादि भारत विरोधी शोर अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। मस्जिदों, ईदगाहों और बड़े–बड़े होटलों से लाउड स्पीकरों पर लोगों को जेहाद छेड़ने का आह्वान किया जाने लगा। भारतीय सरकारी कर्मचारियों, कारोबार कर रहे हिन्दुओं, बाहर के प्रांतों से कश्मीर में रोजी रोटी कमाने आये गरीब मजदूरों और पर्यटकों को कश्मीर छोड़ने की धमकियां दी गई। बाहरी मजदूरों को मारा–पीटा जाने लगा। उनके घर फूंके गये और उन्हें नंगा करके पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए मजबूर किया गया। पाकिस्तान और "स्वंतत्र कश्मीर राष्ट्र" के पक्ष में जलसे जलूसों का सिलसिला शुरू हो गया। सारे हालात 1989 जैसे बना दिया गये जब इन्हीं अलगाववादी नेताओं ने 3 लाख कश्मीरी हिन्दुओं को उनके घरों से भगा दिया था। देशद्रोह का यह माहौल पूरे कश्मीर में फैल गया और शुरू हो गया आजाद कश्मीर के लिए जंगे आजादी का जेहाद। सरकार खामोश रहकर तमाशा देखती रही।

वोट बैंक की राजनीति

जब सारा माहौल भारत और हिन्दू विरोधी बन गया और कश्मीर की जनता हुर्रियत कांफ्रेंस जैसे अलगाववादी संगठनों के पीछे खड़ी हो गई तो पीडीपी को अपना जनाधार खिसकता हुआ दिखाई दिया। अमरनाथ यात्रियों को जमीन देने के फैसले में शामिल पीडीपी के नेता पूर्व उपमुख्यमंत्री मुजफ्फर बेग और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती समेत पूरी पार्टी ने अलगाववादियों की हां में हां मिलाकर हिन्दू यात्रियों से जमीन वापस लेने की मांग कर डाली। पीडीपी नेताओं ने कश्मीरियत, आजादी, हिन्दू कालोनी बनने का खतरा, मुसलमानों की तहजीब पर हमला, कश्मीर पर भारतीय वर्चस्व और स्वतंत्र कश्मीर राष्ट्र का बवाल खड़ा कर दिया। पीडीपी को इस तरह कश्मीरियों में अपना जनाधार मजबूत करते देख नेशनल कांफ्रेंस घबरा गई। एन.सी. के संरक्षक डा. फारूख अब्दुल्ला और उनके पुत्र एनसी अध्यक्ष उमर फारूख ने भी पैंतरा बदला और अलगाववादियों की कतार में खड़े हो गये। कश्मीर में मुस्लिम वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए डा. अब्दुल्ला ने यह ऐलान भी कर दिया कि एनसी की हकूमत आने पर अमरनाथ श्राइन बोर्ड से जमीन वापस ले ली जायेगी। इसी तरह उमर अब्दुल्ला ने भी कश्मीरियत की तोता रटंत शुरू कर दी। हुर्रियत कांफ्रेंस, तहरीके हुर्रियत, जेकेएलएफ, डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी, पीडीपी, एनसी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस में बैठे कट्टरपंथी कश्मीरी मुस्लिम नेता श्राइन बोर्ड को दी जाने वाली जमीन को वापस लेने के मुद्दे पर एक मंच पर आ गये।

इन अलगाववादी संस्थाओं, पीडीपी, एनसी और आतंकवाद समर्थक नेताओं के भारत विरोधी बयानों पर नजर डालने से इनके असली चेहरे साफ दिखाई देते हैं। हुर्रियत कांफ्रेंस के चेयरमैन मीरवायज उमर फारूख ने शुक्रवार को हजरत बल में जुम्मे की नमाज़ के बाद कश्मीरी मुसलमानों को भड़काते हुये कहा कि यह सवाल केवल अमरनाथ श्राइन बोर्ड को दी गई 800 कनाल जमीन वापस लेने का ही नहीं हैं। असली मसला तो कश्मीरियों की पहचान, संस्कृति और कश्मीरी राष्ट्रीयता का है। हिन्दुस्थानियों और हिन्दुस्थान की फौज ने हमारी लाखों कनाल जमीन पर कब्जा कर रखा है। हमारे ऊपर बंदूक के जोर से दबदबा बनाये बैठी हिन्दुस्थानी फौज से हम निजात चाहते हैं। इसी तरह तहरीके हुर्रियत कांफ्रेंस के नेता सईद अलीशाह गिलानी भी बोले कि हमारा वर्तमान आंदोलन एक बड़े संघर्ष की शुरूआत है। हम तो कश्मीरियों को हिन्दुस्थान के शिकंजे से निकालना चाहते हैं। हिन्दुस्थान

ने कश्मीर को अपनी कालोनी बनाकर रखा हुआ है। इसी तरह पीडीपी के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मुजफ्फर बेग ने तो फिरकापरस्ती की सारी हदें पार करके बयान जारी कर दिया कि यह सवाल कश्मीर और कमीरियत का है। इसलिए पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अमरनाथ श्राइन बोर्ड पूरी तरह फिरकापरस्त है। पूर्व राज्यपाल और उसके मुख्य सचिव यहां आग लगाना चाहते थे – क्या हुआ अगर जम्मू वालों ने हमारी सप्लाई लाइन रोकने की धमकी दी है तो दूसरी सड़क तैयार है (श्रीनगर–मुजफ्फराबाद रोड) .... आई एम स्पीकिंग आन दा बीहाफ ऑफ माई नेशन (कश्मीर)। उधर महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने भी खुलेआम अलगाववादी संगठनो की हां में हां मिलाते हुये बयान जारी कर दिये कि यह सारा मसला कश्मीरी राष्ट्रीयता का है। अमरनाथ श्राइन बोर्ड को जमीन देने से हमारी राष्ट्रीय पहचान को खतरा हो जायेगा।

कश्मीर में उफान पर पहुंचे इस खुले भारत और हिन्दू विरोध को सख्ती से दबाने के बजाये जम्मू–कश्मीर की कांग्रेस नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने भी अपना वोट बैंक ध्यान में रखते हुये अलगाववादियो के आगे घुटने टेकने में ही गनीमत समझी। उधर पीडीपी के संरक्षक मुफ्ती मोहम्मद सईद ने सरकार से समर्थन वापस लेने की धमकी को अमली जामा पहनाते हुये सरकार को गिराने की घोषणा कर दी। मुख्यमंत्री गुलामनबी आजाद ने पहले तो सरकार बचाने के लिए जोड़तोड़ का प्रयास किया। अपनी कुर्सी बचाने में जब सफल नहीं रहे तो आजाद ने विधानसभा में बहुमत साबित करने से पहले ही अपनी सरकार का त्याग पत्र सौंप दिया। इस बीच राज्यपाल एस.के. सिन्हा सेवामुक्त हो गये और उनके स्थान पर एन.एन. वोहरा ने राज्यपाल का पदभार संभाला। यह वहीं एन.एन. वोहरा हैं जिन्होंने ग्रेटर मुस्लिम कश्मीर के पुरोधा अलगाववादी नेता वजाहत हबीबउल्लाह के भारत विरोधी मिशन कश्मीर का समर्थन किया था। श्रीनगर पहुंचते ही राज्यपाल महोदय ने मुख्यमंत्री आजाद को पत्र लिखकर पूछा कि क्या सरकार अमरनाथ यात्रा की व्यवस्था कर सकती है? इंतजार में बैठे मुख्यमंत्री ने तुरंत हामी भर दी। राज्यपाल ने बिना श्राइन बोर्ड की बैठक बुलाये अपने पत्र में लिख दिया था कि श्राइन बोर्ड अमरनाथ यात्रा की सुचारू व्यवस्था नहीं कर सकता। बोर्ड के पास पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं हैं। जबकि श्राइन बोर्ड द्वारा पिछले आठ वर्षो में की गई सर्वोत्तम व्यवस्था की सर्वत्र देश–विदेश में प्रशंसा हो रही थी।

सच्चाई तो यह है कि सोची समझी योजना के तहत केन्द्र से भेजे गए राज्यपाल महोदय ने यह पत्र मुख्यमंत्री गुलामनबी आजाद, पीडीपी नेता मुजफ्फर बेग और एनसी प्रधान उमर फारूख की सलाह पर लिखा था। उल्लेखनीय है कि 26 जून को राज्यपाल से मिलने के तुरंत बाद बेग और फारूख ने बयान जारी कर दिया था कि जमीन का मामला शीघ्र समाप्त हो जायेगा। राज्यपाल ने उनके सारे सुझाव मान लिये हैं। इसी प्रकार मुख्यमंत्री ने भी तुरंत बयान दाग दिया कि श्राइन बोर्ड के चेयरमैन राज्यपाल महोदय को बालटाल में जमीन की जरूरत नहीं है। सरकार यात्रा की व्यवस्था संभालने में सक्षम है। आजाद ने तुरंत मंत्रीमंडल में प्रस्ताव पारित कर जमीन व श्रीअमरनाथ श्राइन बोर्ड से सारी व्यवस्थाएं वापस लेकर पर्यटन विभाग को सौंप दी। इस समय पीडीपी के समर्थन वापस लेने से आजाद सरकार अल्पमत में आ चुकी थी।

असंवैधानिक फैसला

राज्यपाल एन.एन. वोहरा का यह कदम पूर्णतया असंवैधानिक था। जम्मू–कशमीर श्रीअमरनाथ श्राइन बोर्ड एक्ट की धारा 12 की उपधारा 3 के अनुसार बोर्ड का चेयरमैन अकेले कोई फैसला नही कर सकता। किसी भी फैसले के लिए बोर्ड की बैठक बुलानी जरूरी होती है और फैसले के वक्त बोर्ड के 10 सदस्यों में से 5 का उपस्थित होना जरूरी होता है। राज्यपाल महोदय ने अपना एक तरफा फैसला थोपते हुये यह भी ध्यान नहीं रखा कि श्रीअमरनाथ श्राइन बोर्ड को दी जाने वाली जमीन का मामला अभी भी हाईकोर्ट के विचाराधीन है। राज्य सरकार ने मई में श्राइन बोर्ड को जमीन देने का निर्णय हाईकोर्ट के एक अंतरिम आदेश के तहत ही किया था। राज्यपाल महोदय ने यह जानने की कोशिश भी नहीं की कि अमरनाथ श्राइन बोर्ड का गठन राज्य की विधानसभा द्वारा बनाये गये श्राइन बोर्ड एक्ट के तहत अस्तित्व में आया है। इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार भी विधान परिषद को ही है। श्राइन बोर्ड एक्ट की धारा 16 के अनुसार श्राइन बोर्ड द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु की जाने वाली व्यवस्थाओं को किसी और के हाथों नहीं सौंपा जा सकता।

राज्यपाल द्वारा अमरनाथ श्राइन बोर्ड से जमीन वापस लेकर प्रदेश सरकार को सौंपने और प्रदेश सरकार द्वारा यात्रा की सारी व्यवस्था को फिर से पर्यटन विभाग को सौंपने से कश्मीर के अलगाववादी संगठनों पीडीपी और एनसी इत्यादि ने जश्न मनाने शुरू कर दिये। अलगाववादियों द्वारा श्रीनगर में ''नमाजे शुकराना'' (अल्लाह का धन्यचाद)

सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में हिन्दुओं से जमीन वापस लेने के सरकारी फैसले को मुस्लिम कौम की जीत बताया गया और जंगे आजादी को पहले से भी ज्यादा तेज करने का ऐलान कर दिया गया। कश्मीर में भारत विरोधी बवाल खड़ा होने से लेकर नमाजे शुकराना का जश्न मनाने तक सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। भारत के विरुद्ध बगावत करने वाले नेताओं को तुष्टिकरण की नीति के तहत पाकिस्तान समर्थक माहौल बनाने की खुली छूट दे दी गई। इस प्रकार सरकार और देशद्रोही तत्वों ने मिलकर देश की समस्त राष्ट्रवादी ताकतों विशेषतया जम्मू के लोगों के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने जम्मू के लोगों को लड्डू खाने और बांटने की सलाह देकर जम्मू के लोगों के पुराने जख्म कुरेद दिये।

लाखों हिन्दुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़

कश्मीर घाटी के कट्टरपंथियों की नजर राज्य में हिन्दुओं के अन्य धार्मिक बोर्डों पर भी है। शुरू से ही यहां की सरकारें तथा केन्द्र सरकार अलगाववादियों को खुश करने के प्रयास करती आई हैं। कांग्रेस सरकार ने भी ऐसा ही कर लाखों हिन्दुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है

—एडवोकेट लीलाकरण शर्मा,
संयोजक संघर्ष समिति

श्री अमरनाथ यात्रा संघर्ष समिति का गठन

हिन्दुओं के आस्थास्थल श्रीअमरनाथ धाम और करोड़ो शिवभक्त यात्रियों के साथ किये गये सरकारी खिलवाड़ और हिन्दुत्व के अपमान के विरुद्ध सारे देश में प्रतिक्रिया हुई। जम्मू क्षेत्र के हिन्दुओं में भयानक रोष उत्पन्न हुआ। लोग सड़कों पर उतरकर अपने-अपने ढंग से विरोध प्रदर्शन करने लगे। वातावरण को गर्म होते देखकर विभिन्न हिन्दू संगठनों के नेताओं ने इस राष्ट्रवादी और हिन्दुत्वनिष्ठ वातावरण को आंदोलन का रूप देने के लिए बैठकें शुरू कीं। विश्व हिन्दू परिषद के आह्वान पर जम्मू संभाग के लगभग 40 हिन्दू संगठनों की एक आपात्तकालीन बैठक जम्मू के गीता भवन में हुई। इसी बैठक में सर्वसम्मति से श्रीअमरनाथ यात्रा संघर्ष समिति का गठन किया गया। इस बैठक में विश्व हिन्दू परिषद जम्मू-कश्मीर के प्रधान डा. रमाकांत दुबे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जम्मू विभाग संघचालक ब्रिगेडियर सुचेत सिंह, संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी के सदस्य एडवोकेट तिलक राज शर्मा और धर्म जागरण समन्वय विभाग जम्मू-कश्मीर के संयोजक श्री दिनेश खन्ना उपस्थित थे। संघर्ष समिति का गठन करते समय इस धर्मरक्षक आंदोलन की रूपरेखा पर खुलकर विचार विमर्श हुआ। जमीन वापसी तक संघर्ष करने का निर्णय लिया गया। इस बात पर बल दिया गया कि पूरे आंदोलन को राजनीति से दूर रखकर हिन्दू शक्ति को संगठित किया जाये। जम्मू हाईकोर्ट के सुप्रसिद्ध वकील श्री लीला करण शर्मा को सर्वसम्मति से संघर्ष समिति का संयोजक बनाया गया। पूर्व में हिन्दू रक्षा समिति के प्रधान के रूप में काम कर चुके श्री लीलाकरण एडवोकेट जम्मू के प्रतिष्ठित, जुझारू, निर्विवाद और राजनीति से पूर्णतया अलिप्त व्यक्ति हैं। 30 जून को जम्मू के गीता भवन में समिति की पहली बैठक में चार प्रस्ताव पारित किये गये :-

प्रस्ताव -1

राज्यपाल को वापस बुलाया जाये

जम्मू-कश्मीर के नवनियुक्त राज्यपाल एन.एन. वोहरा ने बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना परिस्थितियों का जायजा लिये और बिना जम्मू-कश्मीर के सभी राजनैतिक दलों से सलाह-मशविरा किये ही, आते

ही आनन–फानन में एक तरफा तानाशाही फैसला करते हुये श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड को मिली जमीन वापस लेने के लिए प्रदेश की सरकार को पत्र (हुकुम) लिख दिया। उधर प्रदेश के मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने भी तुरंत इस फैसले को आंख मूंद कर स्वीकार कर लिया और जमीन वापसी का ऐलान कर दिया। जाहिर है कि राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री दोनों ने ही किसी खास साजिश के तहत यूपीए की चेयरमैन सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह के इशारे पर अलगाववादी संगठनों और भारत विरोधी दलों के आगे घुटने टेके। सरकार के इस फैसले से देश–विदेश के करोड़ों हिन्दुओं की आस्था पर कुठाराघात लगा। हम भारत की सरकार और राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करते हैं कि इससे पहले कि हालात बेकाबू हो जायें, राज्यपाल वोहरा को वापस बुला लिया जाये अन्यथा जम्मू क्षेत्र के लोग राज्यपाल को कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम नहीं करने देंगे।

प्रस्ताव – 2

प्रदेश सरकार को बर्खास्त किया जाए

जम्मू–कश्मीर की सत्ता पर काबिज गठबंधन सरकार के सभी घटकों विशेषतया कांग्रेस और पीडीपी ने सर्वसम्मति से श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड को जमीन देने का फैसला किया और बाकायदा मंत्रिमंडल की मान्यता द्वारा सरकारी आदेश से जमीन सौंपी गई। परन्तु वोट की घटिया राजनीति ने कश्मीर केन्द्रित राजनैतिक दलों खासतौर पर पाकिस्तान परस्त अलवागवादी संगठनों को भारत और हिन्दू विरोध के मुद्दे पर एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। कश्मीर में भारत और हिन्दू विरोधी प्रदर्शन हुये, पाकिस्तान और इस्लाम के झण्डे फहराये गये और पीडीपी और नेशनल कांफ्रेस अपने पहले के फैसलों से मुकर गये। सारे कश्मीर में भारत और हिन्दू–विरोधी आग लगा दी गई। जम्मू–कश्मीर की कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने देश द्रोहियों के आगे घुटने टेक दिये। लिहाजा यह संघर्ष समिति राष्ट्रपति से निवेदन करती है कि दोगली नीति अख्तियार करने वाले मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व वाली सरकार को तुरंत बर्खास्त करके किसी राष्ट्रवादी राज्यपाल के नेतृत्व में राज्यपाल शासन लागू किया जाये। घाटी में भारत विरोधी बयान देने वाले नेताओं अलीशाह गिलानी, मीरवायज उमर फारूख, मुजफ्फर बेग, मुफ्ती महबूबा और उसके वालिद मुफती मोहम्मद सईद और उमर फारूख को गिरफ्तार कर उन पर देशद्रोह के मुकदमें चला कर जेलों में ठूंसा जाये।

प्रस्ताव – 3

श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड को जमीन वापस दी जाये

देश–विदेश के करोड़ों हिन्दुओं की आहत हुई भावनाओं और आस्था को पुनः बहाल करने के लिए श्राइन बोर्ड को जमीन वापस दी जाये। अमरनाथ यात्रा की व्यवस्था से संबंधित बोर्ड के सभी अधिकार लौटाए जायें। श्री अमरनाथ यात्रा समस्त देशवासियों विशेषतया हिन्दुओं का धार्मिक मामला है। उसमें किसी भी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप असंवैधानिक और नाकाबिले बर्दाश्त है। सरकारी दखल अंदाजी से अलगाववाद के और भी ज्यादा पनपने का रास्ता साफ होगा। परिणाम स्वरूप सारे देश का तथाकथित धर्मनिरपेक्ष माहौल बिगड़ेगा। यह संघर्ष समिति राष्ट्रपति महोदय से अपील करती है कि वह इस संवेदनशील मामले की गहराई तक उतरते हुये श्राइन बार्ड को जमीन लौटाने का आदेश राज्यपाल और मुख्यमंत्री को दें। अगर सरकार अमरनाथ श्राइन बोर्ड को जमीन नहीं लौटा सकती तो फिर बाबा गुलामशाह और पंपोर इस्लामिक विश्वविद्यालय, जम्मू–कश्मीर में बने हज हाउस और देश भर में मुस्लिम संगठनों को उनकी धार्मिक गतिविधियों के लिए दी गई जमीन और हज सब्सीडी भी वापिस ली जाये।

प्रस्ताव –4

पूरे देश के हिन्दू संगठन एक मंच पर आएं

श्रीअमरनाथ यात्रा का संबंध केवल जम्मूवासियों और कश्मीरी पंडितों से ही नहीं है। 13500 हजार फीट की ऊचाईं पर पवित्र अमरनाथ गुफा में पिछले 5 हजार वर्षों से चल रही पूजा, पिछले 350 वर्षों से चल रही छड़ी मुबारक और पिछले 148 वर्षों से चल रही अमरनाथ यात्रा पूरे देश और हिन्दू समाज की एकता और आस्था का प्रतीक है। यह संघर्ष समिति पूरे देश के सभी हिन्दू संगठनों, संत महात्माओं, जगद्गुरुओं, शंकराचार्यों, मठाधीशों और अखाड़ों के मंहतों का आह्वान करती है कि वह सभी अपने मठ मंदिरों, अखाड़ों और झोंपड़ियों से बाहर निकल कर इस संघर्ष का नेतृत्व करें और भारत के कोने–कोने में इस हिन्दू और भारत विरोधी फैसले के विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ें। अन्यथा पाकिस्तान परस्त तत्वों के हौंसले बुलंद होंगे और जम्मू–कश्मीर के साथ–साथ पूरे देश में अलगाववादियों के मंसूबे पूरे होंगे। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड पर की गई चोट ने देश की अखण्डता को चुनौती दी है। हिन्दुओं की आस्था पर प्रहार करने वाले देश द्रोहियो के आगे पूंछ हिलाने वाली प्रदेश और केन्द्र की कांग्रेसी सरकारों को चेताने के लिए इस समय हिन्दू एकता की जरूरत हैं। ■■■

श्रीअमरनाथ यात्रा संघर्ष समिति : कोर ग्रुप

	नाम	संगठन
1.	श्री लीलाकरण शर्मा एडवोकेट	– संयोजक
2.	ब्रिगेडियर सुचेत सिंह	– अ. भा. पूर्व सैनिक सेवा परिषद
3.	श्री तिलकराज शर्मा एडवोकेट	– राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
4.	श्री रमेश सब्रवाल	– राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
5.	डा. गौतम मैंगी	– राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
6.	डा. रमाकांत दुबे	– विहिप
7.	श्री सुरेन्द्र अग्रवाल	– विहिप
8.	श्री अशोक खजूरिया	– भाजपा
9.	प्रो. हरिओम	– भाजपा
10.	श्री रमेश पप्पा	– अ.भा.विद्य.ार्थी परिषद
11.	श्री नरेन्द्र सिंह	– अ. भा. विद्यार्थी परिषद
12.	श्री नारायण सिंह	– राजपूत सभा
13.	श्री राम सहाय	– चैंबर ऑफ कामर्स
14.	श्री यशपाल गुप्ता	– रिटेलर एसोसिएशन
15.	श्री हीरालाल भट्ट	– जम्मू–कश्मीर विचार मंच
16.	डा. आर.एल. भट्ट	– कश्मीर इन्टेक्चुयल फोरम
17.	डा. जितेन्द्र सिंह	– प्रोफेसर मेडीकल कालेज
18.	श्री वी.एस. सलाथिया	– बार एसोसिएशन
19.	श्री उदय चंद	– डुग्गर मंच
20.	श्री चन्द्रमोहन शर्मा	– प्रजा परिषद
21.	डा. वीरेन्द्र गुप्ता	– स्टेट मोर्चा प्रोग्रैसिव
22.	श्री देवराज बड़ू	– ब्राहम्मण सभा
23.	श्री विजय शर्मा	– ट्रांसपोर्ट यूनियन
24.	श्री कुलदीप सिंह	– ट्रांसपोर्ट यूनियन
25.	श्री आनन शर्मा	– क्रांति दल
26.	श्री राजेश गुप्ता	– युनाईटड हिन्दू शिव सेना
27.	श्री राजेश केसरी	– यूनाईटड हिन्दू शिव सेना
28.	श्री जगदीश लंगर	– उद्योगपति
29.	प्रो. भोला नाथ	– शिक्षाविद
30.	श्री श्याम चूढ़ामणि	– सनातन धर्म सभा
31.	श्री विरेन्द्रजीत सिंह	– नेशनल सिख फोरम
32.	श्री सुरेन्द्र सिंह	– गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी
33.	श्री पवन कोहली	– पूर्व एसडीएम
34.	श्री कमलेश परोच	– पूर्व जज

प्रचंड जन आंदोलन शुरू

समिति के आह्वान पर पूरा जम्मू क्षेत्र 10 दिन के लिए बंद रहा। सर्वत्र प्रदर्शन, जलसे और जुलूस सम्पन्न हुये। पुलिस द्वारा लाठी चार्ज, आंसू गैस तथा फायरिंग की गई। सैंकड़ों लोग घायल हुये। संघर्ष समिति के सैकड़ों कार्यकर्त्ताओं को गिरफ्तार कर जेलों में ठूंस दिया गया। पुलिस की बर्बरता ने इस धर्मयज्ञ में घी का काम किया। पूरा हिन्दू समाज जिसमें बुजुर्ग, जवान, बच्चे तथा महिलाओं ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया। तीन जुलाई को विश्व हिन्दू परिषद के आह्वान पर पूरा भारत इस आंदोलन के समर्थन में बंद रहा। राज्य सरकार ने जम्मू, साम्बा, कठुआ, आरएसपुरा, भद्रवाह, बड़ी ब्राहम्मणा इत्यादि स्थानों पर कर्फ्यू लगाकर देशभक्त जम्मूवासियों को खामोश करने की विफल कोशिश की। लोगों ने कर्फ्यू की धज्जियां उड़ाकर विशाल जलूस निकाले। पुलिस इतनी बर्बर थी कि जम्मू कि पीर मिट्ठा इलाके में एक आंदोलनकारी युवक रमेश कुमार का वहां के एसएचओ मोहम्मद शौकत ने तीसरी मंजिल तक पीछा किया। रमेश छत से गिर पड़ा और मस्तिष्क आघात से उसकी मौत हो गई।

भद्रवाह में शांतिपर्वूक प्रदर्शन कर रहे लोगों पर मुख्यमंत्री आजाद के भाई के पीएसओ ने बिना चेतावनी दिये फायरिंग शुरू कर दी। संघर्ष समिति के 7 कार्यकर्त्ता घायल हो गये। इसी वक्त प्रदर्शनकारियों पर शरारती तत्वों ने ग्रेनेड हमला कर दिया जिसमें 20 आंदोलनकारी गंभीर रूप से घायल हुये। घायलों में से एक 25 वर्षीय नौजवान मंजीत सिंह शहीद हो गया। पुलिस ने उसका शव परिवारजनों को न सौंपकर चोरी से उसके गांव में भेज दिया।

गुलामनबी आज़ाद की सरकार गई

7 जुलाई को राज्य सरकार ने इस्तीफा दे दिया और आंदोलन का एक मुकाम पूरा हुआ। 9 जुलाई को प्रातः 11 बजे संघर्ष समिति के नेतृत्व में विशाल धरना दिया गया। जिसमें विभिन्न हिन्दू संगठनों के पांच हजार से ज्यादा कार्यकर्त्ता उपस्थित थे। इसके बाद आंदोलन से संबंधित आगे की रूपरेखा तैयार करते हुये जम्मू संभाग के सभी जिलों में संघर्ष समितियां गठित करने का काम शुरू हो गया। 13 जुलाई को जम्मू में काला दिवस मनाया गया। दिन को लोगों ने अपने-अपने गली मौहल्लों में सरकार विरोधी प्रदर्शन किये। रात्रि को घरों की छतों पर थालियों की गड़गड़ाहट से, बहरी सरकार के कानों तक जम्मू की आवाज

पहुंचाने की कोशिश की गई। 14 जुलाई को राज्यपाल के पहली बार जम्मू पहुंचने पर उनका काले झण्डों से विरोध किया गया। 16 जुलाई को संघर्ष समिति के आह्वान पर पूरे जम्मू संभाग में चक्काजाम और हड़ताल की गई। जम्मू–कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर से लेकर रामबन, जम्मू से लेकर डोडा किश्तवाड़ और पुंछ–राजौरी इत्यादि के सभी दूरदराज के गांवों तक के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किये। इस व्यापक बंद में कहीं भी कोई हिंसक धटना नहीं हुई। सड़कें चौराहें वीरान रहे। यातायात पूर्णतः ठप्प रहा। प्रत्येक स्थान पर प्रदर्शनकारियों ने राज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री गुलामनबी आजाद समेत श्राइन बोर्ड विरोधी सभी राजनीतिक दलों के पुतले फूंके। पठानकोट से जम्मू और जम्मू से श्रीनगर मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह बंद रहा। हड़ताल करवाने, बंद रखने और प्रदर्शनों में भाग लेने के लिए लोग स्वतः अपने घरों से निकले।

गांव–गांव तक पहुंचा आंदोलन

जैसे जैसे पुलिसिया कहर बढ़ता गया वैसे वैसे आदोलन का विस्तार होता चला गया। भारत माता की जय, जय श्री अमरनाथ, बम–बम भोले, जय शिवशंकर इत्यादि उद्घोषों ने पूरे क्षेत्र को अपनी लपेट में ले लिया। जगह जगह पर भारत माता के बड़े–बड़े चित्रों के साथ प्रदर्शन हुये। नवयुवकों और बच्चों ने त्रिशूलधारी शिवजी का रूप धारण कर झांकियां निकालीं। सड़कों, चौराहों और गांवों की चौपालों पर एकत्र होकर प्रदर्शनकारियों ने तिरंगे झण्डे फहराये और शिव आराधना तथा रामधुन गाकर कीर्तन किये। प्रदर्शनकारियों ने जम्मू क्षेत्र के सभी विधायकों के घरों पर धरने देकर उन्हें संघर्ष समिति का साथ देने को कहा।

इस आंदोलन की खास बात यह है कि मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध इत्यादि सभी मजहबों के लोगों के साथ गुज्जरों–बकरवालों ने भी इसमें हिस्सा लिया। मुसलमान गुज्जरों की संख्या जम्मू–कश्मीर में 11 प्रतिशत है। इस तरह यह आंदोलन प्रदेश की जनता का लोकप्रिय सत्याग्रह बन गया।

श्री अमरनाथ यात्रा संघर्ष समिति ने जम्मूवासियों समेत देशवासियों से पुरजोर अपील की कि हिन्दुओं की अस्मिता को बचाने के लिए शुरू हुये इस अहिंसक आंदोलन को जारी रखें। यह आंदोलन केवल मात्र जम्मू के लोगों तक सीमित न होकर समस्त देशवासियों खासतौर पर हिन्दुओं से संबंधित है। संघर्ष समिति ने देश की सभी धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं और राष्ट्रवादी राजनीतिक दलों का आह्वान किया कि इस आंदोलन को देशव्यापी बनायें। भारत के कोने–कोने में संघर्ष समितियां बनाकर हिन्दू आस्था पर हुये अलगाववादी आक्रमण के विरुद्ध लड़ी जा रही जंग में शामिल हो जायें।



'भारत माता की जय' और 'बम–बम भोले'
इन महामंत्रों ने राष्ट्रभक्त शक्तियों को संगठित किया



संघर्ष समिति के संयोजक श्री लीलाकरण शर्मा
और उनके साथियों पर लाठियां बरसाती हुई पुलिस

कुलदीप डोगरा का अनुपम बलिदान

जम्मू की एक बस्ती तालाब तिल्लो के रहने वाले 38 वर्षीय कुलदीप डोगरा ने अपना बलिदान देकर अमरनाथ यात्रा संघर्ष समिति के नेतृत्व में हो रहे आंदोलन को जनांदोलन में बदलने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की। संघर्ष समिति के कार्यक्रम अनुसार जम्मू के सभी जिला केन्द्रों पर 20 जुलाई से 23 जुलाई तक क्रमिक धरनों और भूख हड़तालों के कार्यक्रम चल रहे थे। 23 जुलाई को जम्मू की परेड ग्राउंड़ में भी एक विशाल धरना दिया गया। इस धरने में कुलदीप डोगरा भी शामिल था। कुलदीप ने खड़े होकर पहले स्वरचित कविता सुनाई –''जागो तुमको हिन्दू की जागीर की रक्षा करनी है''। इस कविता को सुनाने के बाद संक्षिप्त भाषण दिया – ''भोले बाबा की जमीन वापस लेने के लिए आंदोलन को गांव–गांव तक पहुंचाना जरूरी है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी जवान को अपना बलिदान देना होगा। मैं अपना बलिदान देकर देश की राष्ट्रवादी शक्तियों को एकजुट होकर आंदोलन में भाग लेने का आह्वान करता हूं।'' इतना कहते ही कुलदीप डोगरा गिर पड़ा। यह वीर देशभक्त भाषण देने से पहले जहर की पुड़िया निगल कर आया था। अस्पताल में डाक्टरों द्वारा कुलदीप को मृत घोषित कर दिया गया।

अब सामने आया प्रशासन और पुलिस का घटिया और चरित्र से गिरा हुआ चेहरा। अस्पताल में कुलदीप के शव को अपने कब्जे में लेने की पुलिस ने हर तरह से कोशिश की परन्तु अस्पताल में पहुंचे साहसिक हिन्दू युवकों ने बड़ी हिम्मत और चतुराई के साथ पुलिस के इरादों को विफल करते हुये कुलदीप के शव को फिर से परेड ग्राउंड में बने धरना मंच पर लाकर रख दिया। इस सारी प्रक्रिया में पुलिस ने संघर्ष समिति के नेता सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर सुचेतसिंह और उनके साथियों पर लाठियां बरसाई। यह समाचार आग की तरह शहर में फैला और हजारों लोग शहीद के शव के पास एकत्रित हो गये। शहीद की पत्नी शिल्पी, उसके दो बच्चे और अन्य परिवार जन भी शव के पास आकर बैठ गये। लोगों ने शहीद के शव को फूल मालाओं से लाद दिया। चार घण्टे तक लोग बम–बम भोले, बम–बम भोले, कुलदीप डोगरा अमर रहे के नारों के साथ भगवान शिव शंकर के भजन कीर्तन करते रहे। संघर्ष समिति के नेताओं ने सूर्य उदय के बाद शहीद का पूरे सम्मान के साथ संस्कार करने का निर्णय किया।

तभी अचानक रात्रि 2.30 बजे हजारों पुलिस कर्मियों ने पूरे मैदान को घेर लिया। कुछ पुलिस जवानों ने आगे बढ़कर जबरदस्ती

धक्का-मुक्की करके कुलदीप के शव को उठाने की कोशिश की। वहां उपस्थित लोगों ने इसका विरोध किया तो पुलिस के भारी हजूम ने उन्हें, शहीद की पत्नी, बच्चों और परिवारजनों को पीटना शुरू कर दिया। कुलदीप की पत्नी शिल्पी ने जब अपने पति के शव को अपनी बाहों में लेना चाहा तो उसे बालों से खींच कर जमीन पर पटक दिया गया। पुलिस ने शहीद के शव को एक वाहन में डाला और निकटवर्ती बिश्नाह कस्बे की ओर चल दिये। पुलिस की इस तानाशाही कार्रवाई पर शक करते हुये सैकड़ों लोग अपने-अपने साधनों से बिश्नाह पहुंचने लगे। इनके साथ शहीद की पत्नी और दोनों बच्चें भी गये।

टायर एवं शराब से शव जलाने की कोशिश

बिश्नाह के श्मशान घाट में पहुंचने पर वहां के पुजारी महंत ने पुलिस का जमकर विरोध किया और कहा कि किसी भी हिन्दू का रात के समय में संस्कार नहीं हो सकता। परन्तु पुलिस बल के आगे महंत की एक नहीं चली। महंत को धक्के देकर किनारे कर दिया गया। पुलिस ने जल्दबाजी में इधर-उधर से लकड़ियां इकट्ठी करके एक चिता बनाई। इस चिता पर कुलदीप के शव को पटक दिया। शव पर रबड़ के टायर रखे, शराब उड़ेली गई और मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी गई। शहीद की पत्नी शिल्पी रोती-चिल्लाती अपने पति के शव के साथ लिपट गई। उसने पुलिसवालों से याचना की कि इस तरह से उसके पति का अपमान मत करो। मेरे हिन्दू पति का संस्कार सूर्य उदय के बाद हिन्दू रीति रिवाजों से होना चाहिए। उसने एक बार अपने पति का मुंह दिखाने की विनती भी की। पास में खड़े एक पुलिसवाले ने यह कहकर उसको धक्का दिया कि सारी रात इसका मुंह देखकर अभी थकी नहीं।

अभी कुलदीप की चिता सुलगनी शुरू हुई ही थी कि जम्मू और बिश्नाह के हजारों लोग श्मशान घाट पर इकट्ठे हो गये। इनकी भारी संख्या और आक्रोश को देखकर पुलिस हक्की-बक्की रह गई। लोग दीवार फांदकर चिता के पास पहुंचे। पुलिस वाले भाग खड़े हुये। लोगों ने अधजले शव को निकाला और बिश्नाह शहर में ले गये। शव को एक मंदिर में सुरक्षित रखा और सूर्य उदय के बाद शहीद के संस्कार की तैयारियों मे जुट गये। प्रशासन ने शहर में कर्फ्यू लगा दिया और चारों ओर सैनिक किलेबंदी कर दी। यह खबर भी निकटवर्ती गांवों में चिंगारी की तरह फैल गई। हजारों लोग कर्फ्यू तोड़कर अश्रूगैस और लाठियों की मार झेलते हुये बिश्नाह के श्मशान घाट तक पहुंचने लगे। संघर्ष समिति ने दोपहर बाद 2 बजे संस्कार का समय तय किया। तब तक जम्मू से

लेकर कठुआ तक के 50 हजार से ज्यादा लोग श्मशान घाट के साथ सटे मैदान में पहुंच गए। लोगों की इतनी बड़ी भीड़ को देखकर पुलिस ने चुपचाप रहने में ही गनीमत समझी। संघर्ष समिति के संयोजक श्री लीला करण शर्मा और संघर्ष समिति के कोर ग्रुप के संयोजक श्री रमेश पप्पा के पहुंचने पर पुजारी महंत ने हिन्दू रीति रिवाजों के अनुसार शहीद के अंतिम संस्कार की विधिवत रस्में प्रारंभ कीं। शहीद कुलदीप को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में लपेट कर बम-बम भोले के नारों के साथ चिता पर रखा और शहीद के 8 वर्षीय बेटे ने मुखाग्नि दी। संस्कार के बाद लोग जय शिव शंकर का उद्घोष करते हुये शांतिपूर्वक अपने घरों को लौट गये।

जम्मू पहुंचने पर शहीद की पत्नी शिल्पी ने एक प्रैस वार्ता में कहा कि यदि कसूरवार पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार करके उन्हें सजा नहीं दी गई तो वह भी उसी जगह पर अपनी कुर्बानी दे देगी जहां उसके पति कुलदीप शहीद हुये हैं।

श्रद्धांजलि सभा पर प्रतिबंध

प्रदेश मे राज्यपाल शासन और पुलिस के जुल्मों की हद तो उस समय देखने को मिली जब शहीद कुलदीप डोगरा को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित सभा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जम्मू शहर और आसपास के इलाकों में पहले धारा 144 लगाई गई और बाद में इस पूरे क्षेत्र में कर्फ्यू लगाकर लोगों को घरों में बद रहने को मजबूर कर दिया गया। जम्मू क्षेत्र के लोग पहले भी 12 दिन तक कर्फ्यू की मार झेल चुके थे। सरकार की इस तानाशाही के खिलाफ जम्मू के लोग, विशेषतया युवक कर्फ्यू को तोड़कर सड़कों पर उतर आए। पुलिस अधिकारियों ने भी राष्ट्रभक्ति के इस आवेग को दबाने के लिए बल प्रयोग के सभी साधन जुटाए। जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का साथ देने के लिए दिल्ली से रैपिड एक्शन फोर्स की आधी दर्जन बटालियनें जम्मू में तैनात कर दी गई। जम्मू शहर की प्रत्येक गली और मोहल्ले में महिलाएं, बच्चे, बूढ़े भारी तादाद में निकलकर रैली स्थान परेड ग्राउंड की ओर बढ़ने लगे। इन आंदोलनकारियों को पुलिस ने गलियों, सड़कों और चौराहों पर रोकने की कोशिश की।

प्रदर्शनकारियों के बढ़ते दबाव को देखकर पुलिस ने बिना चेतावनी दिये ही अश्रुगैस के गोले छोड़े और बाद में लाठियां बरसा कर भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश की। यह सिलसिला दिनभर चलता रहा। जम्मू की बाहरी सीमा पर करीब दो दर्जन स्थानों पर लोगों को रोका गया। जम्मू क्षेत्र के साम्बा, कठुआ, उधमपुर, राजौरी, पुंछ,

डोडा इत्यादि क्षेत्रों में भी पुलिस ने जबरदस्ती की और कहीं भी शहीद की याद में श्रद्धांजलि कार्यक्रम नहीं होने दिया। पुलिस की इस बर्बरता में 500 से ज्यादा लोग जख्मी हुये। लगभग 300 लोग गिरफ्तार किये गये। इस अमानवीय दर्दनाक कहानी का अंत यहीं नहीं हुआ। अश्रूगैस, लाठीचार्ज और गोलियों से जख्मी हुये लोगों को पुलिस ने अस्पताल न पहुंचाकर ट्रकों में डालकर पुलिस थानों में पहुंचा दिया। कइयों को जख्मी हालत में ही जेल भेज दिया गया। लोग दवाईयों के लिये चिल्लाते रहे। पुलिस वाले इसे अपनी विजय समझकर हंसते रहे और गालियां देते रहे। बाद में दबाव बढ़ने पर लोगों को छोड़ा गया। निजी हस्पतालों में डाक्टरों ने अपने स्तर पर जख्मी हुये लोगों का इलाज शुरू किया।

पूर्व नियोजित अत्याचार

शांत लोगों पर किया गया यह अत्याचार पूर्व नियोजित था। 27 जुलाई को सुबह 11 बजे शहीद कुलदीप डोगरा की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा जम्मू के प्रसिद्ध परेड मैदान में होने वाली थी परन्तु प्रशासन द्वारा धारा 144 लगने के बाद श्रद्धांजलि सभा का आयोजन स्थानीय ब्राहम्मण सभा में करने का फैसला किया। शहर में कर्फ्यू के बावजूद छिपते--छिपाते करीब 600 लोग श्रद्धांजलि स्थल पर पहुंच गये। संघर्ष समिति के संयोजक श्री लीलाकरण शर्मा भी अपना भेष बदल कर वहां पहुंचे। बिश्नाह से शहीद के अस्थि कलश को लेकर लगभग 50 युवक इस श्रद्धांजलि सभा के लिए रवाना हुये। यह लोग खेत खलियानों के रास्तों से करीब 20 किमी. पैदल चलकर जम्मू की तबी नदी के किनारे तक पहुंच गये। इन्हें तवी का पुल पार करने की इजाजत नहीं दी गई। अस्थिकलश अपने हाथों में लिये यह युवक तिरंगे झण्डे के साथ तवी नदी में उतरे और कमर और गंले तक पानी को पार करते हुये तबी के दूसरे किनारे पर पहुंचे। वहां से किसी प्रकार जम्मू की घनी आबादी वाले जुलाका मोहल्ले से होते हुये पुलिस की आंखों में धूल झोंककर श्रद्धांजलि स्थान पर पहुंच गये। इस तरह सम्पन्न हुई शहीद की अस्थिकलश यात्रा और श्रद्धांजलि सभा।

■■■

पुलिस और कर्फ्यू आर्डर, दोनों ने जम्मू क्षेत्र के लोगों की हिन्दुत्व और भारतभक्ति को समाप्त करने की पुरजोर कोशिश की। गर्व से कहा जा सकता है कि जम्मू क्षेत्र के लोगों की एकता पर कोई आंच नहीं आई और न ही आंदोलन कमजोर पड़ा।

हिन्दुत्व के लिए पी गए शहादत का जाम

हिन्दू आस्था और राष्ट्रीय एकता की प्रतीक श्री अमरनाथ यात्रा और शिवभक्त यात्रियों के स्वाभिमान की रक्षा के लिए जिन देशभक्तों ने अपना जीवन पुष्प चढ़ाया है उन्हें समस्त देशवासी कभी नहीं भूल सकते। जब–जब भी इस सफल जनांदोलन की चर्चा होगी, इन शहीदों को लोग याद करेंगे। इनके अतुलनीय बलिदान से आने वाली पीढ़ियां सदैव प्रेरणा लेती रहेंगीं। इन शहीदों की कुर्बानियों के बिना जनांदोलन का संक्षिप्त इतिहास अधूरा रहेगा।

शहीद मंजीत सिंह

इस राष्ट्रवादी आंदोलन में सबसे पहले शहीद हुआ भ्रदवाह निवासी मंजीत सिंह। 2 जुलाई को संघर्ष समिति द्वारा भद्रवाह में एक विशाल जनसभा की गई और बाद में जुलूस निकाला गया। हिन्दुओं की भारी भीड़ को प्रशासन और बहुसंख्यक समाज के लोग सहन नहीं कर सके। उपद्रवियों ने एक हैंड ग्रेनेड जुलूस पर फेंका। इस धमाके में 36 लोग घायल हो गयें। मंजीतसिंह भी घायलों में शामिल था। 6 जुलाई को अस्पताल में जाकर उसने दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने बहुत ही बेरहमी से उसके शव को उठाया और इंतजार कर रहे परिजनों को न सौंप कर सीधे ही उसके गांव ले जाकर ग्रामवासियों को सौंप दिया। स्थानीय निवासियों ने शहीद का संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया।

शहीद रमेश कुमार

7 जुलाई को जम्मू के एक इलाके पीर मिट्ठा का रहने वाला रमेश कुमार जरूरी घरेलू समान लेने के लिए निकटवर्ती लखदाता बाजार में गया। पुलिस ने इसे रुकने को कहा। रमेश जब वापस घर की ओर लौटने लगा तो पुलिस ने उस पर लाठियां बरसानी शुरू कर दीं। पुलिस से बचने के लिए रमेश ने भागना शुरू किया। पुलिसकर्मी भी उसके पीछे भागे। रमेश अपने घर में घुसकर चौथी मंजिल पर चढ़ गया। एक पुलिस

अफसर ने उसका पीछा चौथी मंजिल तक किया। रमेश ने बचने के लिए जब घर के सामने वाली छत पर छलांग लगाई तो वह गली में गिर गया। सिर पर चोट लगने से रमेश की मौत हो गई।

शहीद कुलदीप डोगरा

बाबा अमरनाथ की भूमि वापस लेने के लिए शहीद हुए कुलदीप डोगरा राष्ट्रवादी कवि थे। 23 जुलाई को जम्मू की परेड ग्राउंड में भूख हड़ताल पर सैंकड़ों लोग बैठे थे। कुलदीप ने देशभक्ति की एक कविता सुनाई और जमीन पर गिर पड़े। कुलदीप की जेब से एक पत्र निकला जिसमें उन्होंने शिव भोले के लिए अपनी कुर्बानी देने की बात लिखी थी।

शहीद कुलदीप डोगरा के 8 वर्षीय बेटे अनमोल ने अपने पिता के संस्कार के बाद पत्रकारों से कहा कि "अपने पिता की कुर्बानी बेकार नहीं जाने दूंगा। उनके अधूरे सपनों को जरूर पूरा करूंगा।"

शहीद संजीवसिंह

4 अगस्त को साम्बा शहर में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर वहां के एसएसपी ने अपने हाथों से फायरिंग की। इस फायरिंग में 24 वर्षीय संजीवसिंह मारा गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि एसएसपी ने प्रदर्शनकारियों को कोई चेतावनी नहीं दी। अलबत्ता एसएसपी ने कुछ प्रदर्शनकारियों को इशारा करके अपनी तरफ बुलाया और निकट आने पर अपने एक साथी की राईफल से गोलियां चला दीं।

शहीद संजीवसिंह के पिता कैप्टेन चंचलसिंह ने अपनी प्रतिक्रिया इन शब्दों में व्यक्त की "मेरा जवान बेटा शहीद हुआ है परन्तु मैंने एक आंसू नहीं बहाया। मेरे बेटे ने अपने हक के लिए संघर्ष में शहादत पायी है। इसका मुझे गर्व है।"

शहीद सन्नी पाधा

4 अगस्त को ही प्रदर्शनकारियों पर हुई फायरिंग में स्थानीय एसएसपी के हाथों ही एक विद्यार्थी सन्नी पाधा शहीद हो गया। अपने मां-बाप का इकलौता बेटा स्नातकोत्तर कक्षा का छात्र था।

सन्नी पाधा के पिता हेमराज ने भी अपने बेटे की शहादत को इस प्रकार याद किया – "मेरा एक ही बेटा था जिसने शहादत का जाम

पिया है। मेरी एक ही तमन्ना है कि जिस जमीन के लिए मेरे बेटे ने बलिदान दिया है वह जमीन श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड को मिलनी चाहिए।

शहीद नरेन्द्र शर्मा

कठुआ निवासी नेरन्द्र शर्मा ने भी अपना बलिदान देकर आंदोलन को गति देने में मुख्य भूमिका निभाई। कठुआ शहर के चड़वाल इलाके में स्पेयरपार्ट की दुकान चलाने वाले नरेन्द्र शर्मा ने 6 अगस्त को हुये प्रदर्शन में एक युवा टोली का नेतृत्व किया। यह टोली कश्मीर में जा रहे ट्रकों को हाईवे पर रोक रही थी। हजारों लोग इस मार्ग पर धरने पर बैठे हुये थे। पुलिस ने बिना सूचना दिये पहले लाठीचार्ज किया और जब भीड़ नहीं हटी तो सेना ने प्रदर्शनकारियों के नेता नरेन्द्र शर्मा को निशाना बनाकर गोलियां चला दीं। नरेन्द्र शर्मा मौके पर ही शहीद हो गया।

शहीद नरेन्द्र शर्मा के पिता श्री जगदीश शर्मा कहते हैं – ''मेरा एक बेटा ही शहीद हुआ है, अभी चार बाकी हैं और उसके बाद मैं भी तो हूं। जमीन वापसी तक संघर्ष करते हुये कुर्बानियां देंगे।''

शहीद डा. बलवंत खजूरिया

70 वर्षीय सेवानिवृत आयुर्वेदाचार्य डा. बलवंत खजूरिया हीरानगर के एक सम्भ्रांत परिवार से संबंध रखते थे। वे कई दिनों तक हीरानगर में आंदोलनकारियों का मार्गदर्शन करते रहे। एक दिन अचानक उन्होंने धरने के दौरान एक आंदोलनकारी से पानी का गिलास मांगा और इसी पानी के साथ जहर की पुडिया निगल ली। वह जहर की पुड़िया अपने घर से ही लेकर आये थे। इससे पूर्व उन्होंने संघर्ष समिति को एक हजार रुपये अपनी ओर से दिये थे। डा. खजूरिया ने अपने अंतिम पत्र में लिखा था कि इस भारत और जम्मू विरोधी सरकार को चेताने और लोगों को अंतिम लक्ष्य तक संघर्ष चलाये रखने की प्रेरणा देने के लिए मैं अपनी कुर्बानी दे रहा हूं।''

शहीद बोधराज

18 अगस्त को कोटली माखी निवासी बोधराज निकटवर्ती कस्बे आर.एस. पुरा में होने वाले प्रदर्शन में भाग लेने के लिए अपने गांव से

मोटरसाईकिल पर आ रहे थे। मोटरसाईकिल पर तिरंगा झण्डा फहरा रहा था। पुलिस ने देखते ही रोकने की कोशिश की। बोधराज ने मोटरसाईकिल की गति तेज कर दी। एक पुलिस अफसर ने अपनी मोटरसाईकिल पर बोधराज का पीछा करके उसके मोटरसाईकिल को गिरा दिया। बोधराज मोटरसाईकिल समेत सिर के बल गिरा और उसकी मौत हो गई। बोधराज एक साधारण किसान था।

शहीद दीपक शर्मा

18,19, 20 अगस्त को संघर्ष समिति के आह्वान पर जेल भरो आंदोलन दूरदराज के गांवों तक पहुंच गया था। जम्मू के निकट बिश्नाह कस्बे में 20 अगस्त को हुये सत्याग्रह में शामिल होने के लिए रियाल गांव के निवासी दीपक शर्मा और उनके साथी अपने ट्रैक्टर पर तिरंगा लगाकर नारे लगाते हुये जा रहे थे। इनका ट्रैक्टर जब एक मोड़ पर पहुंचा तो पुलिसकर्मियों ने रुकने का इशारा किया। तेज गति से चल रहे ट्रैक्टर की जब जोर से ब्रेक लगाई गई तो ट्रैक्टर ट्राली उलट गई। दीपक शर्मा और उसके साथी गंभीर रूप से घायल हुये। अस्पताल में जाकर दीपक शर्मा की मौत हो गई।

उपरोक्त सभी शहीदों के शवों का जम्मू–कश्मीर की पुलिस ने भरपूर अपमान किया। परन्तु जनता ने इन्हें ''अमर शहीद'' का सम्मान देकर हिन्दू धार्मिक विधिविधान से इनका संस्कार किया। इनके शवों को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे मे लपेट कर हजारों नर नारियों की उपस्थिति में चिताओं पर रखा। इनकी श्रद्धांजलि सभाओं में लाखों लोग उपस्थित रहे। इन शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष मेले लगते रहेंगे। जम्मू की राष्ट्रवादी जनता इन शहीदों के बलिदानों को बेकार नहीं जाने देगी और इनसे प्रेरणा लेकर अपने अधिकारों के लिए जूझती रहेगी। शहीदों की स्मृति में समस्त हिन्दू समाज का प्रणाम।

युवकों के बेकाबू जज़्बात

सरकार द्वारा कश्मीर के अलगाववादियों के आगे बार बार समर्पण करने की एकतरफा देशघातक रणनीति ने भी अनेक युवकों के दिलों में लगी देशभक्ति की आग में घी डालने का काम किया। सत्याग्रह के दौरान लाठियां, गोलियां खाने के बावजूद भी कुछ लोग अपने पर नियंत्रण नहीं रख सके और उन्होंने संघर्ष को और ज्यादा तेज करने के

लिए स्वयं अपनी कुर्बानियां देने जैसे कठोर कदम उठाने शुरू किये। हालांकि जहर खाकर बलिदान देना गौरवास्पद नहीं कहा जा सकता तो भी इन युवकों की भावनाएं सम्मान के योग्य हैं।

25 जुलाई :– जानीपुर निवासी मुनीष सिंह ने जहर खाकर जनांदोलन के समर्थन में अपनी जान देने की कोशिश की।

29 जुलाई :– जम्मू के निकट साम्बा के कमलदीप सिंह ने अपना बलिदान देने के उद्देश्य से जहर खा लिया और लोगों को भी बलिदान देने के लिए कहा।

10 अगस्त :– आर.एस. पुरा के रहने वाले अनिल कुमार ने जहरीला पदार्थ खाकर आंदोलन की सफलता के लिए आत्म बलिदान करने का प्रयास किया।

11 अगस्त :– कानाचक्क निवासी जीवनसिंह ने पहले सत्याग्रह में भाग लिया और फिर घर आकर जहर की पुड़िया निगल ली।

14 अगस्त :– कस्बे के एक प्रतिष्ठित आयुर्वेदिक डाक्टर 70 वर्षीय बलवंत खजूरिया ने बाबा अमरनाथ की जमीन के लिए जहर खाकर आत्म बलिदान कर दिया।

19 अगस्त :– लंगरेयाली गांव के जितेन्द्र मेहरा ने भी आंदोलनकारियों को प्रेरणा देने के नाम पर जहर खाकर आत्म बलिदान देने का प्रयास किया।

20 अगस्त : :– झज्जर में रहने वाले बंटी सिंह ने जहर खाकर अपनी कुर्बानी देने की कोशिश की।

उपरोक्त सब लोगों ने जहर खाने से पहले अपनी जेबों में स्वयं लिखित पत्र लिखे। जिनमें प्रायः यही लिखा होता था कि सरकार हमेशा हिन्दुओं के अधिकारों का हनन करती है। हम हिन्दुओं को ललकारने के लिए अपना जीवन दान देना चाहते हैं।

देशभक्ति का अनूठा जनून

अलगाववादी नेताओं की गधों पर सवारी

जैसे–जैसे आंदोलन का विस्तार होता चला गया लोग तरह–तरह के ढंग निकालते गये। बच्चों ने राम, कृष्ण और शिव के रूप धारण किये। महिलाओं ने साक्षात दुर्गा का रूप रचा। लोगों ने अपने–अपने मतानुसार हवन कीर्तन, अखण्ड पाठ जारी रखे। स्थान–स्थान पर लोगों ने महबूबा मुफ्ती, उमर फारूख और अलगाववादी नेताओं के मुखोटे पहने और गधों पर सवार होकर जुलूस निकाले। इनके गलों में तख्तियां लटकी होती थीं जिन पर लिखा होता था – "हम पाकिस्तानी हैं भारत हमारा देश नहीं है, हम कश्मीर में हिन्दुओं को जमीन नहीं देंगे।" गधों पर सवार इन नेताओं के पीछे लोगों का भारी हजूम जूते और चप्पलों से इनकी पिटाई करता हुआ साथ चलता था। यह सिलसिला पूरे जम्मू संभाग में चला। कई स्थानों पर लोगों ने इन भारत विरोधी नेताओं के पुतले बनाकर इन्हें फांसी पर भी लटकाया।

युवाओं ने सिर मुंडवाये

जम्मू संभाग के कठुआ, साम्बा, बिश्नाह इत्यादि स्थानों पर सैंकड़ों युवकों ने अपने सिर मुंडवा दिये। इन युवकों ने अपने ढंग से अलगाववाद विरोधी नारे लगाते हुये प्रदर्शन किये। सिर मुंडवाए हुये युवक जब प्रदर्शन करते हुये शहरों और कस्बों के चौराहों पर निकलते थे तो इनके पीछे हजारों की संख्या में बच्चे भी निकल कर नारे लगाते हुये इनका साथ देते थे। इन्हें देखने के लिए लोग घरों और बाजारों की छतों पर चढ़ जाते थे और वह भी बाबा अमरनाथ की जमीन वापस लेने के नारे लगाते थे।

चांद में भी दिखाई दिये शिव शंकर!

बम–बम भोले का उद्घोष इस आंदोलन का मूल मंत्र बन गया। बाबा अमरनाथ की भक्ति में रमकर जमीन वापसी के लिए संघर्ष कर रहे जम्मू के लोगों को जगह–जगह भोले शंकर के ही दर्शन होने लगे। बम–बम भोले के नारों में मस्त संघर्षरत बच्चों, महिलाओं और वृद्धों को शिवशंकर का मानों रंग चढ़ गया। "जिधर देखता हूं–तू ही तू है" वाली कहावत जम्मूवासियों के जहन में उतर चुकी थी। एक रात जब लोग सोने की तैयारियां कर रहे थे, लोगों को घरों में फोन आने शुरू हो गये

कि चांद में त्रिशूलधारी शिव शंकर जी दिखाई दे रहे हैं। जंगल की आग की तरह यह खबर पूरे जम्मू क्षेत्र में फैल गई। जिसे भी सूचना मिली वह घर की छत पर चढ़ गया और चांद में भोले शंकर के दर्शन करने लगा। खड़ीका तालाब निवासी पंडित अशोक शर्मा ने दावा किया कि उन्होंने चांद में भोले बाबा के दर्शन किये हैं। जम्मू के विभिन्न क्षेत्रों से लोगों ने अपने रिश्तेदारों को फोन पर कहा कि तुरंत चांद में त्रिशूलधारी शिवशंकर के दर्शन करो और आंदोलन की सफलता के लिए आशीर्वाद मांगो। पूरे जम्मू संभाग में लोग छतों पर चढ़कर चंद्रमा में प्रकट हुये शिव भोले से आशीर्वाद मांगने लगे।

लोगों का कहना था कि स्वयं बाबा अमरनाथ ने लोगों को दर्शन देकर अंतिम जीत तक संघर्षरत रहने का आदेश दिया है। देखते ही देखते यह सिलसिला पूरे जम्मू क्षेत्र में फैल गया। देर रात से शुरू हुआ यह सिलसिला प्रातः सूर्य उदय तक चलता रहा। सारी रात लोग चांद में शिव भगवान के दर्शन करके जमीन वापसी के उद्घोष करते रहे। लोगों ने जोर जोर से हर हर महादेव और बम-बम भोले के नारे लगाये। कई स्थानों पर महिलाओं ने छतों पर एकत्र होकर शिवभक्ति के गीत गाये। इस अद्भुत घटना ने लोगों को इतना उत्साहित किया कि उन्हें विश्वास हो गया कि भगवान शंकर ने दर्शन देकर उन्हें आशीर्वाद दे दिया है। अब हम अपने आंदोलन में अवश्य सफल होंगे।

राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा बना एकता का प्रतीक

निरंतर दो महीने तक चले इस हिन्दुत्व रक्षक आंदोलन में चारों ओर तिरंगे ही तिरंगे दिखाई देते थे। जम्मू क्षेत्र का कोई गली कूचा ऐसा नहीं बचा जिसके घरों की छतों पर तिरंगा झण्डा न लहराया गया हो। तिरंगा झण्डा राष्ट्रवादी जम्मू निवासियो के लिए स्वाभिमान का प्रतीक बन गया। पुराने बुजुर्ग बता रहे थे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले देशभक्ति के ऐसे ही माहौल में लोग तिरंगा झण्डा हाथों में लेकर सत्याग्रह करते जेलों में जाते थे। शहरों में कर्फ्यू लगने और संघर्ष समिति द्वारा पूर्ण बंद के आदेश के कारण सभी कारोबार बंद थे। परन्तु लोगों ने अपने घरों में ही तिरंगे झण्डे बनाना शुरू कर दिये। दर्जी का कारोबार करने वाले अनेकों लोगों ने अपनी जेब से पैसा खर्च करके हजारों तिरंगे झण्डे बनाकर समाज में वितरित किये। लाखों की संख्या में आंदोलनरत जम्मू संभाग के लोगों ने दो महीने में 1 करोड़ से ज्यादा तिरंगे झण्डों का इस्तेमाल किया। इससे पहले 15 अगस्त अथवा 26 जनवरी पर ही तिरंगे झण्डों का प्रचलन था।

लोगों ने बनाई वेबसाईट "जम्मू मैटर्स"

संघर्षरत लोगों ने अपनी आवाज को देश और विदेश में पहुंचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। जम्मू के कुछ युवाओं ने इस कार्य के लिए एक बेबसाईट बना डाली –"जम्मू मैटर्स" नामक इस बेबसाईट से पूरे विश्व में इस आंदोलन की रूपरेखा और उद्देश्य पहुंचने लगे। करीब दो दर्जन से ज्यादा आर्टीकल इस बेबसाईट पर लाये गये। जम्मूवासी यह महसूस कर रहे थे कि उनकी देशभक्त आवाज कश्मीर की भारत विरोधी आवाज के नीचे दब रही है। जम्मू की आवाज को बुलंद करने के लिए इस बेबसाईट ने अपना एक विशेष रोल अदा किया है। हिन्दू समाज के विभिन्न तबकों ने इस पहल का स्वागत किया। इसी तरह जम्मूवासियों ने ब्लाग और आरकुट पर भी अपने संघर्ष को विस्तार देने में सफलता हासिल की। अनेक युवा लोग नैट पर ब्लाग बनाकर संघर्ष का प्रचार करने में जुट गये। इस प्रकार ब्लागों की तादाद बढ़ती गई।

गूगल, रैडिफ और याहू आदि पर मिलने वाली ब्लाग की सुविधा का इस्तेमाल लोगों ने श्री अमरनाथ संघर्ष समिति द्वारा छेड़े गये आंदोलन में समर्थन जुटाने के लिए किया। ऐसे ही एक ब्लाग में रमेश नायडू ने अमरनाथ यात्रा को हज यात्रा के साथ जोड़कर कहा था कि हज यात्रियों को सरकार भरपूर सुविधायें देती हैं, परन्तु अमरनाथ यात्रियों के लिए 800 कनाल जमीन देकर भी वापस ले ली गई। इसी तरह अशोक मलिक द्वारा बनाये गये ब्लाग में कहा गया था कि यह किसी एक राजनीतिक दल अथवा बिरादरी का आंदोलन न होकर, एक विशाल जनांदोलन है, जिसमें सभी पंथों, वर्गों और जातियों के लोगों ने भाग लिया है। एक ब्लाग में दर्शाया गया था कि जब हिन्दू अपनी आवाज उठाते हैं तो उन्हें साम्प्रदायिक कहकर दबा दिया जाता है। सरकार ने श्री अमरनाथ धाम के मुद्दे पर भी हिन्दुओं को ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। परन्तु इस समय हिन्दू समाज जिस तरह से अपने भेदभावों को भुलाकर इस संघर्ष में कूदा है सफलता अवश्य मिलेगी।

पुलिस के शिकंजे से छुड़ाई महिला नेता

जम्मू शहर से लगभग 10 किमी. दूर गंग्याल क्षेत्र के अंतर्गत एक पुलिस थाने पर भारी संख्या में लोग तिरंगे झण्डे लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने बिना चेतावनी दिये लाठी चार्ज शुरू कर दिया। अनेक महिला और पुरुष घायल हो गये। थाना अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी की महिला नेता किरण सलाथिया को गिरफ्तार करके थाने के लाकअप

में बिठा दिया। बाहर खड़े प्रदर्शनकारियों ने उसकी रिहाई की मांग की और देखते ही देखते सैकड़ों ग्रामवासी भारी तादाद में इकट्ठे को गये। लोगों के हाथ में पैट्रोल के डिब्बे थे। लोगों ने चेतावनी दी कि अगर हमारी नेता को नहीं छोड़ा गया तो थाने को फूंक डालेंगे। लोगों के गुस्से को देखकर पुलिसकर्मी भाग खड़े हुये। इस तरह जनता की संगठित शक्ति ने अपनी नेता को छुड़ा लिया। बाद में लोगों ने पैट्रोल के डिब्बे दिखाते हुये पत्रकारों से कहा कि इसमें पैट्रोल की जगह पर पानी था। हमने पुलिस को मूर्ख बनाकर अपनी नेता को छुड़ा लिया है।

रैसलिंग चैंपियनशिप नहीं, जेल जाना जरूरी

20 अगस्त को पाकिस्तान में "मिशन दोस्ती प्रोग्राम" के अंतर्गत रैसलिंग चैम्पियनशिप प्रतिस्पर्धा हुई। कटड़ा (जम्मू) के रहने वाले भारतीय रैसलिंग टीम के मैनेजर शिवकुमार शर्मा, संघचालक रियासी जिला, इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाले थे। परन्तु कटड़ा में जेल भरो आंदोलन शुरू हो गया। शिवकुमारजी ने पाकिस्तान न जाकर प्रदर्शनकारियों के साथ सत्याग्रह किया और जेल चले गए। जे एण्ड के इंडियन स्टाईल रैसलिंग एसोसिएशन के प्रधान और इंडियन स्टाईल रैसलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कोषाध्यक्ष शिवकुमारजी ने कहा कि इस समय सारा हिन्दू समाज अपने हिन्दू स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा है, मैं इस लड़ाई से अलग कैसे हो सकता हूं इसलिए मैं पाकिस्तान न जाकर जेल जा रहा हूं।

पुलिस पर फेंका अश्रुगैस का गोला

कठुआ शहर में प्रदर्शनकारियों की सभा हो रही थी। हजारों की तादाद में लोग जमा थे। उसी वक्त लगभग सौ युवकों के एक समूह ने पुलिस थाने का घेराव करना चाहा। युवक थाने की ओर बढ़े। पुलिस ने उनका रास्ता रोका। युवा प्रदर्शनकारी आगे बढते गए। पुलिस ने उन पर अश्रुगैस का एक गोला फेंका। वह गोला फटा नहीं। एक प्रदर्शनकारी ने उस गोले को उठाया और पुलिस पर फेंक दिया। उस युवक ने जोर से कहा कि हिम्मत है तो फिर फेंको। इतने में वह गोला फट गया और पुलिस वाले जान बचाने के लिए इधर–उधर भागने लगे। युवकों का जुलूस बम–बम भोले का उद्घोष करता हुआ भाग कर थाने पर पहुंच गया। इसी वक्त हजारों प्रदर्शनकारी भी नारे लगाते हुये वहां पहुंच गये। थाने में मौजूद पुलिस अधिकारियों और आंदोलनकारी नेताओं के बीच हुई बातचीत के बाद घेराव समाप्त हुआ।

पुलिस का घिनौना चेहरा

साम्बा में जुल्म की आंधी

पूरे जम्मू क्षेत्र में हो रहा जनांदोलन अपनी चरमसीमा की ओर बढ़ रहा था। 7 अगस्त को साम्बा शहर में हजारों लोगों ने विशाल प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी पूरे उत्साह में थे। हर हर महादेव के नारे लग रहे थे। शहर के बीचोबीच पुलिस थाने के निकट पहुंचकर लोगों ने धरना दिया। धरना देने के बाद फिर शांतिपूर्ण जलूस आगे बढ़ा। पुलिस ने रास्ता रोककर आगे जाने के लिए मना किया। जब लोग नहीं माने तो पुलिस ने फायरिंग का सहारा लिया। 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुये। जिसमें 6 की हालत अत्यंत गंभीर हो गई। संघर्ष समिति के कार्यकर्त्ताओं ने उन्हें जम्मू के मेडिकल कालेज में भर्ती करवाया। प्रदर्शनकारियों में दो जवान जुगल किशोर और सुनीलसिंह शामिल थे। पुलिस द्वारा की गई गोलाबारी के बाद जब मृतकों और जख्मियों को उठाया जाने लगा तो साम्बा निवासी जुगल किशोर और सुनीलसिंह के शव मिले। पुलिस ने दावा किया कि दोनों जवान हमारी फायरिंग से नहीं मरे। इससे लोगों में भ्रम फैल गया। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि इन्हें आपसी रंजिश के कारण इनके ही किसी पुराने दुश्मन ने मौके का फायदा उठाकर गोलियों से भून दिया। असलियत का पता सरकारी जांच पड़ताल के बाद ही चलेगा।

इसी तरह 4 अगस्त को साम्बा में ही वहां के एसएसपी ने हजारों निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर उस समय गोलियां दागी जब वे शांतिपूर्वक बम–बम भोले और भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। एसएसपी ने आंदोलनकारियों को किसी प्रकार की कोई चेतावनी नहीं दी, बल्कि उनमें से कुछ युवा नेताओं को अपने पास बुलाया। जैसे ही इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे नेता अपने युवा साथियों के साथ एसएसपी की ओर आने लगे तो उसी वक्त एसएसपी ने अपने साथी की राईफल लेकर उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं। दो युवा नेता संजीवसिंह और पवन पाधा मौके पर शहीद हो गये। इस एसएसपी ने महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा। उन पर जमकर लाठीचार्ज किया और दौड़ा–दौड़ा कर पीटा।

पुलिस ने ले लीं पवन की दोनों आंखें

5 अगस्त को दोपहर के समय ज्यौड़ियां के एक मंदिर में संघर्ष

समिति की बैठक चल रही थी। अचानक पुलिस पहुंची और उसने लोगों पर लाठियां भांजनी शुरू कर दीं। खबर मिलते ही पूरे ज्यौड़ियां के सैंकड़ों लोग नारे लगाते हुये वहां पहुंचे। पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए हवाई फायरिंग शुरू कर दी। कुछ गोलियां जमीन पर भी दागी गईं। 22 लोग घायल हो गये। इसी फायरिंग में 30 वर्षीय पवन कुमार की दोनों आंखे चली गईं। इस हादसे से उत्तेजित होकर करीब 150 महिलाओं ने पुलिस पर हमला बोल दिया। कई पुलिसवालों की धुनाई कर डाली गई। पुलिस भाग खड़ी हुई।

बाबा अमरनाथ की जमीन के लिए अपनी दुनियां अंधेरी कर चुका पवन एक गरीब किसान है और मजदूरी भी करता है। पवन के पिता नहीं हैं। उसके परिवार में बूढ़ी मां, एक भाई, दो वर्षीय बच्ची है। जम्मू के सरकारी अस्पताल में पवन का इलाज चल रहा है। डाक्टरों ने उसके इलाज के लिए 8 लाख का खर्चा बताया। एक पूर्व सैनिक 60 वर्षीय अनंत राम ने अपनी एक आंख पवन को देने की पेशकश की। इसी तरह एक अन्य गांववासी मंगूराम ने भी अपनी एक आंख पवन को देने का वायदा किया। पवन की पत्नी रो-रोकर लोगों से पैसा मांग रही थी। संघर्ष समिति ने पवन के इलाज के खर्चे की सारी व्यवस्था करके अपना कर्त्तव्य निभाया है।

मुंडन संस्कार पर अश्रुगैस

जम्मू से करीब 4 किमी. के फासले पर नई बस्ती के एक घर में दोपहर 12 बजे बच्चे के मुंडन संस्कार का समारोह चल रहा था। इलाके में तैनात पुलिस ने इस समारोह को कर्फ्यू का उल्लंघन बताकर घर पर अश्रूगैस के गोले और रबड़ की गोलियां दागनी शुरू कर दीं। रैपिड एक्शन फोर्स और जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा अकारण की गई इस गोलाबारी में कई लोग जख्मी हो गये। 75 वर्षीय एक वृद्ध की टांग बर्बाद हो गई। भगदड़ मचने से तीन बच्चे सीढ़ियों से गिर कर जख्मी हो गये। इस दर्दनाक घटना के बाद सभी रिश्तेदार और अन्य लोग खाना इत्यादि छोड़कर अपने घरों को लौट गये। किसी भी पुलिसकर्मी पर प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं की।

पुलिस ने डाक्टर और बच्चे की बाजू तोड़ी

सरकारी आदेश के तहत जनांदोलन को दबाने के लिए जम्मू-कश्मीर पुलिस के जवानों ने बुद्धिजीवियों, बच्चों, महिलाओं और बीमारों पर भी जुल्म करने की सारी हदें पार कर दीं। डाक्टरों, पत्रकारों

और कई सरकारी कर्मचारियों को दिये गये कर्फ्यू पासों का कोई महत्व नहीं रहा। पुलिस वालों ने कर्फ्यू पास देखकर गालियां निकालते हुये नालियों में फेंक दिये। जम्मू के जानीपुरा के इलाके के एक डाक्टर विनीत महाजन के पास को न केवल फाड़ा, अपितु उसकी जमकर पिटाई भी की गई। राईफल के बटों से पड़ी मार के कारण डाक्टर की बाजू टूट गई। सभी डाक्टर हड़ताल पर चले गये। जिससे अस्वस्थ लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ी परन्तु अस्पतालों में पड़े हुये बीमार लोग भी जनांदोलन की सफलता की कामना करते रहे।

दो महीने तक चले इस जनआंदोलन में जम्मू–कश्मीर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पीटने और उन पर तरह–तरह के अत्याचार करने के कई रिकार्ड कायम कर दिये हैं। पुलिस ने एक तीन वर्षीय बच्चे वंश बबल को भी लाठियों से पीटकर उसकी बाजू तोड़ दी। वंश अपने मामा के साथ गली के चौराहे पर जा रहा था। एक जवान ने अचानक उन पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। उनसे कर्फ्यू पास मांगा गया, कर्फ्यू पास दिखाने के बावजूद भी उनको नहीं बख्शा गया।

हिन्दू नेताओं पर प्रतिबंध

अगस्त के प्रथम सप्ताह में जम्मू के हालात का जायजा लेने साध्वी ऋतंभरा और उमा भारती जैसे ही जम्मू के एयरपोर्ट पर उतरे उन्हें पुलिस ने घेरे में लेकर एयरपोर्ट के ही एक कमरे में नजरबंद कर दिया। साध्वी ऋतंभरा ने सायं 4 बजे जम्मू की परेड ग्राउंड में एक जनसभा में भाषण देना था। इन दोनों नेताओं को वापस दिल्ली लौटने के आदेश दे दिये गये। दोनों साध्वियों ने इस सरकारी आदेश को गैरकानूनी बताकर एयरपोर्ट पर ही धरना दे दिया। साध्वी ऋतंभरा को तो पुलिस ने जबरदस्ती दिल्ली की फ्लाईट में बिठा दिया और उमा भारती को ऊधमपुर के सरकारी गैस्ट हाउस में नजरबंद कर दिया। समाचार मिलते ही ऊधमपुर के हजारों लोग गैस्टहाउस के आंगन में इकट्ठे हो गये। उमा भारती झपटकर पुलिस के घेरे से निकलीं और आधे घंटे तक प्रदर्शनकारियों के सामने भाषण देती रहीं। दूसरे दिन उमा भारती को भी दिल्ली वापस भेज दिया गया। इसी तरह का व्यवहार जम्मू पहुंचे भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह और भाजपा महामंत्री अरुण जेतली के साथ करने की कोशिश की गई। परन्तु लोगों की भारी भीड़ ने इनका स्वागत किया और प्रशासन को मजबूर होकर इन्हें भाजपा कार्यालय तक जाने दिया। इन दोनों नेताओं ने अस्पताल में जाकर जख्मी आंदोलनकारियों की कुशलक्षेम पूछी।

कांग्रेस, पीडीपी और एनसी का सूपड़ा साफ

जैसे–जैसे इस आंदोलन का विस्तार होता चला गया। वैसे–वैसे ही इसका विरोध करने वाले कांग्रेस, पीडीपी और एनसी की पोल खुलती चली गई। पीडीपी और एनसी की हिन्दू विरोधी राजनीति जम्मूवासियों के सामने खुलकर आ गई। कांग्रेस की तुष्टिकरण और एनसी की जम्मू विरोधी नीतियों को समझकर आंदोलनकारियों ने इन दोनों दलों के नेताओं के घरों पर धरने प्रदर्शन शुरू कर दिये। कांग्रेसी मुख्यमंत्री द्वारा श्राइनबोर्ड से जमीन वापस लेने से कांग्रेसी विधायकों का जनाधार खिसक गया।

अनेक कांग्रेसी नेताओं ने दबी जुबान से आंदोलन का समर्थन करना शुरू कर दिया। कांग्रेस में फूट पड़ गई। कांग्रेसी नेता सांसद मदनलाल शर्मा के नेतृत्व में दिल्ली पहुंचे और उन्होंने सोनिया गांधी के दरबार में हाजरी लगा कर संघर्ष समिति की मांगों को स्वीकार करने की सलाह दी।

सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह से मिलने के बाद इन नेताओं ने वापस जम्मू पहुंचकर अज्ञातवास ले लिया। यह नेता अपने घरों से बाहर निकल कर लोगों को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहे। कांग्रेसी नेता और पूर्व मंत्री गुलचैन सिंह चाढ़क को जब राजपूत बिरादरी से बर्खास्त करने की धमकी मिली तो उन्होंने भी श्राइनबोर्ड की धरती वापस करने का बयान जारी कर दिया। इसी तरह पूर्व उपमुख्यमंत्री पंडित मंगतराम शर्मा को भी ब्राहम्मण बिरादरी ने बर्खास्त करने की धमकी दे दी। पंडित जी पर दबाव डाला गया कि वह आंदोलन का समर्थन करें। 24 अगस्त को पंडित मंगतराम शर्मा का आंदोलनकारियों ने घेराव किया। हजारों लोगों के घेरे को पुलिस के जवानों ने तोड़ने में असमर्थतता जताई। प्रशासन ने रैपिड एक्शन फोर्स भेजकर पूर्व उपमुख्यमंत्री को बहुत कठिनाई से सुरक्षित निकाला।

यही स्थिति पूरे जम्मू संभाग में कांग्रेसी नेताओं की बनी। पीडीपी नेताओं के दफ्तरों पर भी लोगों का गुस्सा उतरा। एनसी नेता उमर अब्दुल्ला ने संसद में जब यह कहा कि कश्मीर में हम एक इंच जमीन भी किसी को नहीं देंगे तो जम्मू और पूरे देश में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। उमर फारूख के इस प्रकार के भारत विरोधी बयानों ने भी एनसी के खिलाफ हवा बनाई। इस तरह से जम्मू संभाग में कांग्रेस का जनाधार कमजोर पड़ गया और एनसी, पीपीडी का तो सूपड़ा ही साफ हो गया। इस जनांदोलन ने कांग्रेस की तुष्टिकरण नीति पर आधारित वोट बैंक की राजनीति का पूरी तरह पर्दाफाश कर दिया।

पुंछ में भी फैली अलगाववादी आग पुलिस ने दिया दंगाईयों का साथ

इस राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान कश्मीर के अलगाववादियों ने जम्मू संभाग के मुस्लिम बहुल इलाकों में मुसलमानों को हिन्दुओं के खिलाफ भड़का कर साम्प्रदायिक दंगे कराने की कोशिश की। सरकारी तंत्र, विशेषकर पुलिस में बहुसंख्या में मौजूद पाकिस्तानी तत्व दंगाईयों की मदद पर उतर आये। पुंछ और आसपास के ग्रामीण इलाकों में हिन्दुओं के पलायन का खतरा पैदा हो गया। 1989 में इसी प्रकार की परिस्थितियां बनाकर तीन लाख कश्मीरी हिन्दुओं को उनके घरों से भगाया गया था।

जम्मू संभाग का पुंछ जिला कश्मीर और पाकिस्तान की सीमा से जुड़ा हुआ है। नियंत्रण रेखा के निकट इस जिले में हिन्दुओं की जनसंख्या मात्र 10 प्रतिशत है। इससे सटे हुये राजौरी जिलें में भी हिन्दू केवल 18 प्रतिशत हैं। जम्मू संभाग में बाबा अमरनाथ की जमीन के लिए संघर्ष शुरू होते ही लश्करे तोयबा और हिज्बुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों ने हिन्दुओं को यहां से चले जाने की धमकियां देनी शुरू कर दीं। 23 अगस्त को योजनाबद्ध तरीके से पुंछ के परेड ग्राउंड में 4 हजार से ज्यादा कट्टरवादी मुसलमान एकत्रित हुये। पुलिस की नाक के नीचे यह लोग जुलूस के रूप में शहर में घुसे। इन्होंने हिन्दुओं की 58 दुकानें और दो दर्जन घरों में आगजनी व तोड़फोड़ की। पुलिस तमाशा देखती रही। जब हिन्दुओं ने एकजुट होकर उन्हें रोकने की कोशिश की तो पुलिस ने लाठियां बरसाई, अश्रुगैस और गोलाबारी शुरू कर दी। शहर में कर्फ्यू लगाकर हिन्दुओं की आवाज को खामोश किया गया। उसी रात कुछ मुस्लिम युवकों ने कर्फ्यू तोड़कर हिन्दुओं के घरों और तीन मंदिरों पर पथराव किया। 'काफिरों पुंछ छोड़ों' के नारे लगाये गये। इसी तरह दो दिन बाद पुंछ के निकटवर्ती गांव दलेरा, खनेत और बैंच में भी मुसलमानों ने हिन्दुओं के घरों और धर्मस्थलों पर हमले किये। ऐसे ही हालात राजौरी जिले में भी बनाये गये। हिन्दू नेताओं द्वारा पुलिस थानों, सुरक्षा चौकियों और केन्द्रीय सुरक्षाबलों के नाकों पर जानकारी देने का कोई असर प्रशासन पर नहीं हुआ।

हिन्दुओं के खिलाफ जेहाद

जेके पुलिस की मौजूदगी में बल्कि यह कहना कोई अतिशयोक्ति

नहीं होगी कि पुलिस की मदद से और कश्मीर के अलगाववादी संगठनों की सुनियोजित साजिश के तहत पुंछ जिले में बहुसंख्यक मुस्लिमों ने अल्पसंख्यक हिन्दुओं के खिलाफ जेहाद छेड़ दिया। लगातार दूसरे दिन भी मुस्लिम दंगाईयों के झुंड ने चुन चुनकर हिन्दुओं की दुकानें तोड़ीं और घर जलाये। दो मंदिरों पर पथराव किया। हिन्दुओं के घरों में घुसकर महिलाओं और बच्चों की पिटाई की। इस सबके बावजूद प्रशासन ने अपनी आंखें बंद करके रखीं। पुलिस अधिकारियों ने अपने मोबाइल स्विच बंद कर दिये।

दिन भर पुंछ में आगजनी व लूटपाट को नियंत्रित करने में पूर्णतः विफल रही पुलिस ने दूसरे दिन प्रातः 7 बजे हिन्दुओं के घरों पर बिना किसी कारण अश्रू गैस छोड़ी। जम्मू–कश्मीर पुलिस की मौजूदगी में अलगाववादी तत्त्वों ने हिन्दू बहुल मोहल्लों में भारी उत्पात मचाया। जिसमें एक वृद्ध महिला विमलादेवी की टांग टूट गई और एक युवक की आंख चली गई। पुंछ के साथ सटे ग्रामीण ईलाकों में मुस्लिम युवक मुख्य रास्तों पर एकत्र हो गये। उन्होंने हिन्दू ईलाकों में दहशत फैलानी शुरू की। मुस्लिम प्रदर्शनकारियों ने बैंच में चार दुकानों को आग लगा दी और वहां स्थित भैरों मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया। हिन्दुओं के विरोध करने पर इन दंगाइयों ने उनके घरों पर हमले किये जिसमें कई महिलाएं और युवक घायल हुये। भीड़ ने दलेरा गांव में स्थित शिवमंदिर पर पथराव किया और भीतर जाकर मूर्ति को तोड़ डाला। सुबह 11 बजे से दोपहर 4 बजे तक इस तरह का उत्पात जारी रहा। तब तक प्रशासन ने सुरक्षा के कोई बंदोबस्त नहीं किये थे।

जम्मू क्षेत्र के कठुआ, साम्बा, रियासी और डोडा जिलों में भी अलगाववादी मुसलमानों ने साम्प्रदायिक हालात पैदा करने की भरपूर कोशिश की। ध्यान देने की बात है कि श्री अमरनाथ धाम और शिवभक्त यात्रियों के समर्थन में जम्मू क्षेत्र में बने अद्भुत हिन्दू मुसलमान सौहार्द को अलगाववादी तत्व बर्दाश्त नहीं कर सके। प्रशासन में घुसपैठ किये हुये पाकिस्तानी तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश में जुट गये।

स्थानीय सूत्रों के अनुसार जम्मू–कश्मीर पुलिस के कई जवान सादे कपड़ों में दंगाईयों के साथ मिलकर हिन्दुओं की दुकानें लूटने और घर जलाने का काम करते रहे। डोडा जिले की गन्दोह तहसील के भटयास गांव में उन्मादियों ने दो हिन्दू मंदिरों को जला डाला। इस प्रकार जम्मू संभाग के मुस्लिम बहुसंख्यक इलाकों में कश्मीरी अलगाववादियों की देशद्रोही गतिविधियां जारी रहीं।

किश्तवाड़ में कहर

कश्मीर के अलगाववादी तत्वों और पीडीपी नेताओं के उकसाने पर किश्तवाड़ के बहुसंख्यक मुस्लिम समाज ने उपद्रव शुरू कर दिए। कश्मीर में पुलिस फायरिंग में हुई हुर्रियत नेता अब्दुल अजीज की मौत के बाद यह उपद्रव तेज हो गये। उपद्रवियों ने हिन्दुओं की 48 दुकानें, 23 घर और कई वाहन जला डाले। रात को ही किश्तवाड़ की सभी मस्जिदों से लोगों से हड़ताल करने की अपील की गई। प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया परन्तु उपद्रवियों को रोकने की उस तरह की सख्त कार्यवाही से परहेज किया, जिस तरह की सख्त कार्यवाही से जम्मू के देशभक्त लोगों पर जुल्म किये गये। कर्फ्यू में सरकारी ढिलाई को देखकर हजारों बहुसंख्यक लोग सड़कों पर उतर आये। किश्तवाड़ के हड़ियाल चौक में जुलूस निकाला गया। किसी शरारती ने एक पत्थर फेंका और सारा माहोल फिरकापरस्ती के रंग में रंग गया। भीड़ में दो ग्रेनेड फटे जिनमें दो लोगों की मौत हो गई। हिन्दुओं की दुकानें लूटी गई। इसी के बाद तनाव बढ़ा और आगजनी लूटमार शुरू हो गई। पुलिस और सीआरपीएफ खड़ी–खड़ी तमाशा देखती रही।

श्रीअमरनाथ यात्रा संघर्ष समिति ने आरोप लगाया कि अलगाववादियों के आगे झुकने वाली सरकार ने यहां भी बहुसंख्यक समाज की हिंसक ज्यादतियों के आगे समर्पण कर दिया है। जबकि जम्मू में सारा आंदोलन साम्प्रदायिक सौहार्द के साथ चल रहा था। पीडीपी और अलगाववादियों ने किश्तवाड़ में साम्प्रदायिक तनाव इसलिए करवाया कि जम्मूवासियों का मुख्य मुद्दे से ध्यान हट जाये।

पुलिसिया पक्षपात

कश्मीर में कहीं भी सख्त कार्रवाई नहीं हुई। नेताओं को गिरफ्तार करने के बजाय उन्हें उनके आलीशान घरों में ही नजरबंद किया गया। कश्मीरी नेताओं को प्रेस कांफ्रेंस करने, इलेक्ट्रोनिक मीडिया को साक्षात्कार देने और खुले में जन सभायें करने की छूट दे दी गई। जहां तक कि पाकिस्तान और इस्लाम के झण्डे फहराने और भारत के राष्ट्रीय ध्वज जलाने पर भी जम्मू–कश्मीर पुलिस मौन होकर खड़े–खड़े तमाशा देखती रही।

देश के कोने–कोने में फैला धर्मरक्षक जनांदोलन

विश्व हिन्दू परिषद ने श्री अमरनाथ यात्रा के राष्ट्रीय मुद्दे पर जम्मू संभाग की जनता द्वारा शुरू किये गये प्रखर राष्ट्रवादी जनांदोलन के समर्थन के लिए देशवासियों का आह्वान किया। दिल्ली में विश्व हिन्दू परिषद के केन्द्रीय कार्यालय में संघ परिवार सहित अनेक हिन्दू संगठनों के प्रतिनिधियों की एक महत्वपूर्ण बैठक में देशव्यापी आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। इससे पहले 3 जुलाई को विश्व हिन्दू परिषद के आह्वान पर पूरे देश में बंद का सफल आयोजन हो चुका था। इस भारत बंद का असर जम्मू से बंगलोर और कच्छ से कामरूप तक दिखाई दिया। पूरे देश के व्यापारिक प्रतिष्ठान और शिक्षण संस्थान बंद रहे। सड़कों पर यातायात पूर्णतः ठप्प रहा। इस सफल बंद से जम्मूवासियों के हौंसले बुलंद हुये और पूरे क्षेत्र में आंदोलन तेज हुआ।

4 अगस्त को विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकर्त्ताओं ने संत महात्माओं के नेतृत्व में और विभिन्न हिन्दू संगठनों के सहयोग से शिव मंदिरों में जलाभिषेक कार्यक्रम का आयोजन किया। देश के 35 हजार मंदिरों में यह कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। जलाभिषेक के बाद मंदिरों में अथवा मुख्य द्वार के बाहर खुली सड़कों और चौराहों पर महाशिव आरती की गई। इन कार्यक्रमों में परिषद के नेताओं तथा साधु संतों ने अपने उद्‌बोधनों में देश की जनता को जम्मू में छिड़ी जमीन की जंग की विस्तृत जानकारी दी। राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सौहार्द के साथ जुड़ी श्री अमरनाथ यात्रा के महत्व की जानकारी देते हुये संतों ने कहा कि जम्मू--कश्मीर की सरकार ने श्रीअमरनाथ श्राइनबोर्ड को यात्रियों की सुविधा के लिए पहले जमीन दी और फिर स्वयं ही उसे वापस लेकर हिन्दुओं की आस्था पर भारी आघात किया है। यह संघर्ष हिन्दुत्व पर आये इस संकट को परास्त करने के लिए छेड़ा गया है। श्रीअमरनाथ श्राइन बोर्ड को जमीन वापसी तक लड़ाई जारी रखी जायेगी।

6 अगस्त को प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई और इस आंदोलन को समाप्त करके कथित शांति की स्थापना में मदद करने की अपील की। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के प्रधान राजनाथ सिंह, भाजपा के महामंत्री श्री अरूण जेतली और भाजपा नेता जसवंत सिंह ने भाग लिया। इन तीनों नेताओं ने जोर देकर

कहा कि सरकार का अलगाववादियों से डर कर जमीन वापस लेने का कदम असंवैधानिक और ओछी राजनीति की मिसाल है। सरकार को जमीन वापस करनी चाहिए ताकि देश–विदेश के हिन्दू तीर्थ यात्री सुविधा पूर्वक श्रीअमरनाथ यात्रा में भाग ले सकें। प्रधानमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व उपप्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी को विशेष रूप से अपने निवास पर बुलाकर उनसे आग्रह किया कि वह इस संवेदनशील मुद्दे पर कोई रास्ता निकालने के लिए सरकार का साथ दें। लालकृष्ण आडवानी ने दो टूक उत्तर देते हुये स्पष्ट किया कि यह आंदोलन उनकी पार्टी नहीं चला रही। श्री अमरनाथ यात्रा संघर्ष समिति ने यह आंदोलन शुरू किया है, वही इसको समाप्त कर सकती है। हम इस मुद्दे पर संघर्ष समिति के साथ हैं। आडवाणी ने प्रधानमंत्री को संघर्ष समिति से सीधे बात करने की सलाह दी।

10,11,12 अगस्त को भारत के सभी प्रांतों की राजधानियों में जेल भरो सत्याग्रह शुरू हुआ। लाखों लोगों ने गिरफ्तारियां देकर अमरनाथ संघर्ष समिति को अपना समर्थन दिया। इस सत्याग्रह में देशभर में 5 लाख से ज्यादा लोगों ने जेल यात्रा की। स्थान–स्थान पर साधु महात्माओं, विश्व हिन्दू परिषद तथा देश भर के अनेक हिन्दू संगठनों के नेताओं और समाज के प्रतिष्ठित धार्मिक नेताओं ने अपने भाषणों में लोगों से अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति तक आंदोलन जारी रखने की अपील की।

पूरे देश में चक्का जाम

विश्व हिन्दू परिषद ने भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से 13 अगस्त को पूरे देश में चक्का जाम रखने का आह्वान किया। प्रातः 9 बजे से लेकर 11 बजे तक दो घण्टे तक किये गये इस चक्का जाम कार्यक्रम को अद्भुत सफलता मिली। लगभग 7 लाख लोगों ने सड़कों पर उतर कर शांतिपर्वूक चक्का जाम करवाया। 85 हजार स्थानों पर सफल हुये इस चक्का जाम से संघर्षरत जम्मूवासियों का उत्साह बढ़ा। इस चक्का जाम कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी हिन्दू संगठन और भाजपा कार्यकर्त्ता जुटे रहे। जनता ने भी पूरा सहयोग दिया। शहरों के प्रायः सभी प्रमुख चौराहों पर यातायात जाम रहा। अधिकांश स्थानों पर ट्रेनों को रोका गया। कई स्थानों पर पुलिस ने बल प्रयोग करके कार्यकर्त्ताओं को रोकने की विफल कोशिश की। शिक्षण संस्थाओं में उपस्थिति बहुत कम रही। चक्का जाम करवाने और प्रदर्शन करने में सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक दलों के कार्यकर्त्ताओं के साथ भारी संख्या में बच्चों और महिलाओं ने भी सहयोग दिया। भारत माता की जय, लाठी गोली

खायेंगे– भूमि वापस लायेंगे और बम–बम भोले के नारों के साथ मुख्य चौराहों पर धरने दिये गये।

सभी प्रांतों के प्रायः सभी जिलों में चक्काजाम बहुत सफल रहा। लोगों ने ट्रेनें और बसें रोकीं। खास बात यह रही कि इन वाहनों में सवार यात्रियों ने भी नारे लगाकर आंदोलनकारियों का साथ दिया। इसी तरह भोपाल, पटना, जयपुर, झांसी इत्यादि स्थानों से भी रेलगाड़ियों को रोककर चक्काजाम को सफल किया गया। हिमाचल प्रदेश के शिमला–कालका राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात दो घंटे तक बंद रहा। इसी तरह जम्मू–कश्मीर के निकटवर्ती राज्यों पंजाब और हरियाणा में भी चक्का जाम सफल रहा।

देशव्यापी जेल भरो आंदोलन

हिन्दुओं के स्वाभिमान की रक्षा के लिए शुरू किये गये जनांदोलन को सारे देश में पहुंचाने के लिए एक और प्रयास 21 अगस्त को किया गया। इस दिन भारत के प्रत्येक जिला केन्द्रों पर सत्याग्रह करने की योजना बनी। विश्व हिन्दू परिषद के नेतृत्व में 9 लाख से ज्यादा स्त्री–पुरूष जेलों में गये। भारतीय जनता पार्टी ने इस जेल भरो आंदोलन में भरपूर साथ दिया। भाजपा, संघ और विश्व हिन्दू परिषद के लाखों कार्यकर्त्ताओं के साथ–साथ समाज ने बढ़चढ़ कर जेल भरो आंदोलन में हिस्सा लिया। सभी स्थानों पर यह कार्यक्रम सफल रहा। जिसमें गिरफ्तारी देने वालों में भाजपा महासचिव अरूण जेतली, दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष डा. हर्षवर्धन, विश्व हिन्दू परिषद के महामंत्री डा. प्रवीण भाई तोगड़िया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग संघ चालक ईश्वरदास महाजन और संघ की केन्द्रीय कार्यकारिणी के सदस्य श्री राममाधव प्रमुख थे। पंजाब और हरियाणा में भी जेल भरो कार्यक्रम के अंतर्गत 50 हजार से ज्यादा लोगों ने गिरफ्तारियां दीं। संघर्ष समिति के नेताओं समेत सभी आंदोलनरत संगठनों के नेताओं ने अफसोस जताते हुये कहा कि हिन्दुओं को अपने ही देश के एक हिस्से में श्री अमरनाथ यात्रियों की सुविधा के लिए जमीन उपलब्ध करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।

बाबा अमरनाथ जमीन पर छिड़ी जंग इस तरह पूरे देश में फैलती चली गई। आर्य समाज, सनातन धर्म सभा और शिव सेना जैसे बड़े हिन्दू संगठनों ने इस संघर्ष में भाग लिया। मंदिरों में होने वाली आरतियों के समय पुजारियों तथा प्रबंधकों ने लोगों से अमरनाथ की जमीन वापसी के लिए प्रार्थना करने को कहा। विश्व हिन्दू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री डा. प्रवीण तोगड़िया ने दिल्ली से बयान जारी करते

हुये कहा कि अमरनाथ श्राइन बोर्ड को दी जाने वाली जमीन और इसे वापस लिये जाने के विवाद से हिन्दू समाज में चेतना जागृत हुई है। इस चेतना के फलस्वरूप राष्ट्रद्रोही तत्वों के मंसूबे धरे–धराये रह जायेंगे। इस संघर्ष के लिए समर्थन जुटाने के उद्देश्य से आयोजित "अखिल भारतीय मठ मंदिर आयाम" प्रमुखों की बैठक का शुभारंभ करते हुये डा. तोगड़िया ने कहा कि आज हिन्दुओं के धर्मस्थलों और मान बिन्दुओं पर जो विधर्मी हमले हो रहे हैं उनका प्रतिकार करने के लिए समस्त हिन्दू समाज को संगठित करने और शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है।

विहिप के अध्यक्ष अशोक सिंहल का वक्तव्य
सौ करोड़ भारतीयों की आस्था का सवाल

श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के गठन और तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए दी गई जमीन को वापस करने की मांगों को लेकर जम्मू संभाग के निवासियों द्वारा चलाये गये इस आंदोलन को पूरे भारत का समर्थन है। हम भारत सरकार को चेतावनी देते हैं कि वह उन जेहादियों को खुश करने के चक्कर में न पड़े जो देश का फिर से विभाजन करने पर तुले हैं।

अमरनाथ प्रकरण पर पूरे देश का हिन्दू एकजुट है। 3 जुलाई 2008 को भारत बंद के आह्वान पर इस एकता का प्रगटीकरण हो चुका है। भारत सरकार हिन्दू समाज की उपेक्षा करके उस पर अपना निर्णय लादने की गलती न करे। भगवान अमरनाथ यात्रा का प्रबंध करना, यात्रियों की सुरक्षा करना और उन्हें आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाना हिन्दुओं का संवैधानिक अधिकार है। जम्मू–कश्मीर राज्य में हिन्दू अल्पसंख्यक होने के नाते सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार उन्हें संविधान प्रदत्त अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। श्राइन बोर्ड के गठन और कार्य में सरकार को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सम्पूर्ण भारतवर्ष में मुसलमानों को बक्फ संपत्ति, उनकी संस्थाओं, कालेजों और यात्राओं का प्रबंध बिना सरकारी हस्तक्षेप के संभालने का अधिकार प्राप्त है।

यदि भारत सरकार श्रीअमरनाथ यात्रा संघर्ष समिति की इच्छाओं के अनुसार श्राइन बोर्ड का गठन करके उसे पहले दी गई 100 एकड़ वनभूमि का अधिकार वापस नहीं सौंपती तो यह हिन्दू जनांदोलन पूरे देश के गांव–गांव तक फैलता चला जायेगा। छोटे से श्री रामलला ने जब पूरे देश को हिलाकर रख दिया था तो आज अमरनाथ बाबा शिव, रामसेतु और रामेश्वरम् भगवान शिव मिलकर देश में भूचाल ला सकते हैं। यह मात्र कोई भावुकता नहीं है। यह 100 करोड़ भारतीयों की आस्था का सवाल है।

केन्द्र सरकार की पक्षपातपूर्ण नीति

जम्मू–कश्मीर में स्वयं अपने ही हाथों से लगाई आग को बुझाने के लिए केन्द्र सरकार ने एक बार फिर अलगाववादी संगठनों के आगे समर्पण किया। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की जमीन के झगड़े को सुलझाने में पूर्णतः विफल रही सरकार ने अब मुस्लिम वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए हिन्दुओं को ब्लैकमेल करना शुरू किया। कांग्रेस को अभी भी यही लग रहा था कि हिन्दुओं के जज्बातों से खेलकर मुस्लिमों की वाह–वाही लूटी जा सकती है। प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह, गृहमंत्री शिवराज पाटिल और तुष्टिकरण की राजनीति के शिकारी अन्य राजनीतिक दलों को अभी तक यही समझ नहीं आया कि जम्मू में प्रगट हुआ प्रखर राष्ट्रवाद कांग्रेस, एनसी, पीडीपी और देश की सभी भारत और हिन्दू विरोधी ताकतों के लिए भस्मासुर साबित होगा।

केन्द्र सरकार की पक्षपातपूर्ण नीति और जम्मू को कश्मीर से लड़ाने की कोशिश का पर्दाफाश इसी एक तथ्य से होता है कि कश्मीर में जरा सी भी हलचल होती है तो सारी सरकार हरकत में आ जाती है। प्रधानमंत्री बैठकें बुलाते हैं, गृहमंत्री भागते हुये श्रीनगर पहुंचते हैं। कश्मीरी आवाम की सुरक्षा, खाद्य सामग्री, पैट्रोल और बिजली पानी के इंतजाम सरकारी स्तर पर किये जाते हैं। यह सरकार पाकिस्तान के झण्डे फहराने वाले देशद्रोहियों से डर जाती है। परन्तु जम्मू में डेढ़ महीने से चले आ रहे पूर्ण बंद, नौ युवकों की शहादत और निरंतर सत्याग्रह का तनिक भी असर केन्द्र की सरकार पर नहीं पड़ा। जम्मू के देशभक्त लोग लगातार कर्फ्यू की मार झेलते हुये भूखे प्यासे रहकर अपने सामाजिक और धार्मिक अधिकारों की लड़ाई जारी रखे हुये थे। सरकार की रणनीति जम्मू के लोगों को थकाने और अस्पतालों, बैंकों, उद्योगों, शिक्षा संस्थानों और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के केन्द्रों को लम्बे समय तक बंद रखने की थी। सरकार अपनी इस दमनकारी नीति से एक तीर से कई शिकार कर रही थी। जम्मू के आंदोलनकारियों का दम तोड़ने, कश्मीरी संगठनों को खुश करने, श्राइन बोर्ड को जमीन वापस न करने और अपने एजेंट राज्यपाल एन.एन. वोहरा का उत्साह बढ़ाने जैसे कई उद्देश्य पूरे करती रही सरकार।

तुष्टीकरण पर उतरी सर्वदलीय कमेटी

जम्मू की जनता द्वारा किये जा रहे संघर्ष से निरंतर 40 दिन तक आंखे मूंदने के बाद केन्द्र की सरकार को हिन्दू आक्रोश की कुछ समझ आई। गृहमंत्री शिवराज पाटिल की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय कमेटी श्री अमरनाथ यात्रा संघर्ष समिति से बात करने के लिए 9 अगस्त को जम्मू पहुंची। इस कमेटी में केन्द्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटिल, केन्द्रीय ग्रामीण विकासमंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह, केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री सैफुद्दीन सोज, केन्द्रीय मंत्री ए. राजा, केन्द्रीय राज्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, सीपीआई सांसद डी राजा, नेशनल कांफ्रेंस सांसद डा. फारूख अब्दुल्ला, भाजपा सांसद अरूण जेतली, लोक जनशक्ति सांसद रामचन्द्र पासवान, पीडीपी सांसद महबूबा मुफ्ती, समाजवादी पार्टी सांसद अमर सिंह, भाकपा सांसद सीताराम येचुरी, सांसद नरेश गुजराल, कांग्रेस सांसद मोहिसिना किदवई, सांसद के.सी. त्यागी और पूर्व सांसद डा. अख्तर हुसैन रिजवी शामिल थे।

जम्मू में जारी आंदोलन का अहसास सर्वदलीय कमेटी को करवाने के लिए जम्मू की जनता ने कड़े विरोध प्रदर्शन करते हुये काले झण्डों से इसका स्वागत किया। एयरपोर्ट से लेकर राजभवन तक हजारों महिलाओं-पुरुषों ने मानव श्रंखला बनाकर प्रदर्शन किये। प्रदर्शनकारियों ने कर्फ्यू, सैनिक घेरे और जम्मू-कश्मीर पुलिस की भारी नाकेबंदी की धज्जियां उड़ाकर पाटिल के काफिले को रोकने की सोची परन्तु प्रशासन ने सैन्य बल के सहारे पाटिल के काफिले को सतवारी सैन्य छावनी के रास्ते से राजभवन पहुंचा दिया। जय श्री अमरनाथ, बम-बम भोले, भारत माता की जय के नारों के साथ गृहमंत्री और उसके साथ आये अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं को चेताया गया। राजभवन के निकटवर्ती मोहल्लों करण नगर और पंजतीर्थी में महिलाओं और बच्चों ने घरों की छतों पर चढ़कर थालियां बजाई और जमीन वापसी के नारे लगाये।

लोगों के जज़्वात दबाए गए

प्रशासन ने इस दिन भी लोगों के जज़्वात दबाने के लिए पुलिस और सेना को सख्त कार्यवाही करने की खुली छूट दे दी। जम्मू शहर को सैनिक छावनी में बदल दिया गया। पूरे शहर के गली-मोहल्लों को कांटेदार तारों से सील कर दिया गया। मीडिया कर्मियों के कर्फ्यू पास फाड़े गये। कई पत्रकारों को पीटा गया। पूरे दिन कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी गई। तो भी प्रातः 8 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक संघर्ष

समिति के स्थानीय नेताओं के नेतृत्व में लोगों ने जुलूस इत्यादि निकाले। पुलिस की लाठियों, अश्रुगैस और गोलियों का सामना करते हुए लोग सड़कों पर उतरे। इस बीच संघर्ष समिति के 24 सदस्य श्री लीला करण शर्मा के नेतृत्व में सर्वदलीय कमेटी से बात करने के लिए तैयार हुये। परन्तु जब उन्हें पता चला कि बातचीत में राज्यपाल वोहरा, पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती, एनसी संरक्षक डा. फारूख अब्दुल्ला, पूर्व मुख्यमंत्री गुलामनबी आजाद और केन्द्रीय मंत्री सैफुद्दीन सोज भी भाग लेगें तो संघर्ष समिति ने वार्त्तालाप के बहिष्कार की घोषणा कर दी।

संघर्ष समिति के संयोजक श्री लीलाकरण शर्मा ने गृहमंत्री पाटिल को आगाह किया कि इन्हीं नेताओं ने कश्मीरी अलगाववादियों के आगे घुटने टेककर श्राइनबोर्ड की जमीन वापस करवाई है। इनकी मौजूदगी में होने वाली कोई बातचीत सार्थक नहीं हो सकती। समिति ने यह शर्त भी रखी कि राज्यपाल के सरकारी निवास राज भवन में वार्ता नहीं होगी। बाजी हाथ से जाते देखकर गृहमंत्री ने समिति की दोनों शर्तें मान लीं। उपरोक्त पांचों नेताओं को मुंह लटका कर वार्ता से दूर रहना पड़ा। सायं 4.30 बजे सर्वदलीय कमेटी और संघर्ष समिति में बातचीत शुरू हुई। गृहमंत्री पाटिल ने आंदोलन वापस लेने की जैसे ही बात की तो संघर्ष समिति के नेताओं ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। संघर्ष समिति ने साफ कहा कि राज्यपाल के त्याग पत्र और जमीन वापसी से कम कोई फैसला स्वीकार नहीं होगा। इस तरह वार्तालाप बेनतीजा रहा। सायं 7.50 पर सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल श्रीनगर के लिए रवाना हो गया। शर्म की बात यह है कि गृहमंत्री ने जम्मू के दर्दनाक हालात, पुलिस द्वारा बरसाये जा रहे कहर, लोगों के कष्टों, मजबूरियों का कोई जायजा नहीं लिया। शहीद हुये युवकों के परिवारों के साथ कोई हमदर्दी नहीं जताई। अस्पतालों में कराह रहे जख्मियों की कुशलक्षेम पूछने के लिए समय नहीं निकाला। गृहमंत्री के इस व्यवहार से जम्मू के लोग और ज्यादा भड़क उठे।

मौकापरस्त राजनीति

हैरानी की बात यह है कि हिन्दू बहुल जम्मू क्षेत्र के लोगों के दुख दर्द के साथ जरा भी सहानुभूति प्रकट न करने वाले गृहमंत्री पाटिल ने मुस्लिम कश्मीर में पहुंचते ही मौकापरस्त राजनीति और चाटुकारिता की सारी हदें पार कर दीं। कश्मीर में हुये प्रत्येक तरह के नुकसान की भरपाई के भरोसे दिलाये गये। फल उत्पादकों को पूरा मुआवजा देने की घोषणा कर दी गई। यह भी आश्वासन दिया गया कि अगर कोई सेब उत्पादक अपना माल भारत में नहीं भेजना चाहता तो उसका सारा माल

सरकार खरीद लेगी। पाटिल ने यह भी मान लिया कि पठानकोट–जम्मू–श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने वाले कश्मीर के ट्रकों को सैन्य सुरक्षा दी जायेगी। कश्मीर के लोगों की सुरक्षा के और भी ज्यादा पुख्ता इंतजाम किये जायेंगे। गृहमंत्री महोदय ने जम्मू के हिन्दुओं के जख्मों पर नमक छिड़कते हुये कश्मीर के अलगाववादियों को यकीन दिलाया कि जम्मू क्षेत्र में रहने वाले मुसलमानों को हुये नुकसान का भी मुआवजा दिया जायेगा। गृहमंत्री उपरोक्त आश्वासन दिलाते हुये शायद यह भूल गये कि वह भारत के गृहमंत्री हैं न कि मुसलमानों के।

जम्मू व कश्मीर के लोगों के जायज कष्टों और शिकायतों को दरकिनार करने वाले गृहमंत्री ने कश्मीरियों के घड़याली आंसुओं पर पूरा विश्वास किया। कश्मीरी नेताओं ने जम्मू में मुसलमानों को मारने, कश्मीरी मुसलमानों को भगाने और उनकी संपत्ति जलाने की मनगढ़ंत शिकायतें कीं। पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती समेत प्रायः सभी कश्मीरी संगठनों ने गृहमंत्री के सामने रोना रोया कि जम्मू वालों ने कश्मीरियों की आर्थिक नाकेबंदी करने के लिए ट्रकों की आवाजाही रोक दी है, जिससे कश्मीर में जरूरी चीजों की कमी के कारण लोग भूखों मरने लगे हैं। जबकि असलियत इसके विपरीत है। सरकार के आदेश पर सैनिक सुरक्षा में जरूरी सामग्री के ट्रक कश्मीर में पहुंचे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जम्मू में हड़ताल, बंद और सत्याग्रह इत्यादि शुरू होने के बाद पहले दस दिनों में 3072 ट्रक खाद्य सामग्री लेकर कश्मीर पहुंचे। 2142 ट्रक फल इत्यादि लेकर कश्मीर से जम्मू के रास्ते सारे देश में गये। जुलाई मास में 25633 ट्रक जम्मू के रास्ते से कश्मीर में गये और 15401 ट्रक कश्मीरी मेवा लेकर भारत के अन्य हिस्सों में पहुंचे। उसके बाद लगभग 700 ट्रकों की कश्मीर से आवाजाही रोज होती रही।

पाक समर्थक "मुजफ्फराबाद चलो" मुहिम

गृहमंत्री पाटिल के इस हद तक कश्मीरी नेताओं की चाटुकारिता करने के बावजूद भी अलगाववादी संगठनों ने "मुजफ्फराबाद चलो" अभियान को जारी रखा। कश्मीर के नेताओं द्वारा फलों और सब्जियों के ट्रकों के साथ मुजफ्फराबाद के लिए कूच करने का ऐलान कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में लाने का एक सियासी पाखंड था। पाक अधिकृत कश्मीर की सरकार द्वारा, सीमा पार करके मुजफ्फराबाद पहुंचने वाले कश्मीरियों के स्वागत की तैयारी भारत के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी थी। देश की सीमा पार करके दूसरे देश में जाने, धमकी और फिर कोशिश दोनों ही गैर कानूनी और देशद्रोह की श्रेणी में आते

हैं। सरकार ने इन अलगाववादियों को गिरफ्तार करके इन पर देशद्रोह के मुकदमें क्यों नहीं चलाये? हालात बिगड़ने का इंतजार करना और बाद में बल प्रयोग करना कहां की कूटनीति है? जब पाक अधिकृत कश्मीर के प्रधानमंत्री ने सीमा पार करने वालों के लिए स्वागत शिविरों का बंदोबस्त करके खाद्य सामग्री और दवाईयां इत्यादि देने की व्यवस्था का ऐलान किया था तो भारत की सरकार ने पाकिस्तान अथवा पाक अधिकृत कश्मीर की सरकार के साथ विरोध क्यों नहीं जताया? पड़ोसी देश द्वारा हमारे देश के एक प्रांत के लोगों को सीमा पार करने के लिए उकसाने का कार्य अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है। इस संवेदनशील मुद्दे पर भारत की सरकार का खामोश रहना इस बात का सबूत है कि सरकार किसी भी कीमत पर अलगाववादियों को नाराज नहीं करना चाहती।

■■■

अलगाववादियों को पाकिस्तान और अरब देशों से पैसा मिलता है –आजाद

पीडीपी द्वारा समर्थन वापस लेने पर 7 जुलाई को विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव पर अपने एक घंटे बाईस मिनट के भाषण में मुख्यमंत्री गुलामनबी आजाद, पीडीपी और हुर्रियत कांफ्रेंस की पोल खोलते हुए कहते हैं कि इन नेताओं की एक टांग हिन्दुस्थान में रहती है तो दूसरी कहीं और। ये लोग 60 साल से रियासत के लोगों को गुमराह करते हुए कुर्सी के लिए अपनी सांप्रदायिक, राष्ट्रविरोधी और मौकापरस्त राजनीति चला रहे हैं। आजाद ने आगे कहा कि इस्लाम इतना कमजोर नहीं कि वह शेरवानी पहनने वालों के आधार पर ही चले या किसी को जगह देने पर खतरे में पड़ जाए। उन्होंने कहा कि ये लोग उनका घर जलाते हैं, जिनके घर में खाने को रोटी नहीं। इनके बच्चे पाक और सऊदी अरब में एमबीबीएस कर रहे हैं। इस तरह आजाद ने कश्मीर में पिछले कई वर्षों से सक्रिय पाकिस्तानी तत्वों की पोल खोली। आजाद ने बड़े ही नाटकीय ढंग से स्वीकार किया कि हुर्रियत कांफ्रैंस, पीडीपी, एनसी तथा अनेक अलगाववादी तत्व कश्मीर के अंदर न केवल फिरका परस्ती की आग लगा रहे हैं अपितु भारत को तोड़ने जैसी देशघातक हरकतों को अंजाम भी दे रहे हैं। आजाद के अनुसार इन कट्टरपंथी नेताओं को पाकिस्तान, अरब देशों और हवाला से भारी धन मिलता है।

जनांदोलन को मिला व्यापक समर्थन

मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने गिरफ्तारियां दीं

भारत के विभिन्न भागों में रह रहे राष्ट्रवादी मुसलमान भी हिन्दुओं की आस्था पर हुये आघात से दुःखी थे। हाल ही में गठित राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के सदस्यों ने 9 अगस्त को दिल्ली के लाल किले से पैगाम–ए–अमन यात्रा शुरू की। इस यात्रा में शामिल देशभक्त मुसलमान श्रीनगर के लाल चौक तक अमन और हिन्दू–मुस्लिम भाईचारे का पैगाम लेकर जाना चाहते थे। परन्तु राज्यपाल वोहरा के संकेत पर प्रदेश की पुलिस ने इन्हें जम्मू के प्रवेश द्वार लखनपुर में ही रोक दिया। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सदस्यों ने तीन घण्टे तक राष्ट्रीय मार्ग पर धरना दिया। रावी पुल पर यातायात जाम हो गया। देशभक्त मुसलमानों ने राज्य और केन्द्र सरकार के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन कर हिन्दुओं को जमीन वापस करने के आंदोलन का समर्थन किया।

पैगाम–ए– अमन में शामिल हुये देश के विभिन्न प्रांतों के राष्ट्रवादी मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि नेताओं ने अपने भाषणों में कहा कि सरकार श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की जमीन का झगड़ा खड़ा करके हिन्दू–मुस्लिम एकता पर भी कड़ा आघात कर रही है। मुस्लिम नेताओं ने सरकार से पूछा कि यदि भारत में हज हाउस बनाने के लिए सरकार जमीन दे सकती है तो अमरनाथ श्राइन बोर्ड को कश्मीर में जमीन क्यों नही दी जा सकती? जब पुंछ में बाबा गुलामशाह विश्वविद्यालय बनाने के लिए जमीन मुहैया करवाई जा सकती है तो अमरनाथ श्राइन बोर्ड को जमीन देने पर यह बवाल क्यों खड़ा किया गया?

पहले भारतीय बाद में मुसलमान

लखनपुर में पैगाम–ए–अमन के यात्रियों और जनता के सामने भाषण देते हुये मुस्लिम नेताओं ने कहा कि हमारी यात्रा को गृहमंत्री शिवराज पाटिल और यूपीए सरकार के इशारे पर रोका गया है। हम अपने हिन्दू भाईयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्रवाद के इस मुद्दे पर संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। हम पहले भारतीय हैं बाद में मुसलमान। हज कमेटी दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष तनवीर अहमद का कहना था कि सरकार में बैठे ऊंचे सख्स लोगों के जज्बातों का मजाक उड़ा रहे हैं। इससे हिन्दू मुस्लिम भाईचारे को खतरा पैदा होता है। जब तक श्राइन बोर्ड को जमीन वापस नहीं मिलती मुस्लिम राष्ट्रीय मंच अमरनाथ यात्रा संघर्ष समिति का समर्थन करता रहेगा। हरियाणा के रहने वाले

औरंगजेब ने कहा कि हम हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए अपने बलिदान देने के लिए तैयार हैं। पीडीपी और एनसी के हिन्दू विरोधी इरादों को कभी कामयाब नहीं होने दिया जायेगा। हज कमेटी छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष डा. सलीम राजा ने पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद और उनकी बेटी महबूबा को देश का गद्दार मुसलमान कहा।

इसी तरह एक महिला मुस्लिम नेता शाहीन अफजल ने भी कहा कि सरकार ने अमरनाथ यात्रियों की सुविधा के लिए दी गई जमीन को वापस लेकर बहुसंख्यक हिन्दू समाज के धार्मिक हकों पर कुठाराघात किया है। जमीन की आड़ में घटिया राजनीति करने वाली भारत विरोधी ताकतों के मंसूबों को हम विफल करेंगे। झारखण्ड के शाही ईमाम ने कहा कि अमरनाथ यात्रा का मुद्दा करोड़ों हिन्दू भाइयों की आस्था से जुड़ा हुआ है। जब तक बोर्ड को जमीन नहीं मिलती हम वापस नहीं जायेंगे। इस तरह देशभक्त मुसलमानों ने अपने विचारों का प्रगटीकरण किया और संघर्ष में पूरा समर्थन देने का ऐलान करके वापस दिल्ली लौट गये।

आंदोलन की सफलता में संतो का योगदान

कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक व्याप्त विशाल हिन्दू समाज में संतों महात्माओं का अपना एक विशेष सम्मानजनक स्थान है। अत्यंत प्राचीन काल से ही इस संत शक्ति ने हिन्दू समाज को संगठित और संस्कारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राजनीति से दूर रहकर इस धर्मसत्ता ने सदैव राजसत्ता पर अंकुश लगाकर उसे राष्ट्र और समाज विरोधी कृत्यों से रोका है। कोटि-कोटि हिन्दुओं के आस्था स्थल श्री अमरनाथ धाम के मुद्दे पर सम्पन्न हुये इस सफल आंदोलन में भी संत शक्ति ने अपने राष्ट्रीय कर्त्तव्य की पूर्ति की है। लोगों को प्रेरित करने और स्वयं भी आंदोलन में शामिल होकर गिरफ्तारियां देने में संत महात्मा पीछे नहीं रहे। संत नारायण दास, स्वामी रामजन्मदास, मंहत नंद किशोर, महंत स्वामी शुभनारायण दास, स्वामी रामेश्वरदास, महंत महावीर पुरी, संत हृदयदास, महंत स्वामी अनुरूद्धदास और महंत मंगलदास ने विभिन्न प्रदर्शनों का नेतृत्व करते हुये अपनी गिरफ्तारियां दीं। अनेक संतों ने अपने अनुयायियों के साथ कर्फ्यू और लाठीचार्ज जैसे अत्याचार सहकर साधारण आंदोलनकारियों का साथ दिया।

ओजस्वी वक्ता स्वामी दिनेश भारती

संतों की इस राष्ट्रभक्त टोली में सबसे प्रमुख रहे राधाकृष्ण मंदिर के मुख्य महंत स्वामी दिनेश भारती। स्वामी जी ने अपनी जोशीले भाषण शैली

से लाखों लोगों में उत्साह भरा। स्वामी दिनेश भारती अधिकांश प्रदर्शनों की अगुवाई करते रहे। इनके ओजस्वी भाषणों से प्रेरणा लेकर हजारों नवयुवक, स्त्री–पुरूष और बच्चे इस संघर्ष में कूद पड़े। जन सभाओं में लोग स्वामीजी का बेताबी से इंतजार करते थे। इनके पहुंचने पर लोग बम–बम भोले और भारत माता के गगनभेदी नारों से वातावरण को देशभक्ति से ओतप्रोत कर देते थे। स्वामी जी ने अनेक जन सभाओं का नेतृत्व किया, प्रदर्शनों की अगुवाई की और लोगों विशेषतया युवकों में पुलिस के जुल्मों का डटकर मुकाबला करने का उत्साह भरा। जम्मू के इतिहास में कभी किसी बड़े राजनेता ने भी इतनी बड़ी भीड़ को आकर्षित नहीं किया जितना स्वामी दिनेश भारती करते रहे। स्वामी जी की सक्रियता से प्रशासन और पुलिस परेशान हो उठे। आखिर प्रशासन ने स्वामी जी पर पी.एस.ए. लगा दिया।

मोबाइल से भाषण किया

स्वामी जी ने भूमिगत रहते हुये भी साम्बा में आयोजित एक जनसभा को मोबाइल फोन पर अपना भाषण सुनाकर लोगों में जोश भर दिया। स्वामी जी ने साम्बा की जनसभा के मंच पर बैठे संयोजक के मोबाइल फोन का नम्बर अपने मोबाइल पर मिलाकर भाषण शुरू किया और जनसभा के संयोजक ने अपने मोबाइल पर आ रही स्वामी जी की आवाज को लाउड स्पीकर के माध्यम से जनता को सुनाया। स्वामी जी ने मोबाइल फोन से ही लोगों से कहा– शहीदों की कुर्बानियां बेकार नहीं करेंगे, जमीन वापस लेकर ही संघर्ष समाप्त होगा। मोबाइल पर दिये जा रहे स्वामी जी के भाषण को प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अफसरों ने भी ध्यान से सुना। जनता के उत्साह में उस समय चौगुनी वृद्धि हुई जब स्वामी जी ने मोबाइल फोन पर ही जोर से कहा लाठी गोली खायेंगे और जनता ने कहा भूमि वापस लायेंगे। इस तरह स्वामी दिनेश भारती और अनेक अन्य संतों महात्माओं ने जनांदोलन की सफलता में अपना अमूल्य योगदान दिया।

पूरी ताकत से जुटे कश्मीरी पंडित

कश्मीर में व्याप्त पाकिस्तान समर्थित और समर्थक हिंसक अलगाववाद के सबसे ज्यादा शिकार हुये हैं। वे कश्मीरी हिन्दू जिन्हें अपने, घर, कारोबार, खेत–खलिहान और बाग बगीचे छोड़कर अपने ही देश के विभिन्न हिस्सों में विस्थापितों की जिंदगी व्यतीत करनी पड़ रही है। अपने असली घर कश्मीर से जबरदस्ती भगाये गये इन हिन्दुओं ने श्री अमरनाथ यात्रा संघर्ष समिति का समर्थन करते हुये अपनी पूरी शक्ति आंदोलन में झोंक दी। निरंतर 600 वर्षो तक कश्मीर में हिन्दू संस्कृति और स्वाभिमान की रक्षा करने वाले इस पंडित समाज ने बालटाल (कश्मीर) अमरनाथ यात्रियों को

जमीन दिलाने के लिए संघर्ष समिति के आंदोलनात्मक कार्यक्रमों में पूरी भागीदारी की।

पनुन कश्मीर के प्रवक्ता और उपाध्यक्ष शैलेन्द्र ऐमा ने कहा कि राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता पर आये संकट को सम्पूर्ण कश्मीरी पंडित समाज अच्छी तरह समझता है। इसलिए जम्मू, दिल्ली और देश के अन्य स्थानों पर कश्मीरी हिन्दुओं के जितने भी सक्रिय संगठन हैं वे सब इस आंदोलन के साथ खड़े हैं। पनुन कश्मीर, जम्मू कश्मीर विचार मंच, रूट्स इन कश्मीर इत्यादि संगठनों के कार्यकर्त्ता और सदस्य हजारों की संख्या में धरनों, प्रदर्शनों और जेल भरो कार्यक्रमों में भाग लेते रहे। इसी तरह पनुन कश्मीर के डा. अग्निशेखर ने बयान जारी कर कहा कि कुछ तत्व जम्मू के लोगों और कश्मीरी हिन्दुओं के बीच दरारें पैदा कर रहे हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है।

जम्मू और आसपास के इलाकों में बने विस्थापित शिविरों में रह रहे कश्मीरी पंडितों ने अपने इन शिविरों से निकलकर निकटवर्ती पुलिस थानों पर धरने देकर गिरफ्तारियां दीं। जेल भरो आंदोलन में भी हजारों कश्मीरी पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया। कश्मीरी पंडितों के अन्य नेताओं अमरनाथ वैष्णवी, अश्विनी कुमार चिरंगु, हीरा लाल चट्ठा, आर.एल. भट, प्रो. एम.एल. रैना, आर.के. रैणा, एच.एल. भट्ट और अशोक कंगन इत्यादि नेताओं ने कश्मीरी पंडितों का नेतृत्व संभाला और समस्त हिन्दू समाज के साथ मिलकर दो महीने तक जमीन वापसी के लिए संघर्ष करते रहे।

दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा संघर्ष समिति के निर्देशानुसार चक्का जाम, शिवमंदिरों में जलाभिषेक कार्यक्रमों, सार्वजनिक स्थानों पर दिये गये धरनों और जेल भरो सत्याग्रह में 15 हजार से ज्यादा कश्मीरी पंडितों ने भाग लिया। पंडित नेता एडवोकेट त्रिलोक राजदान और अजय भारती ने संघर्ष समिति के अनेक कार्यक्रमों विशेषतः पत्रकार सम्मेलनों को सम्पन्न करवाने में अपना विशेष योगदान दिया। इनके सहयोग से दिल्ली के समाचार पत्रों को संघर्ष समिति के आंदोलन की नियमित खबरें भेजने का कार्य बखूवी सम्पन्न हुआ।

पूर्व सैनिक सेवा परिषद का आंदोलन को समर्थन

जम्मू में आंदोलनरत संघर्ष समिति को अपना समर्थन देने के लिए अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का एक प्रतिनिधि मंडल जम्मू पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल के नेता सेवानिवृत ले.जनरल एच.एस. कंवर ने एक प्रैस सम्मेलन में कहा कि देश की एकता और अखण्डता के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। श्री अमरनाथ यात्रियों का मामला

देश के प्रत्येक जन से जुड़ा हुआ है। इस पवित्र यात्रा का संबंध न केवल हिन्दुओं के साथ अपितु समस्त देशवासियों के साथ है। जम्मू के लोग हाथों में तिरंगा झण्डा लेकर आंदोलन को चला रहे हैं। इसलिए यह आंदोलन केवल जम्मूवासियों का न होकर पूरे देशवासियों के स्वाभिमान के साथ जुड़ा हुआ है।

पूर्व सैनिकों के इस प्रतिनिधि मंडल ने सरकार को चेतावनी देते हुये कहा कि यदि संघर्ष लम्बा चला और पूरे देश में फैल गया तो उससे निकलने वाले भयंकर नतीजों के लिए जम्मू–कश्मीर और देश की दोनों सरकारें जिम्मेवार होंगी। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि वह राष्ट्रपति से मिलकर जम्मू में छिड़े इस राष्ट्रवादी जनांदोलन की सही तस्वीर पेश करेंगे। इस प्रतिनिधि मंडल में सेवानिवृत्त ले.जनरल कंबर के अलावा एयरमार्शल आर.सी. वाजपेयी, ब्रि. बी.डी. मिश्रा, कर्नल महेश गांधी, डा. ओम प्रकाश, डी.आई.जी महेन्द्र लाल, कर्नल आर.एस.त्रिपाठी, सीपीओ जय प्रकाश, एयर कोर कमांडर बी.के. गांधी, ग्रुप कैप्टेन के.एस. भट्टी, कर्नल के.एस. जुनेजा, कर्नल ए.एस. केर, कैप्टेन पुरुषोत्तम और ब्रिगेडियर एस.एस. सैनी शामिल थे।

जहां यह बताना जरूरी है कि श्रीअमरनाथ यात्रा संघर्ष समिति के नेता सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर सुचेतसिंह अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष हैं। उनके इस व्यापक संबंधों के कारण जम्मू–कश्मीर के दूर दराज के गांवों में रहने वाले हजारों पूर्व सैनिकों ने आंदोलन में भाग लिया। अनेकों गांवों में गठित संघर्ष समितियों की अगुवाई इन पूर्व सैनिक अफसरों ने की। हजारों पूर्व सैनिक जवानों ने संघर्ष समिति के आदेशानुसार गांव–गांव में आंदोलन का आधार बनाने में मुख्य भूमिका निभाई।

लेह–लद्दाख में भी जनांदोलन को मिला समर्थन

श्री अमरनाथ यात्रा संघर्ष समिति के झण्डे तले किये जा रहे इस धर्म रक्षक जनांदोलन का असर लेह–लद्दाख में भी हुआ। इस क्षेत्र में बौद्ध धर्मावलंबियों की संख्या 98 प्रतिशत है। यह लोग भी कश्मीरी अलगाववादियों के इस्लामिक जनून से दुःखी हैं। पिछले कई वर्षो से लेह–लद्दाख के लोगों के हितों के लिए संघर्ष कर रहे लद्दाख यूनियन टैरीटरी फ्रंट ने श्री अमरनाथ यात्रा संघर्ष समिति की ओर से चलाये जा रहे आंदोलन का भरपूर समर्थन किया। इस संगठन के उपप्रधान सेरिंग वेंगगूस ने एक बयान देकर कहा कि हम हिन्दू समुदाय के साथ हैं और हिन्दू संस्कृति के मान बिन्दुओं की रक्षा के लिए हर कुर्बानी देंगे। सेरिंग के अनुसार

देश के एक मात्र मुस्लिम बहुल प्रदेश जम्मू–कश्मीर में हिन्दुओं और बौद्धों के अधिकार सुरक्षित रहने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा जम्मू–कश्मीर के दो डिवीजनों लद्दाख और जम्मू पर कश्मीर के मुस्लिम नेताओं का दबदबा समाप्त होना चाहिए। पिछले 61 सालों से जम्मू व लद्दाख के लोग कश्मीरी नेताओं के पक्षपात का शिकार हो रहे हैं। श्री बाबा अमरनाथ धाम के मुद्दे पर छिड़े संघर्ष ने हिन्दुओं और बौद्धों को एक जुट होने का अवसर प्रदान किया है। लेह और लद्दाख के लोग हिन्दुओं को जमीन वापस देने की मांग का न केवल समर्थन करते हैं बल्कि संघर्ष में साथ देने का वादा भी करते हैं। अतः संघर्ष समिति के आह्वान पर आंदोलन के प्रायः सभी कार्यक्रम लेह–लद्दाख में सम्पन्न हुए।

भूख प्यास में भी हौंसले बुलंद

जम्मू संभाग के लोगों ने जिस तरह से भूखे प्यासे रहकर दो महीने तक इस धर्म युद्ध को चलाया है उससे आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा लेती रहेंगी। आंदोलन के मध्य पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी। दुकानें, उद्योग धंधे, छोटे–छोटे कारोबार सब बंद हो गये। सरकारी, गैर सरकारी दफ्तर, बैंक, डाकखाने, छोटे आर्थिक अदारे सब सुनसान पड़े थे। रेहड़ी खोमचे वाले, मेहनतकश मजदूर, नाई, धोबी, मोची इत्यादि सभी ने अपनी–अपनी कमाई के सहारों का ठप्प होना बर्दाश्त किया परन्तु क्षणभर के लिए भी निरुत्साही नहीं हुये। बम–बम भोले के नाद गुंजाते रहे। गरीब लोग भी गली मोहल्लों में जय शिवशंकर के जयकारों के साथ प्रदर्शन करते रहे। एक सरकारी अर्थशास्त्री के अनुसार दो महीनों में शहरों से गांवों तक समस्त आर्थिक कारोबार के बंद रहने से जम्मू संभाग को 26 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा है। सबसे दर्दनाक हालत उन गरीब और साधारण लोगों की हुई जो रोज कमाकर अपने बच्चों का पेट भरते थे।

जम्मू के रणवीरेश्वर मंदिर के सामने फूल बेचने वाली सोमा देवी ने कहा कि उसके तीन बच्चे हैं। पति आटोरिक्शा चलाता है। दो महीने से कोई कमाई नहीं की। मोहल्ले वालों ने मदद की है। बाकी थोड़ी सी जमा पूंजी समाप्त हो गई है। फिर भी हम अंतिम श्वांस तक इस संघर्ष में साथ देंगे। बाबा अमरनाथ की जमीन वापस मिलनी चाहिए। जम्मू की रैजीडेंसी रोड पर सरकारी डाक बंगले के सामने बैठकर भीख मांगने वाले एक अपाहिज व्यक्ति ने भी संघर्ष समिति के कार्यकर्त्ता को 51/-- रुपये देकर कहा कि आंदोलन को समाप्त मत करना। हम सब आपके साथ हैं। भोले बाबा के शत्रु एक दिन परास्त होंगे और शिवभक्तों की जीत होगी।

सार्वजनिक लंगरों की व्यवस्था

जम्मू क्षेत्र की जनता ने न केवल आंदोलन/सत्याग्रह में भाग ही लिया अपितु एक दूसरे को आर्थिक मदद और जीवन यापन की जरूरी वस्तुएं उपलब्ध करवाकर सामाजिक सौहार्द और एकता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। कर्फ्यू के दिनों में पुलिस और सेना ने गलियों के मोड़ों, सड़कों के नाकों और चौराहों पर कांटेदार तार लगाकर लोगों को घरों मे कैद कर दिया था। परन्तु लोगों ने गांवों, नगरों और शहरों के गली कूचों में ही छोटे–छोटे लंगर लगाकर बेसहारों और गरीब लोगों को खाना खिलाना शुरू कर दिया। इस तरह के लंगरों की व्यवस्था गांव–गांव तक लोगों ने अपने स्तर पर की। इन लंगरों में उन पुलिसकर्मियों और सैनिकों ने भी खाना खाया जिन्होंने बेकसूर आंदोलनकारियों पर लाठियां और गोलियां बरसायीं थीं।

अनेक शहरों, कस्बों और गांवों में चलाए गए हजारों छोटे–बड़े लंगरों में खाद्य सामग्री और धन की कोई कमी नही आई। जरूरतमंदों, गरीबों और साधुसंतों के लिए चले इन लंगरों के स्थानीय प्रबंधकों को सक्षम लोगों ने दिल खोल कर धन दिया। लंगरों की व्यवस्था को देखकर सैनिक अफसर भी आश्चर्यचकित रह जाते थे। बच्चे बूढ़े सब्जियां काटते थे। महिलायें चपातियां बनाती थीं युवा परोसते थे। इस तरह पूरे गली मोहल्ले के लोग लंगर सेवा और सत्याग्रह दोनों में योगदान देते रहे। संघर्ष समिति ने अस्पतालों और कुछ दवाई विक्रेताओं को अपना काम करने की अनुमति दे रखी थी। परन्तु कर्फ्यू के कारण अस्वस्थ लोग घरों से निकल नहीं सके। विश्व हिन्दू परिषद, सेवा भारती और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्त्ताओं ने घर–घर जाकर लोगों का कुशलक्षेम पूछा और योजनाबद्ध तरीके से दवाइयों की व्यवस्था की। कई डाक्टरों ने घर–घर जाकर बीमार लोगों की जांच की और यथासंभव अपने घरों से दवाइयां दीं। अधिक अस्वस्थ लोगों को निकटवर्ती अस्पतालों में पहुंचाने, इलाज करवाने और फिर घरों तक वापस पहुंचाने का कार्य भी संघ के स्वयंसेवकों ने संभाला।

उल्लेखनीय है कि जरूरतमंदों के लिए चलाये गये लंगरों में राशन और धन सभी वर्गों और पंथों के लोगों ने दिया। अनेक स्थानों पर मुसलमान भाइयों ने वाकायदा आग्रहपूर्वक अपने घरों से आटा दाल पहुंचाया। कई स्थानों पर रेहड़ी वालों और मजूदरों ने भी अपनी क्षमता अनुसार पैसा देकर इस धर्मयज्ञ में अपनी आहुति दी। 50 दिनों तक चले लगभग 250 लंगरों में लाखों लोगों ने भोजन किया। इन लंगरों में सचमुच ईश्वरीय सत्ता के दर्शन हो रहे थे। इस तरह बम–बम भोले के प्रति अटूट विश्वास और बर्फानी बाबा अमरनाथ के प्रति दृढ़ आस्था ने लोगों को दो महीने तक सरकारी जुल्म से जूझने की प्रेरणा दी।

राष्ट्रीय पर्वों पर उमड़ा देशभक्त जनसैलाब

संघर्ष समिति ने मनाया स्वतंत्रता दिवस

हिन्दुओं के अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलनरत श्रीअमरनाथ यात्रा संघर्ष समिति ने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर सम्पन्न होने वाले सरकारी समारोहों का बहिष्कार करने का निर्णय किया। परन्तु भारत का स्वतंत्रता दिवस एक राष्ट्रीय पर्व है। इसका सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का राष्ट्रीय कर्त्तव्य है। इसलिए संघर्ष समिति ने जम्मू संभाग के दूरदराज के गांवों तक अपने स्तर पर स्वतंत्रता दिवस सम्पन्न करने का निर्णय ले लिया। हिन्दुओं की आस्था पर आघात करने वाली सरकार का विरोध भी होना चाहिए और भारत का स्वतंत्रता दिवस समारोह भी पूरे हर्षोल्लास और उत्साह के साथ सम्पन्न होना चाहिए, इसी नीति के तहत जम्मू संभाग में प्रत्येक गांव तक गठित सभी संघर्ष समितियों को अपने-अपने स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराकर देशभक्ति के गीतों के साथ स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों के भाषण करवाने के निर्देश दिये गये।

संघर्ष समिति के आदेश का जम्मू क्षेत्र के देशभक्त नागरिकों ने अक्षरशः पालन किया। जम्मू की परेड ग्राउंड में आयोजित सरकारी समारोह में केवल पुलिस और सेना के जवान ही उपस्थित थे। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार स्कूल के बच्चे भी नहीं पहुंचे। पूरा मैदान सुनसान पड़ा था। उधर जम्मू की मुबारक मण्डी में संघर्ष समिति के नेतृत्व में सम्पन्न हुये स्वतंत्रता दिवस समारोह में एक लाख से ज्यादा लोग जुटे। स्कूलों के जिन बच्चों ने सरकारी समारोह में भाग लेना था उन्होंने संघर्ष समिति के समारोह में अपने गीत, नृत्य तथा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किये। संघर्ष समिति के संयोजक श्री लीलाकरण एडवोकेट ने राष्ट्रीय तिरंगा झण्डा फहराया। समिति के अन्य नेताओं के भाषण भी हुये। इसी तरह पूरे जम्मू संभाग के सभी कस्बों और गांवों में सरकारी समारोहों का पूर्णतः बहिष्कार किया गया। सभी स्थानों पर संघर्ष समितियों के संयोजकों ने स्थानीय सेवा निवृत्त सैनिक अफसरों और जवानों को साथ लेकर राष्ट्रीय ध्वज- तिरंगा फहराया और वंदेमातरम व जन-गन-मन राष्ट्रीय गीत गाये। संघर्ष समिति द्वारा गैर सरकारी स्तर

पर हुये स्वतंत्रता दिवस समारोहों में उमड़े देशभक्तों के सैलाब ने सुनसान पड़े सरकारी समारोहों को चुनौती थी। यह साबित हो गया कि जनता जनार्दन राष्ट्रवादी शक्तियों का प्रतीक है और उन्हीं के साथ है न कि हिन्दुत्व विरोधी सरकार के साथ।

रक्षाबंधन पर धर्मरक्षा की प्रतिज्ञा

16 अगस्त को श्रीअमरनाथ संघर्ष समिति के आह्वान पर पूरे जम्मू संभाग में रक्षाबंधन का उत्सव धर्मरक्षा दिवस के रूप में मनया गया। दूरदराज के गांवों तक संघ और विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकर्त्ताओं ने संघर्ष समिति के नेतृत्व में धर्मरक्षा प्रतिज्ञा कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस कार्यक्रम को शिवरक्षा संकल्प की संज्ञा दी गई। संघ द्वारा संचालित धर्मजागरण विभाग ने 10 लाख से ज्यादा रक्षासूत्र तैयार किये। रक्षासूत्रों की पूजा–अर्चना करके इन्हें मंदिरों में अभिमंत्रित किया गया। संघर्ष समिति ने एक शिवरक्षा संकल्प तैयार किया। प्रत्येक गांव तक यह संकल्प पत्र और रक्षासूत्र भेजे गये। प्रत्येक वर्ग, सरकारी कर्मचारी, दुकानदार, मजदूर, किसान, डाक्टर, वकील, इंजीनियर और सभी पंथों और बिरादरियों के लोगों ने एक दूसरे की कलाई पर रक्षासूत्र बांधते हुये प्रतिज्ञा दोहराई – "मैं पाक परस्त अलगाववादियों को पराजित कर श्रीअमरनाथ श्राइन बोर्ड को जमीन मिलने तक तन–मन–धन पूर्वक संघर्ष करने का संकल्प लेता/लेती हूं।" इस संकल्प ने आंदोलन को तेज करने और इस धर्मयज्ञ में आम नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने में अद्भुत योगदान दिया। इस प्रकार के प्रयासों से समाज का प्रत्येक वर्ग इस आंदोलन में शामिल होता चला गया और यह संघर्ष एक प्रबल जनांदोलन का रूप लेता चला गया। कई स्थानों पर जब बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी तो उन्होंने धन के बदले बाबा अमरनाथ की जमीन मांगी और भाईयों ने भी उन्हें जमीन दिलाने के लिए इस जनांदोलन में आखिरी श्वांस के रहते जूझने का आश्वासन दिया।

अभूतपूर्व श्रीकृष्ण जन्माष्टमी

पिछले 61 वर्षों में पहली बार जम्मू संभाग में जन्माष्टमी के अवसर पर लाखों लोग हाथों में तिरंगे झण्डे लेकर कृष्ण कन्हैया की शोभा यात्रा में अपने बच्चों के साथ शामिल हुये। हाथी घोड़ा पालकी– जय कन्हैया लाल की, जय श्रीकृष्ण – बम–बम भोले, जय शिव शंकर, बच्चा–बच्चा राम का – अमरनाथ के काम का, लाठी गोली खायेंगे–भूमि वापस लायेंगे, नहीं झुकेंगे नहीं झुकेंगे–जुल्म के आगे नहीं झुकेंगे इत्यादि राष्ट्रीय और हिन्दुत्वनिष्ठ उद्घोषों

ने वातावरण को राष्ट्रीयता और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कर दिया। नंदगोपाल के भक्ति के गीतों ने समा बांध दिया। जम्मू शहर के प्रसिद्ध श्री रघुनाथ मंदिर से निकली शोभायात्रा में 2 लाख से अधिक लोग शामिल हुये। महिलाएं भगवा रंग की साड़ियां पहने हुई थीं। बच्चों ने बालगोपाल का रूप धारण करके अपने हाथों में सुदर्शन चक्र पकड़े हुये थे। जवानों ने शिव का रूप बनाकर हाथों में त्रिशूल थामे हुये थे। अनेक भक्तों ने भगवान राम का स्वरूप बनाकर हाथों में धनुषबाण उठाये हुये थे। ऐसा लग रहा था मानो भगवान श्रीकृष्ण, श्रीराम और शिवशंकर स्वयं शोभा यात्रा में उपस्थित होकर देशभक्त जम्मूवासियों को हिन्दुत्व की रक्षा के लिए छिड़े संघर्ष में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हों।

राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के साथ भारत माता की जय के जयकारों ने हिन्दुओं की संगठित शक्ति को उभारने का ऐतिहासिक काम किया। पुलिस और सेना के जवान हथियारों के भारी अमले के साथ शोभा यात्रा के साथ–साथ और आगे–पीछे चल रहे थे। आज उनकी हिम्मत नहीं हुई कि शोभा यात्रियों को किसी प्रकार भड़का कर हालात को खराब करें और लाठियों और गोलियां का सहारा लेकर शोभा यात्रा को तितर–बितर कर दें। इससे पहले यह पुलिसकर्मी सरकार के इशारे पर छोटे–छोटे जलसे जलूसों को इसी प्रकार अस्त व्यस्त करने की कोशिश करते रहे। 4 किमी. लम्बी इस शोभा यात्रा के समय राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सौहार्द के उदाहरण भी प्रस्तुत हुये। स्थान–स्थान पर मुसलमान भाइयों ने शोभा यात्रा का स्वागत करके राष्ट्रवाद के इस यज्ञ में अपना हिस्सा डाला। इस सारे दृश्य को देखकर हिन्दू विरोधी शक्तियां खासकर पाकिस्तान समर्थक अलगाववादियों की नींद उड़ गई। श्री अमरनाथ धाम और अमरनाथ यात्रा के ऊपर आये इस्लामिक संकट और सरकार की घुटने टेक नीति के खिलाफ हिन्दुओं के प्रचंड रोष की स्पष्ट झलक शोभा यात्रा में दिखाई दे रही थी। ऐसे ही राष्ट्रवादी वातावरण का प्रगटीकरण जम्मू संभाग के प्रत्येक शहर, कस्बे और गांव में हुआ।

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी शोभायात्रा में चल रहे एक 92 वर्षीय वृद्ध मुकंदलाल मंगोत्रा से एक पत्रकार ने पूछा – क्या आप पुलिस की लाठियों की मार और जेल जाने से नहीं डरते? तो उस वृद्ध ने गर्दन उंची करके थोड़ा गुस्से में आकर उस पत्रकार से कहा – "आप डरते होंगे, हम नहीं डरते" क्या आपको पता नहीं कि हम आज जिस भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी मना रहे हैं उनका तो जन्म ही जेल में हुआ था। जन्म से लेकर अंत तक भगवान कृष्ण आतताई शक्तियों से लोहा लेते रहे और अंत में दुष्ट शक्तियों पर सज्जन शक्तियों की विजय करवाकर अपने अवतार धारण के उद्देश्य की पूर्ति की। बर्फानी भोले बाबा की जमीन वापस लेने के लिए जब छोटे–छोटे बच्चें संघर्ष कर रहे हैं तो मैं इस संघर्ष में क्यों न कूदूं।

ऐतिहासिक जेल भरो आंदोलन

राष्ट्रहित में भी मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति से बाज न आने वाली केन्द्र की कांग्रेस सरकार और उसके एजेंट राज्यपाल एन.एन. वोहरा के अड़ियल रुख को देखते हुये श्री अमरनाथ यात्रा संघर्ष समिति ने विशाल जेल भरो आंदोलन का आयोजन किया। 18 अगस्त से 20 अगस्त तक तीन दिन तक चले इस आंदोलन में जम्मू क्षेत्र के 11 लाख से भी ज्यादा लोगों ने गिरफ्तारियां दीं। जम्मू संभाग की जनसंख्या लगभग 40 लाख है। लिहाजा प्रत्येक चौथा व्यक्ति आंदोलन में भाग लेकर जेल में गया। हिन्दुत्व की रक्षा के लिए आम नागरिक का जज्बा देखकर सरकार, प्रशासन और पुलिस के होश उड़ गये।

पहले दिन 3.50 लाख लोग गिरफ्तार

18 अगस्त को जेल भरो आंदोलन शुरू हुआ। पहले ही दिन तीन लाख से ज्यादा लोगों ने गिरफ्तारीयां दीं। जम्मू शहर और जम्मू क्षेत्र के कस्बों और गांवों में हजारों की संख्या में लोग घरों से निकले और भारत माता की जय के नारे लगाते हुये निकटवर्ती थानों पर पहुंच गये। पुलिस और प्रशासन के इंतजाम कम पड़ गये। पूरे क्षेत्र में सैकड़ों स्कूलों और धर्मशालाओं को जेलों में तबदील कर दिया गया। इन अस्थाई जेलों में बैठने, भोजन करने इत्यादि का कोई बंदोबस्त नहीं था। किसी भी थाने में गिरफ्तार हुये आंदोलकारियों को रजिस्टर करने जैसी व्यवस्था नहीं थी। जम्मू संभाग के सभी स्थानों पर बनी स्थानीय संघर्ष समितियों के नेताओं के नेतृत्व में सत्याग्रहियों ने गिरफ्तारियां दीं। अस्थाई जेल में तबदील जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में गिरफ्तार किये गये लगभग 40 हजार सत्याग्रहियों ने भोजन और पानी की सुविधाएं न मिलने के कारण प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और भूखहड़ताल शुरू कर दी। गिरफ्तारी देने पहुंचे लोगों ने थानों का घेराव करके शिव भोले के भजन गाने शुरू कर दिये।

थाने पर कब्जा

जम्मू क्षेत्र के कठुआ, साम्बा, कटड़ा, रियासी, बसोहली, हीरानगर, लखनपुर, भद्रवाह, किश्तवाड़, इत्यादि स्थानों पर सत्याग्रहियों ने गिरफ्तार न किये जाने पर पुलिस स्टेशनों का दिन भर घेराव किया और अंत में पुलिस ने अस्थाई टैंटों की व्यवस्था करके उन्हें गिरफ्तार करके फिर छोड़ दिया। ऊधमपुर जिले में पुलिस ने सत्याग्रहियों पर आंसू गैस के



तीय अस्मिता
रक्षा करेंगे

विजय रैली की ओर बढ़ते लोग



विजय रैली में जाते हुये लाखों महिलाओं और पुरुषों को पुलिस ने बलपूर्वक रोक दिया



तवी नदी को पार करके विजय रैली स्थान की ओर जाते युवक

गोले छोड़कर उन्हें वापिस घरों में जाने के लिए विवश करने की कोशिश की। फिर भी सुरक्षा घेरे को तोड़कर लोग थानों के अंदर घुस गये। मजबूर होकर पुलिस ने सबको गिरफ्तार कर लिया। दोपहर 12 बजे के बाद धार्मिक और सामाजिक संगठनों के नेताओं के नेतृत्व में फिर लोगों ने इकट्ठे होकर स्थानीय थानों को घेर लिया। थाने पर पुलिस और सीआरपीएफ के जवान सैकड़ों की संख्या में तैनात थे। पुलिस ने अश्रु गैस के गोले दागे, लाठी चार्ज किया। लाठीचार्ज में सात युवक गंभीर रूप से घायल हो गये। आंदोलकारियों ने थाने पर कब्जा कर लिया। डीआईजी पुलिस की दखल अंदाजी पर लोग शांत हुये। पुलिस ने सभी आंदोलकारियों को बसों में बिठाकर पीजी कालेज में बनी अस्थाई जेल में भेज दिया। पूरे जम्मू क्षेत्र में आज का सत्याग्रह संघर्ष समिति की आशाओं से कहीं ज्यादा सफल रहा।

दुर्गा बनी जम्मू की नारियां

माताओं बहनों का अविस्मरणीय सत्याग्रह

जेल भरो आंदोलन के दूसरे दिन गिरफ्तारियां देने की बारी महिलाओं की थी। जम्मू संभाग के प्रत्येक शहर और कस्बे और गांव के गली मोहल्लों में माताएं–बहनें हाथों में त्रिशूल और तिरंगे लेकर निकलीं और यहीं से छोटे–छोटे जत्थों के रूप में "हम भारत की नारी हैं–फूल नहीं चिंगारी हैं" इत्यादि नारे लगाते हुये पुलिस थानों की ओर बढ़ीं। पूरे क्षेत्र में 2.50 लाख महिलाएं सत्याग्रह करती हुई गिरफ्तार हुई। अकेले जम्मू में एक लाख से ज्यादा महिलाएं जेलों में गई। प्रशासन को महिला पुलिस की कमी महसूस हुई। महिलाएं अस्थाई जेलों में शाम तक भोले बाबा के भजन गाती रहीं। तिरंगे झण्डे फहराती रहीं। महिलाओं ने "देशद्रोहियों कश्मीर छोड़ो" जैसे उद्घोष करके जेलों की दीवारें हिला दीं। जम्मू के नगरोटा और ऊधमपुर थानों में गिरफ्तारी देने वाली महिलाओं ने पुलिस का भोजन खाने से इनकार कर दिया। ऊधमपुर जिला पुलिस थाने पर लगभग 13 हजार महिलाओं ने सत्याग्रह किया। इन महिलाओं ने सुरक्षा घेरे को तोड़कर थाना परिसर में प्रवेश किया। पुलिस अफसर और जवान भाग खड़े हुये। ऊधमपुर में सत्याग्रह करने वाली महिलाओं के एक जत्थे का नेतृत्व स्थानीय मुस्लिम महिला शकीना बानो ने किया। जम्मू में महिलाओं के सत्याग्रह के समर्थन में बार एसोसिएशन ने भी अपने अध्यक्ष भोपेन्द्र सिंह सलाथिया एडवोकेट की अगुवाई में सत्याग्रह किया। जिसमें 600 वकीलों ने गिरफ्तारियां दीं।

इससे पहले इन वकीलों ने शहर में स्कूटर रैली निकाल कर लोगों को सत्याग्रह में शामिल होने का आह्वान किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार इस दिन के सत्याग्रह में 2.50 लाख महिलाओं समेत 4 लाख लोगों ने गिरफ्तारियां दीं।

एक नेत्रहीन वृद्ध महिला ने गिरफ्तारी दी

जम्मू के निकटवर्ती एक छोटे कस्बे बड़ी ब्राहम्णा में सत्याग्रही महिलाओं का नेतृत्व एक नेत्रहीन 56 वर्षीय महिला बीना देवी ने किया। यह महिला सत्याग्रही महिलाओं के आगे–आगे दो बच्चों के कंधों का सहारा लेकर चल रही थी। इस छोटे कस्बे की लगभग 1800 महिलाओं का जोश देखते ही बनता था। थाना परिसर के बाहर खड़े होकर इन महिलाओं ने ''लाठी गोली खायेंगीं–भूमि वापस लायेंगी'' और ''बम–बम भोले'' के नारों के साथ थाने का घेराव कर लिया। यहां भी पुलिसकर्मी थाना छोड़ कर भाग गये। सत्याग्रही महिलायें थाना परिसर में घुसीं और दिन भर भोले बाबा का कीर्तन करती रहीं। 5 घण्टे तक कोई भी पुलिसकर्मी उन्हें गिरफ्तार करने नहीं पहुंचा। महिलायें नारे लगाती हुई अपने घरों को वापस आ गईं।

लड़की ने 80 फुट ऊंचे टावर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया

जम्मू शहर के बीचोबीच स्थित सिटी पुलिस थाने के परिसर के बाहर बीएसएनएल का एक 80 फुट ऊंचा टावर बना है। करीब 30 हजार महिलायें इस पुलिस स्टेशन के बाहर सत्याग्रह करने पहुंची तो पुलिस और सेना के जवान हक्के–बक्के रह गये। हाथों में तिरंगे लिये इन महिलाओं ने थाने को घेर लिया। एक लड़की अनीता शर्मा का ध्यान बीएसएनएल के टावर पर पहुंचा। वह हाथ में तिरंगा झण्डा लेकर भारत माता की जय के नारे लगाती हुई इस टावर पर चढ़ गई। अनीता ने टावर के शिखर पर तिरंगा झण्डा लहरा दिया। जैसे ही इस अद्‌भुत और साहसिक दृश्य पर आंदोलनकारी महिलाओं की नजर पड़ी वे ऊंची आवाज में बम–बम भोले का नाद करने लगीं। पुलिस और सेना के जवान देखते रह गये। उनमें हिम्मत नहीं थी कि अनीता को कैसे गिरफ्तार करें। पुलिस अधिकारियों के कहने पर भी अनीता नीचे नहीं उतरी। उसने झण्डे को टावर के शिखर के साथ अपनी चुन्नी से बांध दिया। संघर्ष समिति के नेता सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर सुचेतसिंह के कहने से वह नीचे उतरी।

बच्चों के जोश ने उड़ाये होश

1.50 लाख बच्चों ने सत्याग्रह किया

जमीन वापसी के लिए शुरू हुये जेल भरो सत्याग्रह के तीसरे दिन जम्मू क्षेत्र के बच्चों ने राष्ट्रभक्ति के जज्बे का अद्भुत परिचय दिया। यह इस आंदोलन के इतिहास का एक स्वर्णिम पृष्ठ माना जायेगा। बच्चों की गिरफ्तारी को असंवैधानिक घोषित करने के और पूरे जम्मू क्षेत्र में कर्फ्यू लगाने के बावजूद भी सेना और पुलिस बच्चों को गिरफ्तारी देने के लिए आगे बढ़ने से रोक नहीं सकी। वृद्ध और जवान माता पिता अपने बच्चों को कंधों और सिर पर बिठाकर अपने गली मोहल्लों से निकले और छोटे-छोटे समूहों में नारे लगाते हुये पुलिस थाने पर पहुंचे। सभी बच्चे भगवान शंकर, कृष्ण और राम का रूप धारण किये हुये थे।

हाथों में त्रिशूल, धनुष और सुदर्शनचक्र पकड़कर जलूस निकालते हुये बच्चों का उत्साह देखते ही बनता था। कई बच्चियों ने धरती माता और दुर्गा माता का रूप धारण किया हुआ था। बच्चे ऊँची आवाज में ''हमारी भूमि वापस दो'', ''वंदे मातरम'', ''हम बच्चे हैं राम के -अमरनाथ के काम के'' और ''बम-बम भोले'' जैसे जयघोष कर रहे थे।

भारत माता की जय और बम-बम भोले के जयघोष करते हुये बच्चों और उनके अभिवावकों की भीड़ से जम्मू क्षेत्र के सभी थाने और स्थाई जेलें खचाखच भर गईं। गिरफ्तारी देने आये बच्चों में कई दुधमुहें बच्चे भी शामिल थे जो अपनी माताओं की गोद मे थे। इस अवसर पर अनेक छोटे बच्चों ने अपनी तोतली भाषा में कविताएं सुनाई और नारे लगाये। बच्चों के साथ-साथ स्कूल और कालेज के हजारों छात्रों ने भी सत्याग्रह किया।

कई स्थानों पर बच्चों के लिए खाने-पीने और ठीक ढंग से बैठने का इंतजाम न होने के कारण बच्चों ने हगांमा खड़ा कर दिया। पुलिस बच्चों के इस उत्पात से परेशान हो गई और दिनभर उनको चुप कराने में लगी रही। बड़ी ब्राहम्णा पुलिस स्टेशन में अपनी मां के साथ गिरफ्तारी देने पहुंचा सात माह का हर्षित पुलिसकर्मियों के आकर्षण का केन्द्र बन गया। यह बच्चा बोतल से दूध पी रहा था।

माताओं की गोद में थे दुधमुहें बच्चे

जम्मू के निकट साम्बा में गिरफ्तारी देने पहुंचे बच्चों में से एक छोटे 6 वर्षीय बच्चे भारत ने मेज पर खड़े होकर भाषण दिया। जब तक हमें भोले शंकर की जमीन वापस नहीं मिल जाती हम चुप नहीं बैठेंगे। कटड़ा और रियासी में मुस्लिम परिवारों के सैकड़ों बच्चों ने अपनी बुर्काधारी माताओं के साथ सत्याग्रह में भाग लिया।

आज पूरे जम्मू संभाग में गिरफ्तारियां देने वाले बच्चों के साथ उनके अविभावकों की तादाद 4 लाख से ज्यादा रही। कई स्थानों पर दादा–पोते एक साथ सत्याग्रह करने के लिए आये। जम्मू शहर में लगभग 10 हजार वृद्ध स्त्री–पुरुष सत्याग्रहियों का नेतृत्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व प्रांत संघचालक 94 वर्षीय डा. ओम प्रकाश मैंगी ने किया। डा. मैंगी 1953 में हुये प्रजा परिषद के आंदोलन का नेतृत्व करने वाले नेता हैं। आज के सत्याग्रह में जम्मू कश्मीर के हजारों पूर्व सैनिकों ने भी गिरफ्तारियां दी।

एक बच्चे ने अपनी गुल्लक संघर्ष समिति को दी

जेल भरो आंदोलन के अंतिम दिन अनेक बच्चों ने अपनी कई महीनों की जेब खर्ची संघर्ष समिति को आंदोलन जारी रखने के लिए दी। जम्मू के निकट सैनिक कालोनी में रहने वाले बच्चे अपनी–अपनी गुल्लकों के साथ सत्याग्रह करने पहुंचे। लगभग 250 बच्चों के इस समूह ने अपनी पैसों से भरी गुल्लकें संघर्ष समिति के स्थानीय नेता को सौंप दीं।

12 वर्षीय प्रकृति जम्वाल ने कुर्सी पर खड़े होकर भाषण दिया कि इस आंदोलन के दौरान हमारे गरीब भाई भूखे–प्यासे रह रहे हैं। उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम जम्मू के बच्चे उनके साथ हैं। उनको भोजन खिलाने के लिए हम अपनी गुल्लकें संघर्ष समिति को दे रहे हैं। बच्चों ने यह भी कहा कि हमारी पढ़ाई के दिन हैं लेकिन इस धर्मयुद्ध में हम जम्मू के लोगों के साथ हैं। इतना सुनते ही सभी बच्चों ने हमारी जमीन वापस दो के नारों से आकाश को गुंजा दिया।

देशभक्ति की कसौटी पर संघर्ष समिति

जम्मू के राष्ट्रभक्त लोगों की एकता और उनकी हिन्दुत्व निष्ठा को देखकर अलगाववादी संगठनों और उनके आका पाकिस्तान की छाती पर सांप लौटने लगे। जम्मू क्षेत्र में सफलता की ओर बढ़ रहे राष्ट्रवादी आंदोलन को विफल करने और कश्मीर में सक्रिय पाकिस्तान समर्थक अलगाववादियों के गिरते हौंसले बुलंद करने के लिए पाकिस्तान ने 26 अगस्त की रात को जम्मू के निकट अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फायरिंग शुरू करके सशस्त्र घुसपैठियों को जम्मू शहर तथा आसपास के इलाकों में हिंसा फैलाने के उद्देश्य से धकेला। भारतीय सेना ने यद्यपि घुसपैठ की कोशिश को विफल किया तो भी कुछ घुसपैठिये भारतीय क्षेत्र में घुसने में सफल हो गये। इन घुसपैठियों ने मिश्रीवाला में चार लोगों की हत्या करने के बाद जम्मू के चिन्नौर इलाके के एक घर में घुसकर बच्चों समेत परिवार के 7 लोगों को बंधक बना लिया। सुरक्षा जवानों ने 18 घण्टे की सैनिक कार्यवाही के बाद घर में घुसे तीनों घुसपैठियों को मार गिराया। जम्मू क्षेत्र में घुसने वाले पाकिस्तानी आतंकियों की संख्या का तो पता नहीं चला परन्तु इनके असली उद्देश्य को समझकर संघर्ष समिति ने अपनी प्रस्तावित विशाल रैली को स्थगित कर दिया। समिति के नेता सेवानिवृत्त ब्रि. सुचेतसिंह ने बयान जारी करके राष्ट्रीय संकट की इस घड़ी में सरकार और सेना का साथ देने की घोषणा की।

देश की सुरक्षा सर्वोपरि

पूर्व निश्चयानुसार जम्मू में एक विशाल विरोध रैली का आयोजन होने वाला था। जम्मू क्षेत्र के कोने कोने से 10 लाख से ज्यादा लोग इस रैली में भाग लेने के लिए आ रहे थे। बसों, ट्रकों, टैम्पुओं से पहुंचने वाले लाखों लोगों के खाने-पीने की व्यवस्था जम्मू शहर के लोगों ने की थी। प्रत्येक घर में दो-दो लोगों के भोजन का पैकट तैयार था। यह रैली सरकार को अंतिम चेतावनी देने के लिए सम्पन्न होने वाली थी। परन्तु पाकिस्तानी आतंकियों के शहर में घुसने से सरकार, सेना और पुलिस को शहरवासियों के सहयोग की जरूरत थी। इसलिए पाकिस्तान की इस गैरइन्सानी और भारत विरोधी हरकत को नाकाम करने के लिए संघर्ष समिति ने अपनी रैली स्थगित कर दी। समिति के अध्यक्ष श्री

लीलाकरण शर्मा एडवोकेट ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि हम देशभक्त हैं, समाज और देश की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। आतंकियों को खोजने और उनका सफाया करने में हम सरकार और सेना का साथ देंगे। संघर्ष समिति के इस फैसले ने सेना का दिल जीत लिया। गौरतलब है कि यदि यह आतंकी कश्मीर में घुसे होते तो अलगाववादियों ने उन्हें आश्रय देकर उनके उद्देश्य की पूर्ति में मदद की होती। वास्तव में कश्मीर में व्याप्त आतंकवादियों की सफलता का यही रहस्य है। उल्टा कश्मीर में तो आतंकियों के साथ जूझने वाले भारतीय सैनिकों और पुलिस जवानों के रास्ते में रोड़े अटकाने और उनके काफिलों पर हमले करने का काम होता है। वहां तो भारतीय सैनिक विदेशी हमलावर माने जाते हैं।

सैनिकों का दिल जीता

इधर जम्मू में प्रचंड जनांदोलन के दौरान भी भारतभक्ति और समाज सेवा को कायम रखा गया। जब चिन्नौर में भारतीय सैनिक आतंकियों से जूझ रहे थे उस समय संघर्ष समिति के आदेश पर स्थानीय लोगों ने उनका साथ दिया। संघर्ष समिति को जब यह पता चला कि सैनिकों ने दिन भर खाना नहीं खाया है तो तुरंत उनके लिए खाद्य समग्री भिजवाई गई। पूरे क्षेत्र में जितने भी सैनिक, पुलिस के जवान और प्रभावित लोग भूखे थे सबको भोजन के पैकट दिये गये। यहां तक कि इस आतंकी घटना की कवरेज करने पहुंचे पत्रकारों को भी वकायदा जलपान और भोजन करवाया गया। जम्मू की जनता ने भारतीय सैनिकों का सम्मान करते हुए अपने राष्ट्रीय कर्त्तव्य की पूर्ति की। एक सैनिक अफसर ने अपना नाम न बताते हुए पत्रकारों से कहा कि हम भी भारतीय हैं और मैं तो हिन्दू हूं। मैं भी श्री अमरनाथ भगवान के प्रति पूरी आस्था और श्रद्धा रखता हूं। परन्तु हमें भी अपना सैनिक कर्त्तव्य निभाने के लिए कई बार सख्ती का सहारा लेना पड़ता है।

इस तरह सैनिकों, पुलिस जवानों और पत्रकार भाइयों को भोजन करवाने का सिलसिला पूरे जम्मू संभाग में चला। यही वजह थी कि सरकार के इशारे पर जो सैनिक और पुलिसवाले आंदोलनकारियों पर एकतरफा जुल्म कर रहे थे उनके मन में भी शांत सत्याग्रहियों के साथ हमदर्दी उत्पन्न हुई। वे शर्मसार भी हुये। परन्तु सरकार विशेषतः तानाशाह राज्यपाल के इशारे पर अत्याचारों की झड़ी लगा रहे बड़े-बड़े पुलिस अधिकारी बाज नहीं आये। उन्होंने अपनी एकतरफा कूरता का प्रदर्शन करते हुये सख्त से सख्त कार्यवाही करने के आदेश जारी रखे।

इतने पर भी जम्मू के लोग डिगे नहीं, घबराये नहीं, झुके नहीं।

सरकार के साथ हुई तीनों वार्ताएं विफल

उम्मीद के विपरीत जम्मूवासियों के एकजुट आक्रोश से संभवतया पहली बार घबरा कर राज्यपाल एन.एन. वोहरा ने संघर्ष समिति को बातचीत का न्यौता भेजा। 31 जुलाई, 9 अगस्त और 23 अगस्त को राज्यपाल के पैनल के साथ संघर्ष समिति के कोर ग्रुप के साथ हुई तीनों वार्ताएं विफल रहीं। अमरनाथ श्राइनबोर्ड को दी जाने वाली 800 कनाल भूमि के संबंध में सरकार टालमटोल करती रही । संघर्ष समिति के पक्के रुख को भांपकर सरकारी पैनल ने यह कहकर बातचीत को समाप्त कर दिया कि यह मामला राज्यपाल के सामने रखा जायेगा और दो दिन के भीतर ही समस्या सुलझ जायेगी।

उल्लेखीय है कि बातचीत के पहले दो दौरों में संघर्ष समिति के कोर ग्रुप ने जमीन वापसी के अलावा पुलिस द्वारा की गई फायरिंग की न्यायायिक जांच करवाने, दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्यवाही करने, प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने जैसी मांगे भी रखीं परन्तु मुख्य मुद्दा श्राइनबोर्ड को जमीन वापसी का ही रहा। इस तरह संघर्ष समिति ने जमीन वापसी को लेकर अपने प्रस्ताव सरकारी पैनल को सौंप दिये। अब गेंद केन्द्र सरकार और जम्मू–कश्मीर के राज्यपाल के पाले में थी।

अपनी मांगों पर अडिग रही संघर्ष समिति

इस वार्त्तालाप में जमीन वापसी के प्रायः सभी पक्षों पर चर्चा हुई। मंत्रीमण्डल के आदेश और न्यायालय के अंतरिम आदेश और गुलामनबी की सरकार द्वारा अमरनाथ यात्रा की व्यवस्था जैसे विषयों पर खुलकर चर्चा हुई। संघर्ष समिति के सदस्य अपने इस फैसले पर डटे रहे कि जमीन को तुरंत वापस किया जाये अन्यथा जनांदोलन जारी रखा जायेगा। संघर्ष समिति के नेताओं ने सरकारी पैनल से यह भी कहा कि हमारे सभी प्रस्तावों को सरकार रद्दी की टोकरी में फेंक रही है। अगर यही दोगला व्यवहार जारी रहा तो हम अगले दौर की वार्त्ता में शामिल नहीं होंगे। संघर्ष समिति के अध्यक्ष श्री लीला करण शर्मा एडवोकेट ने बाहर इंतजार कर रहे पत्रकारों से कहा कि समिति के नुमांइदों ने

राज्यपाल से बालटाल में श्राइन बोर्ड को जमीन वापस सौंपने और बोर्ड को सशक्त बनाकर इसका पुराना अस्तित्व बहाल करने की मांग की थी। इन मांगों का कोई उत्तर सरकार ने नहीं दिया। फिर क्यों राज्यपाल और उसके पैनल से बात की जाये? इसके साथ ही संघर्ष समिति आंदोलन की अगली रूपरेखा तैयार करने में जुट गई।

आखिर झुक ही गई सरकार

इस प्रकार तीन बार हुई वार्त्ताओं में सरकार ने संघर्ष समिति को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। सरकार चाहती थी कि किसी प्रकार संघर्ष समिति द्वारा जनांदोलन वापस ले लिया जाये अथवा सरकारी ताकत के बल पर और आंदोलनकारियों में फूट डलवा कर संघर्ष को विफल कर दिया जाये। परन्तु संघर्ष समिति सरकार के किसी झांसे में नहीं आई। लाखों लोगों द्वारा संघर्ष में बढचढ़ कर भागीदारी करने से संघर्ष समिति के नेता पूरे उत्साह में थे और अपनी मांगों पर अड़े रहे। संघर्ष समिति के नेताओं, कार्यकर्त्ताओं और आम जनता के इस दृढ़ निश्चय की खबरें खुफिया विभाग द्वारा सरकार तक पहुंचती रहीं।

जम्मू में शुरू हुये इस प्रखर जनांदोलन को देश के अन्य हिस्सों में फैलता देखकर प्रदेश और केन्द्र की सरकारों ने श्रीअमरनाथ यात्रा संघर्ष समिति के आगे समर्पण करने का मन बना ही लिया। उधर भारतीय जनता पार्टी ने हिन्दुत्व के इस ज्वलंत मुद्दे को भारत के कोने–कोने में ले जाकर देशव्यापी आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया। भाजपा नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी ने बाबा अमरनाथ से संबंधित जमीन पर छिड़े आंदोलन को पूर्व में हुये श्रीरामजन्म भूमि आंदोलन और रामसेतु रक्षा आंदोलन के साथ जोड़ दिया। भाजपा के इस संभावित जनांदोलन के कड़े स्वरूप को भांपकर प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने राज्यपाल और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को दिल्ली बुलाकर एक बैठक की और संघर्ष समिति की मांगे मान लेने के निर्देश दे दिये।

निरंकुश राजसत्ता झुकी हिन्दू स्वाभिमान की जीत

श्री अमरनाथ यात्रियों की सुविधा के लिए कश्मीर में अस्थाई रूप से दो महीने के लिए मात्र 100 एकड़ जमीन प्राप्त करने के उद्देश्य से जम्मू समेत पूरे देश के हिन्दू समाज को 63 दिन तक निरंतर संघर्ष करना पड़ा। इस संघर्ष के दौरान जम्मूवासियों को 26 हजार 775 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। आखिर अनेक प्रकार की कुर्बानियां देने के बाद हिन्दुओं के स्वाभिमान की जीत हुई। जम्मू–कश्मीर के डोगरों की संगठित शक्ति के आगे राजसत्ता को झुकना पड़ा।

प्रदेश और केन्द्र की सरकारों के साथ हुई अनेक वार्ताओं के विफल होने के पश्चात अंत में 31 अगस्त की रात को राज्यपाल के पैनल और संघर्ष समिति की कोर टीम में ऐतिहासिक समझौता हो गया। दो महीने तक जम्मूवासियों के हौंसले को चुनौती देकर पुलिसिया कहर को खुली छूट देने वाले राज्यपाल एन.एन. वोहरा के पैनल ने श्रीअमरनाथ यात्रा संघर्ष समिति की सभी मांगों को स्वीकार कर लिया। राज्यपाल द्वारा गठित पैनल की अध्यक्षता मुख्य सचिव एस.एस. बिलोरिया ने की जिसमें जम्मू विश्वविद्यालय के उपकुलपति अमिताभ मट्ट, जस्टिस जी. डी. शर्मा बी.बी. ब्यास शामिल थे। उधर संघर्ष समिति की कोर टीम की अध्यक्षता समिति के प्रवक्ता एडवोकेट तिलक राज शर्मा ने की। जिसमें सेवा निवृत्त ब्रिगेडियर सुचेतसिंह, नरेन्द्र सिंह, पूर्व तहसीलदार पवन कोहली शामिल थे।

दोनों पक्षों में रात्रि 9 बजे स्थानीय सरकारी गैस्ट हाउस में वार्त्तालाप हुआ जो रात्रि 12.30 बजे तक चला। सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। सरकारी पैनल ने संघर्ष समिति के कोर ग्रुप को कुछ ठोस प्रस्ताव सौंपे। कोर ग्रुप के सदस्य इन प्रस्तावों को लेकर संघर्ष समिति से वार्त्ता करने चले गये। संघर्ष समिति ने पैनल के प्रस्तावों को उचित और सकारात्मक पाया। तब समिति के संयोजक लीलाकरण शर्मा समेत 22 सदस्य कोर ग्रुप के साथ सरकारी गैस्ट हाउस में पहुंच गये। संघर्ष समिति की मांगों पर फिर विचार विमर्श हुआ। सरकारी पैनल ने सभी मांगों को थोड़ी खुशी और थोड़ी हिचकिचाहट के साथ स्वीकार कर

लिया। रात्रि 4.30 बजे दोनों पक्षों में समझौता हो गया। सरकारी पैनल के अध्यक्ष और संघर्ष समिति के संयोजक ने इस ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये।

समझौते के मुख्य बिन्दू

क. राज्य सरकार परंपरागत वार्षिक यात्रा के लिए बालटाल व दोमेल में 800 कनाल जमीन उपलब्ध करायेगी जिसका इस्तेमाल केवल श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के द्वारा होगा। (कम्पार्टमेंट नं. 63/5, सिंध फारेस्ट डिवीजन)

ख. जमीन के मालिकाना हक, टाईटल और स्टेटस में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

ग. बोर्ड उपरोक्त भूमि को यात्रा अवधि के दौरान (व्यवस्था करने व समेटने की अवधि भी इसमें शामिल है) विभिन्न प्रकार की सेवाओं की आवश्यकताओं के अनुसार उपलब्ध करवायेगा।

घ. उपरोक्त भूमि श्राइन बोर्ड द्वारा समय–समय पर आवश्यकतानुसार प्रयुक्त की जायेगी जिसमें निम्नलिखित कार्य शामिल हैं :–

- अस्थायी बने–बनाये ढांचे व शौचालयों की सुविधाओं का निर्माण।
- निजी संस्थाओं द्वारा टैंटों में रहने की सुविधा की व्यवस्था (स्थानीय, स्थाई निवासी राज्य के)
- दुकानदारों द्वारा दुकानों की व्यवस्था (स्थानीय, स्थायी निवासी राज्य के)
- पिट्ठू व पौनी की सुविधा
- स्वास्थ्य व चिकित्सा की सुविधाओं का प्रावधान।
- निजी व्यक्तियों व संस्थाओं द्वारा बोर्ड से लाईसेंस प्राप्त कर मुफ्त लंगरों की व्यवस्था।
- हैलीकाप्टर परिचालन की सुविधा व वाहनों की पार्किंग।
- स्थानीय पुलिस, अर्ध सुरक्षा बल तथा अन्य सुरक्षा एजेंसियों द्वारा इस स्थान पर आने जाने वाले लोगों की सुरक्षा व्यवस्था तथा भूमि संरक्षण, भूमि सुरक्षा, तथा वन्य सुरक्षा के बंदोबस्त करना।

अन्य बिन्दू

♦ यह हमेशा के लिए स्वीकृत है कि यात्रा की समस्त व्यवस्थाओं के लिए दोनों मार्गों पर बोर्ड का दायित्व रहेगा जिसमें सभी व्यवस्थाएं करना शामिल हैं। जिनकी व्याख्या श्रीअमरनाथ जी श्राइन बोर्ड एक्ट 2000

ईस्वी में उल्लेख है।

- इसके अलावा समिति द्वारा गठित कमेटी द्वारा वार्ता के दौरान प्रस्तुत 14 बिन्दुओं का मांग पत्र राज्य सरकार को दिया गया था। जिसमें मुख्य मांगे थी :– अनेक लोगों पर लगे अपराधिक मामलों को वापस लेना, संघर्ष के दौरान प्रभावित परिवारों को क्षतिपूर्ति का प्रावधान तथा उचित आर्थिक सहायता से हानि की क्षतिपूर्ति करना। ट्रांसपोर्ट, व्यपार व उद्योग, हार्टिकल्चर, होटल तथा पर्यटन विभाग को हुये नुकसान की भरपाई करना। राज्य सरकार ने उचित तरीके से निश्चित समय सीमा के आधार पर इन सबकी समीक्षा करने पर सहमति जताई है।
- विशेषतया संघर्ष के दौरान अनेक लोगों पर थोपे गये अपराधिक मामलों से संबंधित सभी जमानती केस वापिस होंगे। बचे हुये केसों की समीक्षा प्रिसिंपल सैकेटरी अनिल गोस्वामी की अध्यक्षता में गठित एक कमेटी करेगी। यह कमेटी केस की योग्यता के आधार पर 60 दिनों में समीक्षा पूरी करेगी। प्रक्रिया के पूरी होने तक इन लोगों पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। इसके साथ ही विशेष प्रकार के आरोपी आंदोलनकारियों के केसों को प्रथम दृष्टया के आधार पर देखा जायेगा
- राज्य सरकार के वर्तमान नियमों के तहत मृतकों के अगले उत्तराधिकारी, सदा के लिए अपंग हुये लोगों और संघर्ष में हुये घायलों को एक्स ग्रेशिया सहायता मिलेगी।
- मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कार्य समूह का गठन होगा जो दोनों संभागों जम्मू व कश्मीर में हुये नुकसान की क्षतिपूर्ति के मुद्दों पर केन्द्रीय सरकार को एप्रोच करेगा। ताकि राज्य सरकार को पर्याप्त आर्थिक सहायता मिले। यह कार्य दो महीनें में सम्पन्न होगा। इस कार्य को अर्थपूर्ण बनाने के लिए प्रत्येक प्रभावित विभाग से एक प्रतिनिधि इस कार्यसमूह में शामिल किया जायेगा।
- श्री अमरनाथ श्राइनबोर्ड का पुनर्गठन एक्ट के प्रावधानों व पिछली व्यवस्थाओं के आधार पर होगा।
- यह स्वीकार किया गया है कि राज्य का कानून विभाग एक महीने में एल पी ए को समाप्त करने की व्यवस्था करेगा।

हस्ताक्षर

लीलाकरण शर्मा	डा. एस.एस. बिलोरिया
संयोजक	सलाहकार
श्रीअमरनाथ यात्रा संघर्ष समिति	राज्यपाल जम्मू–कश्मीर

विजय रैली पर प्रतिबंध

भारत में पिछले 61 वर्षों में हिन्दुओं की हुई इस ऐतिहासिक विजय पर जम्मू समेत सारा देश झूम उठा। समझौते का समाचार रात ही बिजली के करंट की तरह पूरे जम्मू शहर से होता हुआ संभाग के गांव–गांव तक पहुंच गया। दो महीने से संघर्ष कर रहे लोग पहले ही रात भर जागकर इस शुभ समाचार का इंतजार बेताबी से कर रहे थे। समाचार मिलते ही लोग घरों से निकल कर नाचते हुये सड़कों और चौराहों पर एकत्र हो गये। ढोल–नगाड़ों के साथ रंग गुलाल उड़ने लगे। जोरदार आतिशबाजी शुरू हो गई। संघर्ष समिति ने 31 अगस्त को दोपहर 11.00 बजे जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में एक विशाल विजय रैली करने की घोषणा की।

जम्मू के लोग इस रैली में जाने के लिए उतावले होकर तैयारियां करने लगे। विजयी महिलाएं और बच्चे तरह–तरह के नये परिधान पहनकर छोटे–छोटे समूहों में रैली स्थान पर जाने की तैयारियों में जुट गये। संघर्ष समिति के आदेश पर जम्मू के प्रत्येक घर में भोजन पैकट बनाये गये। इस तरह 5 लाख लोगों की उपस्थिति का अनुमान लगाकर विजय रैली की सभी तैयारियां पूरी कर ली गईं।

बुजदिल सरकार की कायराना हरकत

जम्मू के लोगों की यह चिरस्मरणीय विजय भी सरकार को बर्दाश्त नहीं हुई। कहीं कश्मीरी अलगाववादी नाराज न हो जायें, हिन्दुओं की संगठित शक्ति के दर्शन देशद्रोहियों को न हों और रैली में कहीं संघर्ष के दौरान हुये पुलिसिया जुल्मों की निंदा न की जाये, इसलिए प्रशासन ने पूरे जम्मू संभाग को एक बार फिर कर्फ्यू के शिकंजे में जकड़ दिया। नाच– कूद कर जश्न मना रहे विजयी लोगों के पांव में कानून की बेड़िया डाल दी गईं।

एक बार फिर शुरू हो गया लाठीचार्ज, अश्रूगैस, रबड़ की गोलियों और गर्म पानी फेंकने का वीभत्स पुलिसिया कहर। एक दूसरे पर गुलाल अबीर फेंक रहे लोगों को पुलिस ने दौड़ा–दौड़ा कर पीटा। प्रशासन ने संघर्ष समिति की रैली को सम्पन्न करने की अपील को ठुकरा दिया। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना था कि जम्मू संभाग में हाल ही में हुई पाकिस्तान घुसपैठ के बाद आतंकवादी शहरों और कस्बों में मौजूद हो सकते हैं। खूफिया सूत्रों के अनुसार शहर में घुसे पाकिस्तानी घुसपैठिये रैली पर हमला भी कर सकते हैं।

बुजदिल सरकार का यह कायराना तर्क लोगों के जोश को ठण्डा नहीं कर सका। लोगों की जुबान पर यही था कि जो सरकार दो आतंकियों को संभाल कर विजय रैली को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती,

वह देश और समाज की क्या रक्षा करेगी? दरअसल सच्चाई यह थी कि यह विजय रैली सरकार की पराजय रैली बन रही थी और देशद्रोहियों के लिए एक प्रबल चुनौती थी। सरकार ने इसीलिए जम्मू संभाग के देशभक्त लोगों को गली और मोहल्लों में कांटेदार तार से बांध दिया। पुलिस और सेना के बल पर सरकार इस विजय रैली को विफल करने में सफल तो हो गई परन्तु लोगों के सब्र का बांध टूट गया।

हर प्रकार के जुल्म सहकर 10 हजार लोग रैली स्थल पर पहुंच गये। रैली स्थल को 5 हजार से ज्यादा पुलिस और सेना के जवानों ने घेर रखा था। लाठियों, गर्म पानी की बौछारों और अश्रूगैस के गोलों का जमकर इस्तेमाल करते हुये लोगों को वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया गया। इतनी सख्ती के बावजूद भी जम्मू क्षेत्र के लोग अपने गली, मोहल्लों, चौराहों और खेत–खलिहानों में नाच–नाच कर जश्न मनाते रहे। इस अभूतपूर्व विजय की खुशी में देश भर में विजय जुलूस निकाले गए, आतिशबाजी की गई। लोगों ने घर–घर में दीपक जलाए।

शहीदों का अपमान

दुख की बात है कि अलगाववादियों को सिर पर चढ़ाने वाली सरकार को जम्मू के देशभक्त लोगों की विजय बर्दाश्त नहीं हो रही। 20 सितम्बर को शहीदों को श्रद्धांजलि एवं उनके परिवारों को दी जाने वाली आर्थिक मदद से संबंधित कार्यक्रम को प्रशासन ने फिर बल प्रयोग से सम्पन्न नहीं होने दिया। जम्मू के अभिनव थियेटर में होने वाले कार्यक्रम की इजाजत ली गई थी। बाकायदा संस्कार भारती के नाम से स्थान की बुकिंग हुई थी। लगभग 10.30 बजे हजारों लोग एकत्रित होना शुरू हुए। प्रशासन ने सारे कायदे कानून ताक पर रखकर इस कार्यक्रम को विफल करने की ठान ली। पहले स्थान की बुकिंग निरस्त की गई और बाद में पुलिस को निहत्थे लोगों पर जुल्म करने की खुली छूट दे दी गई। हजारों पुलिस कर्मियों ने अभिनव थियेटर को घेर लिया। बिना किसी चेतावनी के लाठियों और गोलियों की बौछार शुरू कर दी। सैंकड़ों लोग जख्मी हो गये। 100 से ज्यादा गिरफ्तार कर लिये गए।

इस तरह से पहले शहीदों के शवों का अपमान करने वाली सरकार ने अब इनकी शहादत और इनके परिवारजनों का अपमान किया। सरकार की इस तानाशाही के खिलाफ जम्मू क्षेत्र फिर दो दिन तक बंद रहा। सरकार जम्मूवासियों से बदला लेने के लिए तरह–तरह के अत्याचार करने से बाज नहीं आ रही। संघर्ष समिति ने घोषणा की है कि आंदोलन स्थगित हुआ है समाप्त नहीं हुआ।

निस्वार्थभाव से आंदोलन में जुटे हजारों कार्यकर्त्ता

श्री अमरनाथ यात्रा संघर्ष समिति का गठन होते ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी पूरी शक्ति संघर्ष को सफल बनाने में झोंक दी। विश्व हिन्दू परिषद समेत संघ परिवार के सभी संगठन इस राष्ट्रीय आंदोलन में पूरी शक्ति के साथ सक्रिय हो गये। इन राष्ट्रभक्त, निष्ठावान, ईमानदार और राजनीति से पूर्णतः अलिप्त जन नेताओं और कार्यकर्त्ताओं के सक्रिय होने से न केवल संघर्ष समिति को बल मिला बल्कि जम्मू क्षेत्र के विविध धार्मिक एवं सामाजिक संगठन भी संघर्ष समिति के साथ जुड़ गये।

29 जून को जम्मू के गीता भवन में सम्पन्न हुये संघर्ष समिति के पहले सम्मेलन में संघ परिवार के सभी संगठनों के अतिरिक्त अन्य 32 हिन्दू संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुये। इस लघु सम्मेलन में संघर्ष समिति के संयोजक श्री लीला करण शर्मा, विश्व हिन्दू परिषद के प्रधान डा. रमाकांत दुबे तथा राधाकृष्ण मंदिर के मुख्य मंहत स्वामी दिनेश भारती भी उपस्थित थे। इस सम्मेलन में ही जम्मू संभाग के प्रत्येक जिले, तालुका और ग्राम स्थल तक संघर्ष समितियों के गठन का निश्चय किया गया।

गांव स्तर तक संघर्ष समितियां गठित

श्री अमरनाथ यात्रा संघर्ष समिति के नेताओं व कार्यकर्त्ताओं ने ग्राम स्तर तक प्रवास करने शुरू किये। एक सप्ताह के भीतर लगभग 1300 संघर्ष समितियों का गठन हो गया। शहरों, कस्बों और गांवों में सक्रिय सभी पंथों और वर्गों के नेताओं ने सहर्ष जमीन की जंग में शामिल होने, आंदोलन के सूत्र संभालने और लोगों को संघर्ष में सहयोग के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी उठा ली।

गांव स्तर तक समितियों का गठन करने के बाद प्रांतीय संघर्ष समिति द्वारा एक कोरग्रुप की स्थापना की गई। इस कोर ग्रुप में समिति के संयोजक श्री लीलाकरण शर्मा समेत 35 लोग शमिल थे। जम्मू के गीता भवन में प्रांतीय संघर्ष समिति का कार्यालय बनाया गया। इस स्थान पर संघर्ष समिति की नियमित बैठक और प्रेस कांफेंस शुरू हो गई। इसी तरह प्रांतीय संघर्ष समिति द्वारा गठित

कोर ग्रुप की बैठक किसी विशेष स्थान पर रोज रात्रि को होती थी। इस बैठक में आंदोलन की नियमित जानकारी के अलावा अगले दिन की रणनीति पर विचार होता था। कोर ग्रुप की बैठक में लिये गये निर्णयों की चर्चा अगले दिन प्रातः प्रांतीय संघर्ष समिति की बैठक में होती थी। प्रांतीय संघर्ष समिति के निर्णय को रोज जिला, तालुका और गांव स्तर की समिति तक पहुंचाने के लिए पूरे जम्मू संभाग में सैंकड़ों कार्यकर्त्ताओं की एक टीम तैयार की गई। इस टीम में संघ के स्वयंसेवकों के अलावा विभिन्न हिन्दू संगठनों के कार्यकर्त्ताओं को शामिल किया गया। गांव स्तर की संघर्ष समितियों तक सूचनाएं भिजवाने, आंदोलन के कार्यक्रमों की रूपरेखा देने और प्रत्येक स्थान में हुये आंदोलन की रिपोर्ट लेने में इन युवा कार्यकर्ताओं ने दिन रात एक कर दिया।

गीता भवन में स्थापित प्रांतीय संघर्ष समिति के कार्यालय के साथ ही काम कर रहे त्रिकुटा संवाद केन्द्र की सेवाओं को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। इस संवाद केन्द्र ने प्रातः 9 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक काम करके इस जनांदोलन में अपना योगदान दिया। अमरनाथ संघर्ष समिति की प्रेस विज्ञप्तियों को तैयार करना, विभिन्न समाचार पत्रों को आंदोलन के कार्यक्रमों की रिपोर्ट भेजना, देश भर के सभी संवाद केन्द्रों पर संघर्ष की भूमिका और प्रगति से संबंधित समाचार और लेख भेजना, आंदोलन से संबंधित विभिन्न समाचार पत्रों में छपी खबरों का संकलन करना, ब्लाग एवं वेबसाईट बनाना और संघर्ष समिति के नेताओं और कार्यकर्त्ताओं को वैचारिक सामग्री उपलब्ध करवाना जैसे कार्यों को त्रिकुटा संवाद केन्द्र ने सफलता पूर्वक सम्पन्न किया है। इस संवाद केन्द्र ने एक पुस्तिका ''आस्था पर आघात'' की सीडी बनाकर समस्त देश के प्रमुख प्रकाशन केन्द्रों पर भेजी। इस तरह इस पुस्तक को कई स्थानों पर लाखों की संख्या में छपवाकर समाज के अग्रणी लोगों के हाथों में पहुंचाया गया। इस पुस्तक में छपी संघर्ष की भूमिका, कार्य और उद्देश्य की जानकारी ने अमरनाथ संघर्ष समिति के कार्य को आसान कर दिया।

लोग जुड़ते गये काफिला बनता गया

24 घण्टे सक्रिय रहने वाली इस व्यवस्था में धीरे-धीरे लोग भारी संख्या में अपने आप जुड़ते गये और आंदोलन जोर पकड़ता

गया। जैसे जैसे आंदोलन का विस्तार होता गया संघर्ष समितियों की जिम्मेदारियां भी बढ़ती चली गई। पूरे जम्मू क्षेत्र में हिन्दू युवकों की ऐसी टोलियां खड़ी हो गई जिन्होंने संघर्ष समिति के प्रत्येक निर्देश का पालन करते हुये इस जनांदोलन को सफलता की ओर बढ़ा दिया।

यह सत्य है कि इस जनांदोलन में लोगों ने स्वयं स्फूर्ति से बम–बम भोले और हिन्दुत्व के नाम पर भाग लिया। लाखों पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने अपने आप जेल भरो इत्यादि कार्यक्रमों में भाग लेकर इस आंदोलन को सफल बनाया। सार्वजनिक लंगरों के लिए धन दिया, स्वयं ही अपने घरों में तिरंगे झण्डे बनाये और इन्हें हाथों में लेकर विभिन्न प्रदर्शनों में कूद पड़े। परन्तु इस तरह का देशभक्तिपूर्ण वातावरण बनाने और जनता का हौसला बनाये रखने के पीछे जिस संगठित हिन्दू शक्ति का आधार था उसको आंखों से ओझल नहीं किया जा सकता।

दो महीनों तक लगातार चलने वाले इस जनआंदोलन से संबंधित अनेक प्रकार की व्यवस्थाओं को संभालते हुये जिन कार्यकर्ताओं ने अपना तन–मन–धन झोंक दिया वे सभी कार्यकर्त्ता पद यश गरिमा से दूर रहने वाले हैं। इन कार्यकर्त्ताओं की अथक मेहनत के कारण निरंतर चले जनांदोलन की क्रमिक श्रंखला तय हो सकी। धरनों, प्रदर्शनों, बंद, संघर्ष यात्राओं, प्रभात फेरियों, जेल भरो आंदोलन के समय पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के अलग–अलग कार्यक्रमों की निश्चित तिथियों तथा इसी प्रकार के अन्य जलसे जलूसों के कार्यक्रम सफल हो सके। कहां गिरफ्तारियां देनी हैं, लंगरों की व्यवस्था कैसे और कहां करनी है, जेल पहुंचे आंदोलकारियों पर चले मुकदमों को कैसे लड़ना है, उनकी जमानतों की व्यवस्था और केस लड़ने के लिए वकीलों का सहयोग इत्यादि सब इंतजाम हजारों संघ कार्यकर्ताओं की इसी श्रंखला ने किये थे। इन कार्यकर्त्ताओं ने यह सब कार्य निस्वार्थ भाव से सम्पन्न किये।

किसी भी आंदोलन को सफल करने के लिए प्रशासन और पुलिस की रणनीति की पूर्व जानकारी प्राप्त करने और तदानुसार अपनी रणनीति को व्यवहार में लाने का काम महत्वपूर्ण होता है। संघर्ष समिति के नेताओं और दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में संघर्ष की बागडोर संभाले कार्यकर्त्ताओं ने गुप्त रूप से इस कार्य को भी सफलता पूर्वक सिरे चढ़ाया। समिति के आदेश पर अनेक कार्यकर्त्ताओं

ने भूमिगत रहकर पुलिस और सेना की गतिविधियों की पूर्व जानकारी प्राप्त की। हालांकि इस महत्वपूर्ण कार्य की विस्तृत जानकारी देना इस पुस्तक का उद्देश्य नहीं है तो भी इतना तो समझा ही जा सकता है कि कार्यकर्त्ताओं ने किस तरह छिपते-छिपाते इस अति महत्वपूर्ण काम को सफलता पूर्वक अंजाम दिया होगा।

पीड़ितों के जख्मों पर मरहम

आंदोलन की सफलता के बाद अब यही कार्यकर्त्ता लोगों के बीच जाकर उनके हौंसले को बरकरार रखने का काम कर रहे हैं। आंदोलन के दौरान शहीद हुये युवकों के परिवारों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। पुलिस के अत्याचारों से पीड़ित लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए कार्यकर्त्ताओं की यह श्रंखला घर-घर पहुंच रही है। व्यापारियों, सरकारी और गैरसरकारी कर्मचारियों को हुये आर्थिक नुकसान की भरपाई तो संघर्ष समिति के यह कार्यकर्त्ता नहीं कर सकते परन्तु स्नेह पूर्वक उनका सम्मान करने के लिए यह कार्यकर्ता घर-घर जाकर संपर्क कर रहे हैं।

संघर्ष समिति के संयोजक श्री लीला करण शर्मा समेत सभी संगठनों के प्रतिनिधि नेता स्थान-स्थान पर जाकर लोगों को हुये अनेक कष्टों की जानकारियां ले रहे हैं और आंदोलन की सारी सफलता का श्रेय आम नागरिकों को दे रहे हैं।

गैर राजनीतिक धरातल पर लड़ी गई इस जंग की सफलता में से निकले इस निष्कर्ष को सार्वजनिक किया जा रहा है कि यदि समस्त हिन्दू समाज संगठित और शक्तिशाली होकर अपनी संस्कृति और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए तैयार हो जाये तो सफलता चरण चूमेगी, विरोधी परास्त होंगे और राजसत्ता भी संगठित धर्म सत्ता के आगे झुकेगी।

अब तो चेंतो!

अनुच्छेद 370 की आड़ में उपजी ''भारत विरोधी कश्मीरियत''

भारत की समस्त देशभक्त जनता और सरकारों को अब यह समझ लेना चाहिए कि कश्मीर में देशद्रोह के पनपने, आजादी का नारा बुलंद होने और कश्मीरी राष्ट्रीयता का शोर मचने के पीछे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 ने भी खासी भूमिका निभाई है। इसी अनुच्छेद ने पिछले 57 वर्षों से कश्मीर में भारत विरोधी तत्वों को आश्रय दे रहा है।

इसी अनुच्छेद की वजह से कश्मीर के युवक देश की मुख्यधारा से कटे हैं, मुस्लिम लीग और हुर्रियत कांफ्रेंस जैसे पाक परस्त संगठनों को मजबूती मिली है। इसी अनुच्छेद के कारण कश्मीर को स्वतंत्र देश घोषित करने वाले हजारों मदरसे खुले हैं। इन इस्लामिक शिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षित हुये कश्मीरी युवकों ने पाकिस्तान की मदद से भारत के विरोध में हथियार उठाये हैं। कश्मीर के राजनीतिक दलों को मुस्लिम वोट बैंक के लिए हिन्दू विरोध की प्रेरणा दी है। अनुच्छेद 370 के कारण ही भारत की सभी सरकारें कश्मीर में पनपते रहे अलगाववाद को मजबूर आखों से देखती रहीं। परिणाम स्वरूप इस्लामिक कट्टरपंथ और पाक प्रेरित अलगाववाद कश्मीरी राष्ट्रवाद का आकार लेने लगा।

भारतीय संविधान के निर्माता डा. भीमराव अम्बेडकर ने प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू को चेतावनी दी थी कि इस अनुच्छेद से जम्मू-कश्मीर को भारत के साथ समरस करने में दिक्कतें खड़ी होंगी। यह अनुच्छेद घाटी के लोगों में अलगाववाद के बीज बोयेगा।

अनुच्छेद 370 की आड़ लेकर कश्मीर घाटी के कट्टरपंथी संगठनों और नेताओं ने सदैव ही भारत की सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय महत्वों के प्रकल्पों और हिन्दू समाज द्वारा सम्पन्न होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों का जातिगत आधार पर विरोध किया है। श्री अमरनाथ यात्रा इसी मानसिकता का शिकार हुई थी। इसी अनुच्छेद की बुनियाद पर इस्लामिक मजहबी जनून को सड़कों पर उतरकर भारत राष्ट्र को चुनौती देने का मौका मिला और कश्मीर में सभी भारतीयों को विदेशी कहा जाने लगा। आज तो अनुच्छेद 370 का औचित्य ही समाप्त हो गया है। अलगाववादी कश्मीरियों के भारत के विरुद्ध खुली बगावत पर उतर आने और भारतीय सेना के साथ छापामार युद्ध करने के बाद इस अनुच्छेद का तो कोई संवैधानिक अर्थ ही समझ नहीं आता।

हिन्दू विहीन कश्मीरियत

अमरनाथ श्राइन बोर्ड की जमीन के राष्ट्रीय मुद्दे ने कश्मीरी नेताओं के जहन में समाई हुई कश्मीरियत की आक्रामक भारत विरोधी मानसिकता पर से पर्दा हटा दिया है। हिन्दू पूर्वजों की संतान इन कश्मीरी नेताओं ने स्वतंत्र कश्मीर राष्ट्र का नारा बुलंद करके एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि इन्हें अपने हिन्दू पूर्वजों की उज्ज्वल, सार्वभौमिक और दिग्विजयी कश्मीरियत से कोई वास्ता नहीं। इन कट्टरपंथी नेताओं को कश्मीर पर आक्रमण करने वाले और इनके ही पूर्वजों की महान संस्कृति को तबाह करके कश्मीर का गौरवशाली चेहरा बिगाड़ने वाले दुर्दांत हमलावरों की विरासत की चिंता है।

ये लोग अपने ही बाप-दादाओं द्वारा बनाये गये मठ-मंदिरों, विश्वविद्यालयों, सांस्कृतिक केन्द्रों और प्रेरणा स्थलों को बर्बाद करने के काम को ही जेहाद और कश्मीरियत मान बैठे हैं। आज जिन कश्मीरी नेताओं को श्रीअमरनाथ यात्रा से कश्मीर में हिन्दू कालोनी बनाने, मुसलमानों का जनसंख्या अनुपात बिगड़ने और भारतीयों के कश्मीर में बस जाने का भय उत्पन्न हो गया है उनसे यह पूछा जाना चाहिए कि 600 वर्ष पहले के हिन्दू कश्मीर को मुस्लिम कालोनी में किसने बदला? कश्मीर की वास्तविक सूरत बिगाड़ने वाले विदेशी हमलावरों को कश्मीर में पांव पसारने और धर्मांतरण की खूनी चक्की चलाने में किसने साथ दिया?

विदेश में उपजी आक्रामक तहजीब

स्वतंत्र कश्मीर राष्ट्र का नारा बुलंद करने वाले यह क्यों भूल जाते हैं कि राष्ट्र एक सांस्कृतिक अवधारणा होती है, राजनीतिक ईकाई नहीं। जिस मजहब अथवा संस्कृति के आधार पर कश्मीरियत को राष्ट्रीयता बताया जा रहा है वह मजहब अथवा संस्कृति कश्मीर की जमीन पर नहीं जन्मी। इस संस्कृति के निर्माताओं में से एक भी कश्मीरी नहीं था। यह संस्कृति विदेशी हमलावरों के साथ आई। इन हमलावरों ने कश्मीर की पांच हजार वर्ष पुरानी संस्कृति, इसके संरक्षकों और अनुयायियों को तहस नहस करके विदेश में उपजी एक तहजीब को थोप दिया।

कितनी अजीब बात है कि इस विदेशी आक्रामक तहजीब का डटकर मुकाबला करने और अपनी कुर्बानिया देकर कश्मीरियत के इस प्राचीन और सनातन स्वरूप को बचाकर रखने वाले कश्मीरी हिन्दुओं को उनकी धरती से विस्थापित होना पड़ा और उधर इन विदेशी हमलावरों

के आगे कायरतापूर्वक घुटने टेक कर कश्मीरियत के असली चेहरे को बिगाड़ने वाले लोग आज कश्मीर के मालिक बनकर कश्मीरी राष्ट्र की दुहाई दे रहे हैं। इन लोगों ने अपने ही पूर्वजों की स्वदेशी कश्मीरियत को तहस–नहस करके विदेश से आये आक्रमणकारियों की तहजीब को कश्मीरियत बना दिया।

जाहिर है कि यह विदेशी तहजीब और मजहब न ही कश्मीरियत और न ही राष्ट्र हो सकती है। ऐसी कश्मीरियत जिसमें कश्मीरी हिन्दुओं का कोई स्थान नहीं, जिसमें कश्मीर की प्राचीन वास्तविक संस्कृति के लिए कोई जगह नहीं और जिसमें कश्मीर के 5 हजार वर्ष पुराने गौरवशाली इतिहास का कोई आधार नहीं, राष्ट्र का रूप नहीं ले सकती। अलगाववादी कश्मीरी नेता जिस मजहबी जनून को राष्ट्र बता रहे हैं वह हिन्दू विहीन कश्मीरियत वास्तव में मुस्लिम राष्ट्र है।

समान पूर्वज समान संस्कृति

कश्मीरी युवकों को समझना चाहिए कि उनकी रगों में हिन्दू पूर्वजों का खून है। शेष देश की भांति कश्मीर के भी हिन्दु और मुसलमानों के समान पूर्वज हैं, समान इतिहास है, समान संस्कृति है और धरती भी समान है। इसलिए हिन्दू और मुसलमानों की राष्ट्रीयता भी एक ही है। मात्र मजहब बदलने से अथवा पूजा के तौर तरीके बदलने से बाप–दादा नहीं बदल जाते तो फिर बाप–दादाओं की संस्कृति और राष्ट्रीयता कैसे बदल सकती है?

अतः भारत की सरकार, राजनैतिक दलों और राष्ट्रवादी जनता को अब जाग जाना चाहिए। श्री अमरनाथ यात्रा संघर्ष समिति द्वारा क़िए गए विजयी जनान्दोलन ने देशद्रोहियों का पर्दाफाश किया है। कश्मीर में पनप चुके भारत विरोधी अलगाववाद को समाप्त करने का एक ही मार्ग शेष है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को हटा कर कश्मीर में उपजे 'कश्मीर राष्ट्र' के बवाल को समाप्त किया जाए।

राष्ट्रभक्त जनता को आह्वान

देशद्रोहियों को हिन्दुत्व की विजय बर्दाश्त नहीं

कोटि–कोटि हिन्दुओं के आस्था स्थल श्री अमरनाथधाम और अमरनाथ यात्रा के अस्तित्व पर आये इस्लामिक खतरे का मुंह तोड़ जबाव देकर विजयी रही हिन्दुओं की संगठित शक्ति से कश्मीरी अलगाववादी और पाकिस्तान बौखला गए हैं। श्री अमरनाथ यात्रा संघर्ष समिति द्वारा देशद्रोहियों के खिलाफ चलाए गये प्रचंड जनांदोलन से पाकिस्तानी एजेंटो की पराजय पाकिस्तान के गले नहीं उतर रही। आजाद कश्मीर, और ''निजामे मुस्तफा'' के झण्डाबरदारों की पीठ थपथपाकर समस्त हिन्दू समाज विशेषतया जम्मू के देशभक्त लोगों को सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान सशस्त्र घुसपैठियों की मदद से कोई बड़ी साजिश कर सकता है।

खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान समेत कश्मीर में व्याप्त सभी भारत विरोधी शक्तियां श्री अमरनाथ धाम के मुद्दे पर हिन्दुओं की विजय को पराजय में बदलने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। उल्लेखनीय है कि जिस दिन से श्रीअमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा जमीन वापसी के लिए संघर्ष शुरू किया गया, पाकिस्तान उसी दिन से कश्मीर में मौजूद अपने एजेंटो और भारत विरोधी तत्वों की मदद पर उतर आया था। कश्मीर में उफान पर पहुंचे ''स्वतंत्र कश्मीर राष्ट्र'' की मुहिम को कूटनैतिक और नैतिक मदद के ऐलान तेज हो गये।

जम्मू में दो मास तक चले राष्ट्रवादी और हिन्दुत्वनिष्ठ जनांदोलन के दौरान पाकिस्तान ने जम्मू–कश्मीर की सीमाओं पर नवम्बर 2003 से लागू संघर्ष विराम को 21 बार तोड़कर भारतीय सैनिक चौकियों पर गोलाबारी की। कश्मीरी अलगाववादियों द्वारा इन्हीं दिनों तेज की गई आजादी की हिंसक जंग से भारतीय सेना का ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान की फौज द्वारा की गई निरंतर फायरिंग से न तो भारत की सेना घबराई और न ही जम्मू के देशभक्त लोग अपने उद्देश्य से पीछे हटे। इसी जनांदोलन के दौरान पाकिस्तानी घुसपैठियों ने जयपुर, बैंगलूर, अहमदाबाद और अब 14 सितम्बर को दिल्ली में बम धमाके करके भारत को चुनौती देते हुये कश्मीर में सक्रिय देशद्रोहियों की पीठ थपथपा दी। जनांदोलन के इन्हीं दो महीनों में पाकिस्तान ने सैकड़ों हथियारबंद घुसपैठियों को जम्मू में धकेलने की कोशिश की।

श्री अमरनाथ यात्रा संघर्ष समिति के जनांदोलन के समय यहां

एक ओर कश्मीर में देशद्रोहियों के मुंह पर पड़ा भारत का मुखौटा उतरा है वहीं जम्मू क्षेत्र के कई इलाकों में व्याप्त पाकिस्तानी एजेंटों की पोल भी खुली है। यह बात स्पष्ट हो गई है कि जहां मुस्लिम आबादी बहुसंख्या में होगी वहां गैर मुस्लिमों को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। उन्हें सताने, भगाने और पलायन करने पर मजबूर किया जायेगा।

यह प्रसन्नता की बात है कि जम्मू समेत जम्मू संभाग के ऐसे स्थानों पर जहां मुसलमान अल्पसंख्यक हैं उन्होंने इस आंदोलन में हिन्दुओं का साथ देकर अपना राष्ट्रीय कर्तव्य निभाया है। सभी देशभक्त मुसलमान आगे आये और अंत तक इस जनांदोलन का साथ देते रहे। मुसलमान भाइयों की इस मदद की सराहना सारे देश में हो रही है।

परन्तु उधर पुंछ, भद्रवाह, किश्तवाड़ और डोडा क्षेत्रों के बहुसंख्यक मुसलमान भाइयों ने इस आंदोलन का न केवल विरोध ही किया बल्कि हिन्दुओं पर हमले, उनके घरों और दुकानों को जलाना यहां तक कि तिरंगे झण्डे का अपमान करके पाकिस्तानी झण्डे फहराने में कोई शर्म महसूस नहीं की। हिन्दुओं को पलायन करके भाग जाने की धमकियां दी गई। यह अलग बात है कि इस बार हिन्दुओं ने पलायन न करके अपनी संगठित शक्ति का परिचय देकर साहस पूर्वक प्रतिकार किया और अपने घरों में डटे रहे।

जम्मू संभाग के इन मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में कश्मीर के अलगाववादी नेताओं ने हिन्दू विरोध की आग भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पाकिस्तान ने भी इन्हीं दिनों पुंछ में घुसपैठियों को धकेलने के लिए तीन बार गोलाबारी की। 31 अगस्त को जिस दिन सरकार और श्राइन बोर्ड के मध्य समझौता हो रहा था उस रात भी पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर शरारत करने की विफल कोशिश की।

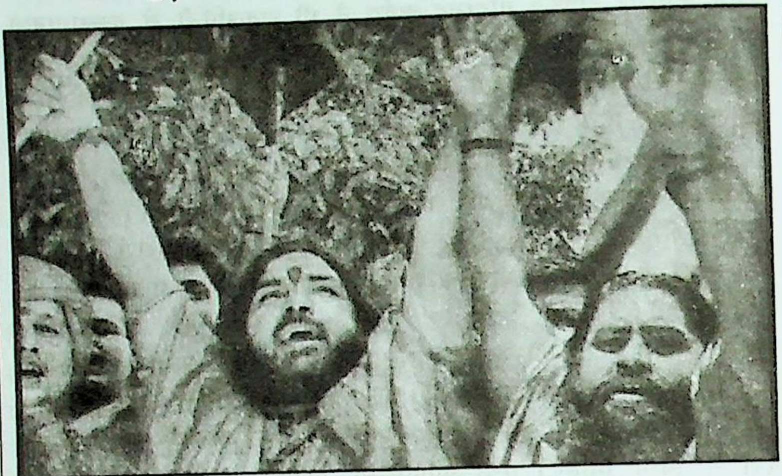
जम्मू–कश्मीर में पाकिस्तानी तत्वों की भारत के राष्ट्रवादियों के आगे हुई पराजय से पाकिस्तान और कश्मीर स्थित आतंकवादी संगठन भी सकते में आ गये हैं। 18 आतंकी संगठनों की सांझी जमात जेहाद कौंसल के सुप्रीम कमाण्डर सईद सल्लाहुद्दीन ने पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में ''डिफेंस ऑफ जम्मू–कश्मीर कांफ्रेंस'' का आयोजन भी श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड को जमीन वापस मिलने के तुरंत बाद किया। इस कांफ्रेंस में बोलते हुये सलाहुद्दीन ने साफ कहा कि अब पाकिस्तान को भारत के साथ सभी संबंध तोड़कर कश्मीर में लड़ी जा रही आजादी की जंग का सीधा समर्थन करना चाहिए।

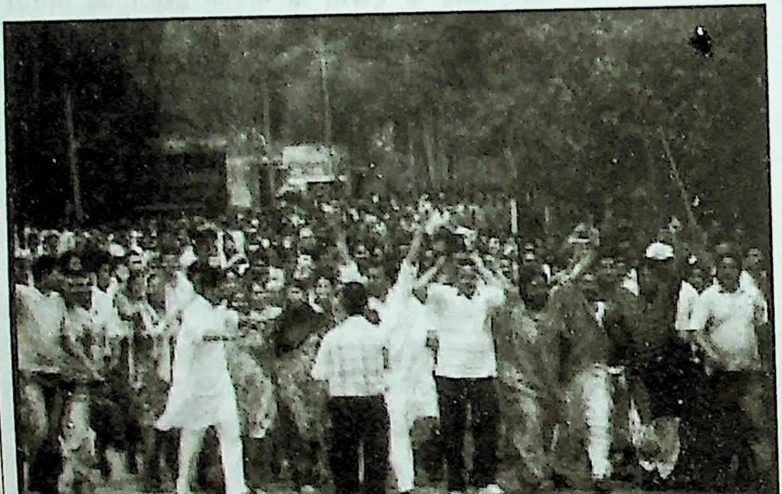
पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर की सरकारों को कश्मीरियों द्वारा शुरू की गई जंगे आजादी की मदद के लिए एक बड़ा आर्थिक बजट बनाना चाहिए। सलाहुद्दीन की इस कांफ्रेंस में 40 से ज्यादा आतंकी संगठनों के नेता मौजूद थे। इसी तरह लश्करे तोयबा के पाकिस्तान स्थित कमांडर हाफिज मोहम्मद सईद ने भी रावलपिंडी से इस्लामाबाद तक एक "कश्मीर सौलीडैरिटी रैली" निकाली जिसमें जम्मू-कश्मीर में हिन्दुओं की जीत पर गहरी चिंता जताते हुये इसे कश्मीरियों के लिए खतरा करार दिया गया।

यह भी सत्य है कि पिछले 61 वर्षों में पहली बार जम्मू-कश्मीर में सक्रिय अलगाववादियों को जिस तरह से राष्ट्रवादी ताकतों ने पछाड़ा है और केन्द्र की सरकार हिन्दुत्व के मुद्दे पर झुकी है, इससे देशद्रोही तत्व पहले से भी कहीं ज्यादा सक्रिय और संगठित होकर भारत राष्ट्र को चुनौती देंगे।

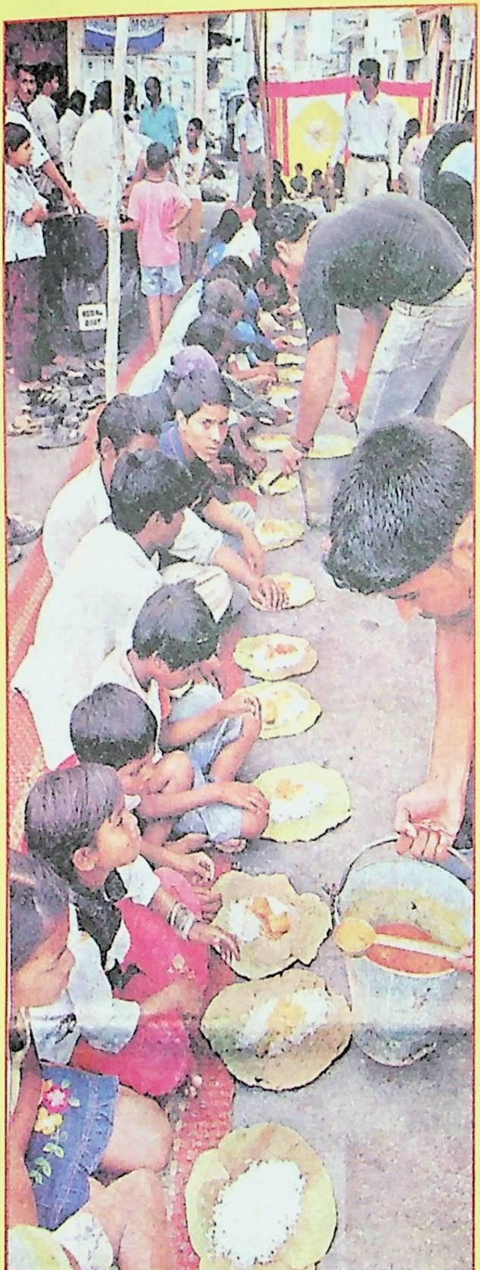
अतः भारत की सरकार, सेना, पुलिस और खासतौर पर जनता को सतर्क रहने की आवश्यकता है। जिस राष्ट्रवादी शक्ति का उदय जम्मू में हुआ है अब उसका प्रगटीकरण कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश में होना चाहिए। तभी पाकिस्तान, कश्मीरी अलगाववादियों और भारत भर में फैले आईएसआई के ऐजेंटों के नापाक इरादों को मिट्टी में मिलाया जा सकेगा।

जम्मू में प्रखर हुआ राष्ट्रवाद

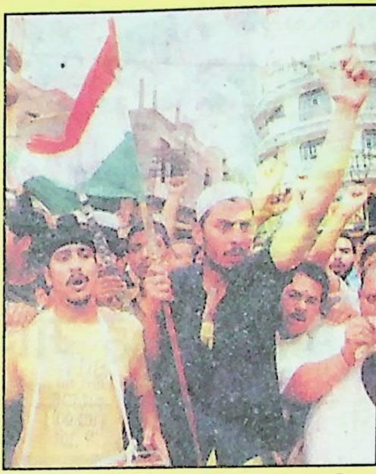




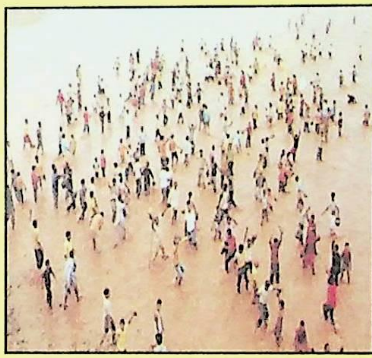
हिन्दु अस्मिता और भारत राष्ट्र पर हुए आघात का पुरजोर उत्तर देने के लिए सभी हिन्दू संगठनों ने बजाया संघर्ष का बिगुल



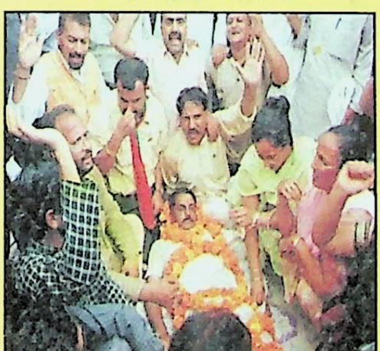
जनान्दोलन के दौरान गरीबों, मज़दूरों और रेहड़ी वालों के लिए शहरवासियों ने लंगर व्यवस्था की ।



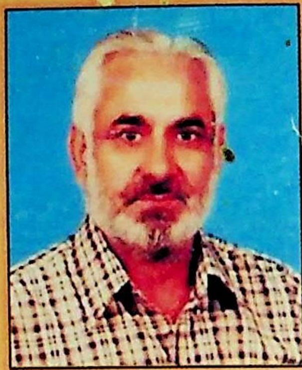
सभी वर्गों पंथों और जातियों के लोगों ने संघर्ष किया ।



तवी नदी को पार करते हुए युवकों के सत्याग्रही जत्थे ।



जनान्दोलन के प्रथम शहीद राष्ट्रवादी कवि कुलदीप डोगरा ।



लेखक परिचय

श्री नरेन्द्र सहगल ने पंजाब विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र एवं इतिहास में एम.ए. किया है। विद्यालय की शिक्षा धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश) और महाविद्यालय की शिक्षा रोहतक (हरियाणा) में पूर्ण की। छात्र जीवन से ही कुशल लेखक एवं प्रभावी वक्ता रहे।

1970–72 में दो वर्षों तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के हरियाणा प्रदेश संगठन मंत्री के नाते कार्य करने के पश्चात् 1982 तक दिल्ली व पंजाब में रा.स्व. संघ में प्रचारक के रूप में कार्य करते रहे। पत्रकारिता में प्रारंभ से ही रूचि थी। 1970–72 में कुरूक्षेत्र से प्रकाशित 'तरूण दीप' मासिक का सम्पादन किया। 1981–83 में चण्डीगढ़ से निकलने वाले 'रवानी' पंजाबी और 'पथिक' हिन्दी मासिक पत्रों के संपादक रहे तथा 1983–89 तक 'तवी दीपिका' जम्मू के सम्पादक व संचालक रहे।

तत्पश्चात् सात वर्षों तक दैनिक भास्कर में जम्मू–कश्मीर के ब्यूरो चीफ के नाते काम किया। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित।

लेखक की अन्य मुख्य पुस्तकें

पंजाब समस्या और उपाय	–	पंजाब साहित्य प्रकाशन, चण्डीगढ़
धर्मांतरित कश्मीर	–	जागृति प्रकाशन, नोएडा (उ.प्र.)
Converted Kashmir	–	**Utpal Publications Shakarpur, Delhi**
घाटी के स्वर	–	उत्पल प्रकाशन, शकरपुर दिल्ली
राम अर्थात् राष्ट्र	–	उत्पल प्रकाशन, शकरपुर दिल्ली
सुरक्षा स्वदेश की	–	पंजाब साहित्य प्रकाशन, चण्डीगढ़
आस्था पर आघात	–	सुरुचि प्रकाशन, दिल्ली